



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 2018/माघ 30, 1939

No. 69]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 2018/MAGHA 30, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2018

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, ईरान और जापान के मूल के बथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 7/14/2017-डीजीएडी.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसकी सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली (जिसे आगे यहां पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. पृष्ठभूमि

1. यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से मेलामाइन के आयातों के सबध में मूल जांच के दिनांक 01 जून, 2012 के अंतिम जांच परिणामों के संबंध में सीमा शुल्क अधिसूचना 08 अक्टूबर, 2012 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 48/2012-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अधिसूचित की गई थी। दिनांक 22 सितंबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 7/14/2017-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई पहली निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) के आधार पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 47/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 07 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

ख. प्रक्रिया

2. नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के तहत संबद्ध सामानों के घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. (जिसे यहां आगे "याचिकाकर्ता" कहा गया है) से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मेलामाइन (जिसे यहां आगे "संबद्ध सामान" कहा गया है) के निरंतर पाठन एवं क्षति का आरोप लगाया गया है। घरेलू उद्योग ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क वापस दिए जाने की स्थिति में पाठन एवं क्षति के खतरे/संभावना के संबंध में भी अनुरोध किया है।

ख. जांच की शुरूआत का औचित्य बताने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के विरुद्ध निर्णायिक समीक्षा जांच शुरू करने का निर्णय लिया।

ग. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के उपय नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने की कार्रवाई से पूर्व आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को सूचित किया।

घ. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच निर्णायिक समीक्षा शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 22 सितंबर, 2017 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ङ. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों, जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, को सार्वजनिक नोटिस की प्रति भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार लिखित में अपने विचार देने का अवसर दिया।

च. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के सभी ज्ञात आयातकों और उद्योग एसोसिएशनों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भेजी और उन्हें सलाह दी कि वे इस पत्र की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचार दें।

छ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को तथा ज्ञात निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जहां अनुरोध किया गया था, को भी आवेदन की प्रति उपलब्ध कराई गई थी।

ज. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी।

डीएसएम मेलामाइन ओसीआई मेलामाइन यूरोप मिजनवेग-1, पीओ बॉक्स नं. 601 6160 एपी गेलीन, नीदरलैंड्स	एग्रोलिंज मेलामाइन इंटरनेशनल जीएमबीएच ए-3021 लिंज, स्टी. पीटर्स स्ट्री-25, ऑस्ट्रिया
निस्सान केमिकल इंडस्ट्रीज लि., 635 सासाकुरा, फुचु माची, टोयामा-9322792, जापान	खोरासन पैट्रोकेमिकल कंपनी, वनक एवेन्यू, पीओ बॉक्स नं. 19395-4583, तेहरान, ईरान
ईरान पैट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन कं., नं. 1339, वलीसर एवेन्यू, वनक स्क्वायर पोस्ट बॉक्स नं. 19697, तेहरान, ईरान	पीटी. डीएसएम कालिटम मेलामाइन कावासन इंडस्ट्री, पीटी पुपुक, कालीमंटन, तिमूर-75313, इंडोनेशिया
पीटी श्री मेलामाइन रेजेकी, प्लाजा अमिटा, नौवां तल, जेआई. लेट. जेंड टी.बी. सिमातुमांग, कव. 10 पोंडोक पिनांग,	

जकार्टा-12310, इंडोनेशिया

झ. जांच की शुरूआत की अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया।

झ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित जात आयातकों/प्रयोक्ताओं/एसोसिएशनों को प्रश्नावली भेजी गई थी:

सेंच्युरी प्लाईबोइर्स (आई) लिमिटेड, 6, लियोन्स रेंज, कोलकाता 700001	ग्रीनप्ले इंडस्ट्रीज लि. ई/176-179, फेज-॥ रीको इंडस्ट्रियल एरिया, पी. ओ. बेहरर-391 701, राजस्थान
मेरिनो इंडस्ट्रीज लि. गांव – अच्छेजा, दिल्ली हापुड रोड, हापुड, उत्तर प्रदेश	मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लि. गांव रोहद, 44 केएमएस स्टोन, दिल्ली रोहतक रोड, हरियाणा
गोल्डन लेमिनेट्स लि. 192-193, इंड. एरिया, पंचकुला, फेज-।, हरियाणा	सूर्या विकास प्लाईवुड प्रा. लि. गांव – दामला, दिल्ली रोड, यमुना नगर
कात्यानी केमटेक इंडिया लि., गांव भगवानपुर, डेराबस्सी – बरवाला रोड, डेराबस्सी	रूसिल डेकोर लि. 1 किंकल अपार्टमेंट, महालक्ष्मी सोसायटी, पालदी, अहमदाबाद, गुजरात
संडेक इंडिया लि. 1421 राजपुर, कलोल मेहासा हाईवे, कादी, नार्थ गुजरात	ब्लूम डेकोर लि. धनलक्ष्मी चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात
एचईएफ इंडिया प्राइवेट लि. न्यू नं. (ओल्ड नं. 2), थर्ड क्लास स्ट्रीट सी.आई.टी. कॉलोनी, माईलेम्पोर, चेन्नई	मंगलम टिंबर प्रोडक्ट्स लि. विरला बिलिंग, सातवां तल, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता
विरगो इंडस्ट्रीज गांव: रामपुर, जतन, नाहन रोड, हिमाचल प्रदेश	एल्फा ईका लि. 2014, उमा इंडस्ट्रियल एस्टेट, सानंद, अहमदाबाद, गुजरात
द बॉम्बे बुरमाह ट्रेडिंग कं. प्लाट नं. 23 से 26, 46 से 48 सेक्टर 5, ॥ ई पंत नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, रुद्रपुर (उत्तरांचल)	

ट. संबद्ध सामानों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली के उत्तर के रूप में उत्तर दिया है अथवा जांच की शुरूआत के संबंध में टिप्पणियां दीं:

- (i) मैसर्स एक्जिम कॉर्प इंडिया प्रा. लि.
- (ii) मैसर्स सेंच्युरी प्लाईबोइर्स (आई) लि.
- (iii) मैसर्स विरगो इंडस्ट्रीज
- (iv) मैसर्स अग्रवाल केमिकल्स
- (v) मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया। इस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण उन विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने किया जिन्होंने सार्वजनिक फाइल से दस्तावेजों की प्रतियों के लिए अनुरोध किया था जो उन्हें उपलब्ध कराई गई थीं।

ड. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे की पर्यासता के संबंध में की गई। प्राधिकारी ने, जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्यास अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें जिसे सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

३. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से, जहां तक आवश्यक समझा गया, सूचना मांगी गई थी। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, जहां तक आवश्यक समझा गया, घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया।

४. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे यहां "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसे निर्मित करने तथा उसकी विक्री करने की लागत पर विचार करते हुए क्षति की सीमा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।

५. जांच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 (12 माह) (जिसे यहां आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है) के लिए की गई थी। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2013-14, 2014-15, 2015-16 और जांच की अवधि है।

६. चूंकि, जांच एक निर्णायिक समीक्षा है, अतः जांच की अवधि के बाद की अवधि (01.04.2017 से 30.09.2017) के आंकड़ों की भी पाठन/क्षति के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए जांच की गई है।

७. पाठनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 02 जनवरी, 2018 को आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी प्रदान किए। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे लिखित रूप में अपने अनुरोध दायर करें और प्रत्युत्तर भी दें तथा उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

८. प्राधिकारी ने 05.02.2018 को नियम 16 के तहत एक प्रकटन विवरण जारी किया और 12 फरवरी, 2018 तक प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां देने के लिए अवसर प्रदान किया।

९. अमेरिकी डॉलर से रुपए में परिवर्तन के लिए जांच की अवधि के लिए विनिमय दर सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार 67.95 रूपये है।

१०. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार से विचार किये जाने का द्योतक है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

३. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है। मूल मामले में 01 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 14/35/2010-डीजीएडी द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एक स्वादहीन, गंधहीन और विषहीन पदार्थ है। मेलामाइन फार्मेलिड्हाइड रेसिन का प्रयोग लेमिनेशन के लिए किया जाता है क्योंकि यह अच्छी समताई, खरांच प्रतिबंधात्मकता, कठोरता, पानी एवं ताप देता है। कुछ विवृत अनुप्रयोगों में प्रयुक्त लेमिनेट में उच्च यांत्रिक शक्ति अच्छी ताप प्रतिरोधकता और अच्छी विवृत इंसुलेशन गुणधर्म होते हैं। एसवेस्टसपूर्ण मेलामाइन रेसिन में अत्यधिक डाइइलैक्ट्रिक शक्ति और उच्च प्रतिरोधात्मकता होती है। सर्वोत्तम आयामी स्थिरता के अतिरिक्त मेलामाइन फार्मेलिड्हाइड मोल्डिंग पाउडर साफ और चमकीले रंग देता है, आसानी से मोल्ड किया जा सकता है तथा सतह पर खरांच को रोकता है। मेलामाइन की फार्मेलिड्हाइड के साथ अनुक्रिया की जाती है और सौंदर्य तथा उपयोगिता के असंबंध उत्पादों को बनाने के लिए रेसिन अथवा मोल्डिंग पाउडर बनाया जाता है। मेलामाइन का प्रयोग मेलामाइन फार्मेलिड्हाइड बनाने के लिए किया जाता है जिसका प्रयोग नीचे के उत्पादों का उत्पादन करने में किया जाता है।

मेलामाइन का सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 का अपना सीमा शुल्क उप शीर्ष 29336100 है। यह उत्पाद ओजीएल श्रेणी में आता है और इसे मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन है। याचिका में प्रस्तुत किए गए अनुसार वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में रहा है जो कि मेलामाइन है। संबद्ध देशों से उत्पादित एवं निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में और घरेलू उत्पादक/जीएसएफसी द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देशों से आयातित सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। ग्राहक दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर रहे हैं।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में मुद्दे उठाए हैं:

(क) मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- यहां तक कि एसजीएस भारत में विचाराधीन उत्पाद का परीक्षण नहीं कर सकता।
- विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए विभिन्न कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
- विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेड हैं।
- विचाराधीन उत्पाद की भिन्न-भिन्न पैकिंग के लिए भिन्न-भिन्न कीमत हैं।
- विभिन्न ग्रेडों की भिन्न-भिन्न कीमत और प्रयोग/अनुप्रयोग हैं।
- ग्रेडों में अंतर के कारण गुणवत्ता और प्रयोग में अंतर है।

(ख) मैसर्स एक्सिम कॉर्प ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:

- मेलामाइन के विभिन्न ग्रेड हैं। आयात शीर्ष गुणवत्ता के ग्रेड के होते हैं जबकि घरेलू उद्योग के ग्रेड अलग-अलग गुणवत्ताओं के हैं और निवल विक्री वसूली घरेलू कीमतों की सही एवं उचित स्थिति नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि, वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा के लिए है, अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है, जो मूल जांच का क्षेत्र है। विचाराधीन उत्पाद मेलामाइन उप शीर्ष 29336100 के तहत अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान है:

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समतुरुप नहीं हैं परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं,

8. दायर आवेदन पत्र समीक्षा के लिए तथा लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा जारी रखने के लिए है और समान वस्तु के मुद्रे को पूर्व जांच में पहले ही ले लिया गया है। पूर्व जांचों में प्राधिकारी ने पहले ही माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।

9. जहां तक विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों का तर्क है, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के संबंध में सहयोग नहीं किया है अथवा कोई सूचना नहीं दी है। कुछ आयातकों ने विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न ग्रेडों के संबंध में चिंताएं उठाई हैं जिनको बाद के पैराग्राफों में उचित रूप से लिया गया है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

10. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) घरेलू उद्योग को निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

“(घ) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग ने “घरेलू उद्योग” के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- जीएसएफसी संबद्ध सामानों का पूर्ण उत्पादक है और नियम 2 के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।
- कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जीएसएफसी ने कतर से संबद्ध सामानों का आयात किया जो कि एक गैर संबद्ध देश है और उसे घरेलू उद्योग के रूप में जीएसएफसी की योग्यता वाला होना चाहिए। विनम्र अनुरोध है कि इन निर्मित मुद्रों का कोई कानूनी आधार नहीं है।
- पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) से यह बहुत स्पष्ट है कि आयातों के संदर्भ में दिया गया संदर्भ पाटित वस्तुओं का आयात है न कि गैर पाटित स्रोत से आयात का। दूसरे शब्दों में, स्वयं आयातक होने के लिए कंपनी संबद्ध देशों से आयात कर सकती थी और गैर संबद्ध देश से आयात, आयातों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते, जैसा कि नियम 2(घ) में प्रावधान है। उपर्युक्त के होते हुए, यदि तर्क यह है कि प्रयुक्त शब्द “उसका आयात” है और इसमें अन्य आयात भी शामिल हो सकते हैं, तो यह गलत पढ़ा जा रहा है और नियम का गलत निर्वचन है। इस उपबंध को उसकी समग्रता में पढ़ा जाना चाहिए और निर्यातों और आयातों के संबंध में मामले में लागू पाटित वस्तु उसके लिए संगत है जो आयात के लिए भी है। यदि निर्वचन में कोई संदेह है तो डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार की भाषा पर विश्वास किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि जीएम एक्सपोर्ट के मामले (संक्षेप में) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है और डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार खुद आयातकों की स्थिति निम्नलिखित रूप में परिभाषित करता है:

“अनुच्छेद 4.1(i) जब उत्पादक स निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं अथवा तथाकथित रूप से पाटित उत्पाद के स्वयं आयातक हैं, तो “घरेलू उद्योग” शब्द का निर्वचन शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जाए।”

- करार में तथाकथित पाटित उत्पाद का स्पष्ट उल्लेख है और भारतीय पाटनरोधी अधिनियम तथा नियम घरेलू उद्योग को परिभ्रषित करते समय अलग बात नहीं बना सकते जो कि विरोधी पक्षकारों के तर्क को किसी औचित्य न होने पर रद्द किया जाना चाहिए और यह माना जाना चाहिए कि जीएसएफसी नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है।
- यह एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी द्वारा कतर से किए गए आयात केवल कुछ ग्राहकों की सांग को पूरा करने के लिए हैं और लम्बे समय तक उन ग्राहकों को खोने के लिए नहीं हैं। वह भी जब कंपनी बड़े क्षमता विस्तारों को पूरा करने वाली हो। कंपनी का पूरा ध्यान अपने संयंत्र में उत्पादन पर ही है और आयात एक प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप के रूप में किए गए थे। कंपनी ने ऐसे आयातों से कोई उल्लेखनीय लाभ का लक्ष्य नहीं बनाया और जैसा कि अनुरोध किया गया है, ये आयात कंपनी द्वारा भावी उत्पादन को दीर्घावधि ग्राहकों को देखते हुए बनाए रखने के लिए किए गए थे। जीएसएफसी की साथ वही बनी हुई है, जो एक जिम्मेदार भारतीय उत्पादक की है और इसके द्वारा किए गए निवेश उसकी साथ को रेखांकित करते हैं। यदि कंपनी का ध्यान आयातों पर होता तो उसने ऐसे निवेशों पर विचार नहीं किया होता।

घ.2 आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में मुद्दे उठाए हैं:

(क) मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

- याचिकाकर्ता कतर से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा है।
- वे कौन से कारण हैं जिनसे याचिकाकर्ता विनिर्माण की बजाए व्यापार कर रहा है।

(ख) मैसर्स एकिजम कॉर्प इंडिया प्रा. लि. ने अनुरोध किया है कि जीएसएफसी का पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में कोई आधार नहीं है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा के लिए आवेदन मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. द्वारा दायर किया गया है जो मूल जांच में घरेलू उद्योग है। याचिकाकर्ता कंपनी संबद्ध देश में किसी निर्यातिक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातक से संबंधित (न तो प्रत्यक्ष रूप से और न अप्रत्यक्ष रूप से) नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने जांच के अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि से पूर्व के वर्षों में तथा जांच की अवधि के दौरान कतर से और क्षति की अवधि में काफी मात्रा में संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का कुछ आयात किया। नियम 2(ख) के प्रावधानों में अपेक्षा है कि पाटित वस्तु के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की जांच की है जो केवल संबद्ध देशों तक ऐसी जांच सीमित करे। यद्यपि यह घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता के संबंध में है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा गैर संबद्ध देशों से आयात क्षति एवं कारणात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए जांच का मामला है जिसका प्राधिकारी ने बाद के पैराग्राफों में मूल्यांकन किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि उपर्युक्त के बावजूद कंपनी उत्पादन करने वाली उत्पादक बनी हुई है और यहां तक कि क्षमता बढ़ा रही है तथा इसीलिए घरेलू उद्योग नियम 2(ख) के अभिप्राय से स्तर बनाए रखने के लिए योग्य है तथा यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार का मानदंड पूरा करती है।

उ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का मूल्यांकन

उ.1 आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में आयातकों, संबद्ध देशों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(क) मैसर्स अग्रवाल केमिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेड रेमिडीज एंड प्रैक्टिसेस

- निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समायोजन साक्ष्य संबंधी नहीं हैं और उन पर विचार नहीं किया जा सकता।

- यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में निर्धारित एमआईपी सामान्य मूल्य के रूप में नहीं मानी जा सकती, परंतु जांच परिणाम के अनुसार 2015-16 में यूरोपीय संघ की उत्पादन लागत पर आधारित हो सकती है और उसे 2016-17 में यूरिया कीमत के साथ आगे समायोजित किया जा सकता है तथा 5 प्रतिशत लाभ जोड़ा जा सकता है जिसका अभिप्राय पाटन नहीं होगा।

(ख) मैसर्स संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

- ओसीआई नाइट्रोजन बी. वी., पी. ओ. बॉक्स 601, 6160 एपी गेलीन, द नीदरलैंड्स, यूरोपीय संघ में विनिर्माता है। यूरोप में दो और विनिर्माता हैं।
- यूरोप से मेलामाइन का निर्यात बहुत कम है।

(ग) मैसर्स सेंच्युरी प्लाईबोड्स प्रा. लि.

- निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्यातकों के प्रकाशित लेखों के आधार पर सामान्य मूल्य का मूल्यांकन करना चाहिए था अथवा बाजार पूछताछ करनी चाहिए थी अथवा तीसरे देशों को निर्यात कीमतों की जांच करनी चाहिए थी।
- यदि निर्यातक देशों में सामान्य मूल्य इतना अधिक है तो घरेलू उद्योग को भी उन बाजारों में निर्यात करना चाहिए।

(घ) मैसर्स एक्जिम कॉर्प इंडिया प्रा. लि.

- निर्णयिक समीक्षा की शुरुआत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 146/2017 तथा 147/2017 में निर्णय के आलोक में स्वतः नहीं है। याचिका पाटनरोधी नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती। सामान्य मूल्य का विनिर्माण प्रकट नहीं किया गया है और निर्यात कीमत संबंधी दावों का समायोजन अत्यधिक है। याचिकाकर्ता का सीएनवी संबंधी दावा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था और यह कि जीएसएफसी को संबद्ध देशों में घरेलू कीमतें प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए थे।
- याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत पर अत्यधिक समायोजन का दावा किया है, उदाहरण के लिए समुद्री बीमा 0.5 प्रतिशत के रूप में, जबकि वह 0.125 प्रतिशत होना चाहिए।

उ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. विभिन्न आधारों के सामान्य मूल्य का मूल्यांकन और उसकी भारत में निर्यात कीमत के साथ तुलना इंडोनेशिया को छोड़कर संबद्ध देशों के मामले में सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाता है क्योंकि इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुए थे।

ख. यूरोपीय संघ, जापान और ईरान से निरंतर आयात हुए हैं। फिर भी, यह तर्क दिया जा सकता है कि मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण आयात आवश्यक हो गए हैं, मामले का तथ्य यह है कि ये आयात पाटित दरों पर किए गए थे और संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों का व्यवहार अब भी अपरिवर्तित बना हुआ है और जब पाटन जारी रहा, जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाए तो पाटन बढ़े हुए तरीके से चालू रहें।

उ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु के लिए तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या राज्य क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातिक देश या राज्य क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातिक देश या राज्य क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातिक देश या राज्य क्षेत्र से या किसी उपर्युक्त तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसरण में यथा निर्धारित, प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्दम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कई हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देशों में "सामान्य मूल्य" का मूल्यांकन करने के लिए अन्य गौण स्रोत आंकड़ों का संदर्भ प्रस्तुत किया है। अतः प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग के लिए लागत आंकड़ों के आधार पर परिकलित सीएनवी के अलावा यूरोपीय संघ के जांच परिणामों, आईसीएसएलओआर तथा विश्व व्यापार आंकड़ों का इस प्रयोजन के लिए संदर्भ दिया है।

18. यूरोपीय संघ ने चीन से मेलामाइन के आयात पर इस पाटनरोधी जांच के संबंध में 30 जून, 2017 के अंतिम जांच परिणाम में 2015-16 की अवधि के लिए 1179 यूरो/मी. टन की घरेलू बिक्री कीमत को अपने जांच परिणाम में सूचित किया था। घरेलू उद्योग ने भी 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए यूरोपीय संघ में मौजूद आईसीएसएलओआर की स्थल कीमतें दी हैं। यूरोपीय आयोग के जांच परिणामों में सूचित की गई घरेलू कीमतें 2015-16 में 1179 यूरो/मी. टन की आईसीएसएलओआर की सूचित घरेलू कीमतों से सह संबंध रखती हैं।

19. प्राधिकारी ने डब्ल्यूटीओ द्वारा सूचित 2015-16 और 2016-17 के दौरान भारत एवं अन्य देशों को यूरोपीय संघ से मेलामाइन की विश्व कीमतों पर भी विचार किया है। वर्ष 2015-16 के लिए यूरोपीय संघ के जांच परिणामों में सूचित घरेलू बिक्री कीमतों को 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान यूरोपीय संघ से विश्व में मेलामाइन के वैश्विक निर्यातों के औसत कीमत अंतर का समायोजन करते हुए 2016-17 के लिए समुचित रूप से समायोजित किया गया है।

20. अतः प्राधिकारी मानते हैं कि निर्णायिक समीक्षा जांच में मौजूदा पाटनरोधी शुल्क बंद करने की स्थिति में संबद्ध देश के वैश्विक निर्यात में व्यापार को ले जाने के लिए जांच की अवधि में तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध देशों की कीमतों की जांच किए जाने की आवश्यकता है और इसीलिए इन संबद्ध देशों की तीसरे देश की कीमतों संबंधी विश्व व्यापार मानचित्र आंकड़ों पर घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर परिकलित सीएनवी के साथ सामान्य मूल्य निर्मित किए जाने के लिए विचार किया गया है। घरेलू उद्योग के आंकड़ों के संबंध में सीएनवी तथा विश्व व्यापार मानचित्र आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देशों की तीसरे देश की निर्यात कीमतों, दोनों के संबंध में संदर्भ दिया गया है और उस पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

यूरोपीय संघ की निर्यात कीमत

21. प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत और पहुँच कीमत का मूल्यांकन करने के लिए, जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए डीजीसीआईएस के आंकड़ों को अपनाया है। जांच की अवधि के लिए भारित औसत सीआईएफ 1.216 डॉलर/किलोग्राम मूल्यांकित किया गया है। सीआईएफ कीमत पर समायोजन समुद्री भाड़े पर 0.1 डॉलर/किलोग्राम तथा समुद्री बीमा पर सीआईएफ का 0.5 प्रतिशत तक सतत परिपाटी/मानदंडों के अनुसार अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्रेशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत एफओबी पर क्रमशः 0.5 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत के समायोजन की अनुमति दी गई है। एक्स-ईपी 1.071 डॉलर/किलोग्राम के रूप में मूल्यांकित किया गया है।

ईरान की निर्यात कीमत

22. प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत और पहुँच मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए डीजीसीआईएस के आंकड़ों को अपनाया है। जांच की अवधि के लिए भारित औसत सीआईएफ 1.353 डॉलर/किलोग्राम

मूल्यांकित किया गया है। सीआईएफ कीमत पर समायोजन समुद्री भाड़े पर 0.04 डॉलर/किलोग्राम तथा समुद्री बीमा पर सीआईएफ का 0.5 प्रतिशत तक सतत परिपाटी/मानदंडों के अनुसार अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत एफओबी पर क्रमशः 0.5 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत के समायोजन की अनुमति दी गई है। एक्स-ईपी 1.260 डॉलर/किलोग्राम के रूप में मूल्यांकित किया गया है।

जापान की निर्यात कीमत

23. प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत और पहुँच मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए जांच की अवधि और क्षति की अवधि के लिए डीजीसीआईएस के आंकड़ों को अपनाया है। जांच की अवधि के लिए भारित औसत सीआईएफ 1.199 डॉलर/किलोग्राम मूल्यांकित किया गया है। सीआईएफ कीमत पर समायोजन समुद्री भाड़े पर 0.05 डॉलर/किलोग्राम तथा समुद्री बीमा पर सीआईएफ का 0.5 प्रतिशत तक सतत परिपाटी/मानदंडों के अनुसार अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार और ऋण लागत एफओबी पर क्रमशः 0.5 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 0.5 प्रतिशत, 1 प्रतिशत के समायोजन की अनुमति दी गई है। एक्स-ईपी 1.102 डॉलर/किलोग्राम के रूप में मूल्यांकित किया गया है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

24. घरेलू उद्योग के उत्पादन लागत के आंकड़ों तथा अन्य समुचित गौण स्रोतों (यूरोपीय संघ के जांच परिणाम, विश्व व्यापार मानचित्र तथा आईसीएसएलओआर) के अनुसार सीएनवी के आधार पर पाटन मार्जिन का परिकलन निम्नलिखित रूप में किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	शूनिट	यूरोपीय संघ	ईरान	जापान
1.	सीएनवी (घरेलू उद्योग के सीओपी आंकड़े)	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***
2.	सीएनवी (गौण स्रोत)	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***
3.	एक्स-ईपी	डॉलर/कि. ग्रा.	1.071	1.260	1.102
4. उपर्युक्त (1) के अनुसार पाटन मार्जिन	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***	***
	% रेंज	5 से 10	माइनस 5 से माइनस 10	0 से 5	
5. उपर्युक्त (2) के अनुसार पाटन मार्जिन	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***	
	% रेंज	20 से 25	माइनस 5 से माइनस 10	0 से माइनस 5	

च. क्षति निर्धारण तथा क्षति की जांच और कारणात्मक संपर्क के लिए सिद्धांत

च.1 आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा दायर किए गए अनुरोध
25. आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(क) मैसर्स सेंच्युरी प्लाइबोइर्स प्रा. लि.

- चूंकि, इंडोनेशिया से आयात शून्य हैं, अतः इंडोनेशिया से पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है।

- जीएसएफसी ने स्वीकार किया है कि यूरोपीय संघ में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है, फिर भी यूरोपीय संघ से क्षति की संभावना का दावा है।
- पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित कीमत के निर्धारण से घरेलू उद्योग को सहायता मिली है।
- जीएसएफसी की उत्पादन लागत 77000 रुपए मी. टन से अधिक नहीं हो सकती और इसीलिए क्षति मार्जिन सकारात्मक नहीं हो सकता।
- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का मामला बनाने के लिए यूरिया का कृत्रिम मूल्य बनाकर तथा बहियों में रिकार्ड किए गए कैपिट्व इनपुट के मूल्य की उपेक्षा करके एनआईपी निर्धारित किया गया।
- यह आश्वर्यजनक है कि यदि प्राकृतिक गैस और विद्युत की कीमत 2013-14 से 2016-17 तक घटी है तो मेलामाइन की लागत 60469 मी. टन से 103796 मी. टन कैसे हो गई।
- डीजीएडी को पाटनरोधी नियमाबली के अनुसार एनआईपी के निर्धारण की जांच करनी चाहिए और चीन से आयातों के मामले में दूसरी निर्णायक समीक्षा के दौरान निर्धारित एनआईपी को भी देखना चाहिए।
- न तो जीएसएफसी द्वारा उत्पादित यूरिया में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया गया और न ही मेलामाइन के उत्पादन में यूरिया का प्रयोग होता है। एनआईपी फर्जी तरीके से निर्धारित किया गया है। एनआईपी के परिकलन के लिए सिद्धांत में विचलन हुआ है।
- घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली कम से कम 15000 रुपए मी. टन होगी जो 74000 रुपए मी. टन के एनआईपी से अधिक है।

(ख) यूरोपीय आयोग

- डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 11.1 के अनुसार, जिसमें यह प्रावधान है कि "पाटनरोधी शुल्क तब तक ही और उस सीमा तक ही लागू रहेगा जो पाटन, जिससे क्षति हो रही है, का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो।" यह स्पष्ट है कि क्षति जारी न रहने की स्थिति में (अथवा जहां पाटित आयातों के कारण क्षति न हो) शुल्क रद्द किया जाना चाहिए।
- आवेदन पत्र में यह दावा किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात निरंतर पाठित हो रहे हैं, फिर भी संगत आंकड़ों, जिन पर शिकायत के अगोपनीय रूपांतर में प्रतिक्रिया की गई थी, के न होने के कारण सामान्य मूल्य के परिकलन को समझना पक्षकारों के लिए असंभव है। तथापि, क्षति के संबंध में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई भी क्षति जारी नहीं है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग स्वस्थ एवं लाभप्रद स्थिति में प्रतीत होता है जहां लगभग सभी आर्थिक मानदंड बहुत ही सकारात्मक और बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाते हैं।
- विशेष रूप से उत्पादन में कमी का कोई संकेत नहीं है, न ही बिक्री की मात्रा में कमी का संकेत है, जो दोनों मानी गई पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहे हैं। बिक्री मूल्य भी कुछ वृद्धि दर्शाता है (100 से 102 का सूचकांक)।
- इसके साथ ही बिक्री लागत कम हुई है और बिक्री कीमत बढ़ी है। परिणामस्वरूप, लाभप्रदता में आकर्षक वृद्धि हुई जो इस अवधि के अंत में तिगुने से अधिक थी (100 से 352 सूचकांक)।
- मजदूरी (+50 प्रतिशत), उत्पादकता और निवेश पर आय के स्तर में भी सकारात्मक एवं बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- जहां तक बाजार हिस्से का संबंध है, यह मानी गई अवधि में 12 प्रतिशत तक कम हुआ है, परंतु बाजार हिस्से में गिरावट को 14 प्रतिशत की मांग में वृद्धि के आलोक में पड़े जाने की आवश्यकता है। लगभग 100 प्रतिशत की क्षमता उपयोग दर से घरेलू उद्यग बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं था जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से आयातों में वृद्धि हुई। फिर भी आयातों में यह वृद्धि संबद्ध देशों से नहीं आई, परंतु अन्य देशों से हुई। उनकी आयात मात्रा 175 प्रतिशत तक बढ़ी और उनका बाजार हिस्सा दोगुने से भी अधिक हुआ।

- चूंकि, घरेलू उद्योग को इस समय वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, अतः उपायों को आगे बढ़ाने की संभावना से ही क्षति होने की संभावना हुई। इस संबंध में और याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर ऐसी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है कि पाटन के कारण हर्ई क्षति भविष्य में होगी। वस्तुतः संबद्ध देशों से आयात की मात्रा मानी गई अवधि में कम (-7 प्रतिशत) हुई है और इसीलिए आयात मात्रा में उनका हिस्सा (-22 प्रतिशत) कम हुआ और मांग में उनका हिस्सा (-18 प्रतिशत) रहा। इसके साथ ही, उनकी आयात कीमतें (+4 प्रतिशत) बढ़ीं और जांच की अवधि के दौरान उनको घरेलू कीमतों में कटौती नहीं हो रही थी। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने में कोई हाथ नहीं है।
- घरेलू उद्योग को क्षति के अभाव के महेनजर तथा क्षति न होने की संभावना को देखते हुए घरेलू उद्योग को होने वाली किसी कठिनाई का कारण (जो उपर्युक्त सकारात्मक प्रवृत्ति का विरोध करते हैं) कोई और हो सकते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि संबद्ध देशों से आयात कम हुए हैं तथापि, जो देश पहले से ही उपायों के अधीन हैं, उनसे और अन्य देशों से आयात बढ़े हैं।
- जहां तक पहले से ही उपायों के अध्यधीन देशों से आयातों का संबंध है, जीएसएफसी का बाजार हिस्सा 36 प्रतिशत है जो संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से और अन्य देशों से बाजार हिस्से के लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त, यह आश्वर्यजनक है कि उपायों के लागू रहने के बावजूद उनकी आयात कीमतें मानी गई अवधि में 28 प्रतिशत तक कम हुई। जांच की अवधि के दौरान वे दोनों संबद्ध देशों (26 प्रतिशत कम) और अन्य देशों (29 प्रतिशत कम) दोनों की कीमतों से काफी कम थीं। इस प्रकार, इस बात की पूरी संभावना प्रतीत होती है कि वे घरेलू कीमतों की काफी कटौती कर रही थीं।
- जहां तक अन्य देशों से आयातों का संबंध है, मात्रा (4614 से 12674 मी. टन) और बाजार हिस्से (दोगुने से अधिक), दोनों में पर्याप्त वृद्धि हुई। परंतु जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि उस स्थिति में जब मांग बढ़ी और घरेलू उद्योग उसे पूरा करने में स्पष्ट रूप से सक्षम नहीं था, तो आयातों ने आपूर्ति का केवल स्रोत दर्शाया तथा आवश्यक रूप से बढ़ गए।
- अतः डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 11.1 के महेनजर यह बात दोहराई जाती है कि "पाटनरोधी शुल्क तब तक ही और उस सीमा तक ही लागू रहेगा जो पाटन, जिससे क्षति हो रही है, का मुकाबला करने के लिए आवश्यक हो।"
- याचिका में यह संकेत है कि घरेलू उद्योग बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सक्षम बनने हेतु अतिरिक्त क्षमता में निवेश कर रहा है। यहां तक कि यदि आर्थिक रूप से यह मांग में वृद्धि की दृष्टि से अपनी क्षमता में निवेश करने के लिए उद्योग के लिए उपर्युक्त हो तो यह निश्चित रूप से घरेलू उद्योग की निवेश योजनाओं का संरक्षण करना पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य नहीं है।
- ऐसी परिस्थितियों में उपायों को आगे बढ़ाना स्पष्ट रूप से डब्ल्यूटीओ के असंगत होगा क्योंकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है और क्षति होने की संभावना नहीं है। इस प्रकार, उपाय अब आगे आवश्यक नहीं हैं।

(ग) मैसर्स अग्रवाल केमिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेड रेमिडीज एंड प्रैक्टिसेस

- याचिकाकर्ता अपने नए निवेश के लिए संरक्षण का दावा नहीं कर सकता क्योंकि पाटनरोधी शुल्क व्यापार के हासमान प्रभाव को समाप्त करने के लिए होता है न कि भावी निवेश का संरक्षण के लिए। चीन जन गण से घोर सिल्क टाइपराइटर रिबन फैब्रिक्स में यूरोपीय आयोग के जांच परिणाम (98/349/ईसी) इस संदर्भ में संगत हैं। इसके बजाए, याचिकाकर्ता की वृद्धि के लिए क्षमता विस्तार को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।
- घरेलू उत्पादक देश की केवल 23 प्रतिशत मांग को पूरा कर सकते हैं तथा यह कि अंतिम प्रयोक्ता मांग को पूरा करने में घरेलू उद्योग की सतत अक्षमता के लिए कीमत चुकाने के लिए मजबूर हैं। वस्तुतः पिछले तीन वर्षों में पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद देश में मांग को पूरा करने के लिए आयात एक स्तर पर स्थिर रहे हैं।
- घरेलू उद्योग कतर से आयात करके भटका रहा है जो आयात की उनके उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत है और इसके साथ ही अन्य देशों के संबंध में पाटनरोधी उपाय की मांग कर रहा है। इस प्रकार, दोनों विश्व के लाभों को ले रहा है।

- क्षति की संभावना, अधिशेष क्षमताओं और इन निर्यातिक देशों की उच्च निर्याति गहनता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।
- विचाराधीन उत्पाद के यूरोपीय संघ में 78 प्रतिशत क्षमता उपयोग के मद्देनजर भारत में यूरोपीय संघ के निर्यातों के विचलन के लिए, भारत में विचलन के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। भारत में निर्यात के लिए कोई कीमत आकर्षकता नहीं है क्योंकि यूरोपीय संघ से निर्यातों की कीमत भारतीय बाजार की कीमतों से अधिक है।
- चूंकि, इंडोनेशिया से कोई निर्यात नहीं है, अतः इंडोनेशिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क वापस ले लिया जाए, जैसा कि एफडीवाई के मामले में था, जहां निर्णायिक समीक्षा जांच वियतनाम के विरुद्ध शुरू नहीं की गई थी जहां से कोई निर्यात नहीं था।
- कीमत कठौती पर संचयी आधार पर विचार किया गया है, न कि अलग-अलग संबद्ध देश-बार।
- घरेलू उद्योग के यह अनुरोध कि यूरोपीय संघ के उत्पादकों के लिए आरओआई 34 प्रतिशत था और यह पाया गया था कि क्षति पुनः हो सकती है, गलत बताए गए हैं क्योंकि यूरोपीय संघ में आरओआई, एनएफए आधार पर परिकलित किया जाता है त कि नियोजित पूँजी पर। इसके अतिरिक्त, निर्णायिक समीक्षा में पाटनरोधी विस्तार संभावना के मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है न कि आरओआई के स्तर पर।

(घ) इंडोनेशिया सरकार

- जैसा कि याचिका में दिया गया है, भारत में घरेलू उद्योग सकारात्मक विकास दर्शते हैं, जहां से संबद्ध सामानों की मांग में 4.5 प्रतिशत का सुधार आया, जबकि उत्पादन थोड़ा से 0.9 प्रतिशत तक बढ़ा और संबद्ध सामानों का कुल आयात 5.9 प्रतिशत तक बढ़ा। यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत को अपनी घरेलू मांग पूरा करने के लिए आयातों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, निवेश पर आय ने भी 57.2 प्रतिशत तक काफी सुधार दर्शाया।
- उपर्युक्त के मद्देनजर, पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जारी रखने की, डब्ल्यूटीओ के पाटनरोधी करार ("एडीए") के अनुच्छेद 3.1 के तहत प्रबल रूप से सलाह नहीं दी जाती है, जिसमें उल्लेख है कि डब्ल्यूटीओ सदस्य अपने पाटनरोधी उपाय लगाए जाने को बढ़ा सकते हैं, यदि "जांच करार के अनुसार की जाती है और निर्धारण किया जाता है कि (क) पाटन हो रहा है, (ख) आयातक देश में समान उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है, और (ग) वो पूर्व परिणामों के बीच कोई कारणात्मक संबंध है।"
- उपर्युक्त विषय के आधार पर इंडोनेशिया सरकार डीजीसीए से अनुरोध करती है कि वे मेलामाइन के आयात पर विशेष रूप से इंडोनेशिया से पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना न बढ़ाएं क्योंकि घरेलू उद्योग को अब कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।
- इंडोनेशिया सरकार ने दो तथाकथित कंपनियों अर्थात् पीटी, डीएसएम कालिम मेलामाइन और पीटी श्री मेलामाइन रेजेटी की मौजूदगी सत्यापित की है और यह कि दोनों कंपनियां मौजूद नहीं थीं तथा उन्हें दिवालिया घोषित किया गया है।
- उपर्युक्त तथ्य याचिका में आंकड़ों का समर्थन करते हैं (प्रपत्र IV पैरा 1 पृष्ठ 44), जो यह दर्शते हैं कि 2013-17 तक इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं था।

(ङ) मैसर्स एक्जिम कॉर्प इंडिया प्रा. लि.

- पिछले पांच वर्षों में जीएसएफसी द्वारा बिक्री वसूली में कम और रद्द ग्रेड शामिल हैं और इसीलिए वे तुलनीय नहीं हैं तथा भारित औसत एनएसआर के परिकलन के लिए उन्हें अलग किया जाना चाहिए।
- डीजीएडी को चाहिए कि वे हमारे लिए एनआईपी प्रकाशित करें ताकि हम अनुरोध कर सकें।

- पाटनरोधी उपाय ऊपरी लाभ मार्जिन अर्जित करने के लिए एक हथियार नहीं है। घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क के बिना लाभप्रद कीमतों पर अपने उत्पाद बेच सकता है।
- पाटन अथवा क्षति की संभावना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है और यह केवल अवधारणाएं हैं।
- डब्ल्यूटीओ के विश्वसनीय साक्ष्य के संबंध में न्याय निर्णय है, यथा ग्वाटेमाला – मैक्सिको से पत्तन भूमि सीमेंट के संबंध में पाटनरोधी जांच में डब्ल्यूटीओ पैनल तथा कनाडा से सॉफ्टवुड लम्बर संबंधी अमेरिकी अंतिम निर्धारण में पैनल। घरेलू उद्योग की याचिका में पाटन एवं क्षति के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हैं।
- जीएसएफसी ने कारखानागत निर्यात कीमत में कटौतियों के पीछे कोई साक्ष्य न देकर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- जीएसएफसी को न तो मात्रा और न ही कीमत के संबंध में क्षति हुई है और इसीलिए किसी भी तरह कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है।
- वास्तविक एनआईपी 74300 रुपए/मी. टन पर निर्धारित की गई थी जो गलतीसे अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित की गई थी।
- याचिकाकर्ता भारत में लागत एवं एनआईपी के प्रकटन से बचा है।
- यूरोपीय संघ में वर्ष 2012 से 2016 के दौरान 1013 यूरो से 1149 यूरो प्रति मी. टन तक औसत विक्री वसूली सत्यापित की गई और इसीलिए सामान्य मूल्य इस रेंज में होना चाहिए।
- प्राधिकारी को चाहिए कि वह यूरोपीय संघ के जांच परिणामों के विभिन्न कारकों की भी जांच करें और घरेलू उद्योग की एनआईपी अब 58500 रुपए/मी. टन से अधिक नहीं हो सकती।
- प्राधिकारी को चाहिए कि वे क्षति की संभावना को एक नकारात्मक जांच परिणाम के रूप में लेने के बजाए सकारात्मक जांच परिणाम के रूप में क्षति होने के जोखिम को सिद्ध करें। जब पाटनरोधी नियमावली में सार्वजनिक हित के लिए कोई सकारात्मक शब्द नहीं है और न ही कोई नकारात्मक शब्द है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को चाहिए कि वे निचले उद्योगों को हितों के संबंध में एक समुचित विश्वेषण दें।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए बनुरोध

- पाटित आयातों का हिस्सा संबद्ध देशों से लगभग 26 प्रतिशत रहा जो कि एक महत्वपूर्ण प्रतिशतता है और ऐसी प्रतिशतता की संगतता यह है कि वे पाटित दरों पर की गई थी।
- घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति जांच की अवधि में सकारात्मक रही जो लागू पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव के रूप में कोई गंभीर वास्तविक क्षति नहीं दर्शाती है।
- उपर्युक्त के होते हुए क्षति उपयोग, जो 2015-16 में 104.65 प्रतिशत था जो जांच की अवधि में घटकर 99.23 प्रतिशत हो गया।
- जांच की अवधि के दौरान पिछले वर्ष में आरओसीई भी थोड़ा कम हुआ।
- यूरोपीय संघ और जापान से कीमत कटौती पाटनरोधी शुल्क के बिना सकारात्मक थी। इरान नकारात्मक था और इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं थे। समग्र पीयू केवल थोड़ा से नकारात्मक है।
- इस महत्वपूर्ण स्तर पर पाटित आयातों की मौजूदगी ने यह दर्शाया कि बढ़ रही पाटित दरों पर ऐसे आयातों की भारी संभावना है और शीघ्र ही कंपनी हानियों की स्थिति में चली जाएगी। प्रपत्र के अनुसार घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि वह अब भी पाटित आयातों के लिए सुभेद्य है और घरेलू उद्योग को अपना निष्पादन बनाए रखने में, जो सहायता कर रहा है, वह लागू पाटनरोधी शुल्क है और उसके समाप्त होने पर पाटन के जारी रहने अथवा उसके बार-बार होने की संभावना है तथा घरेलू उद्योग

को क्षति होने की भी संभावना है। ऐसी संभावना है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग में पाटन तथा क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होगी।

- संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन एवं क्षति गंभीर रूप से मौजूद रहने की संभावना है। यह अनुरोध है कि संबद्ध सामान पाटित कीमतों पर संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे हैं। जांच की अवधि ("पीओआई") के दौरान संबद्ध देशों से वर्तमान पाटन मौजूद है। इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि मूल जांच में संबद्ध देशों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन संबद्ध देशों के उत्पादकों के पाटन के लिए रुक्कान दर्शते हैं। अतः यह तथ्य कि वर्तमान मामले में काफी पाटन मार्जिन है, जबकि पाटनरोधी शुल्क मौजूद है, माननीय प्राधिकारी के लिए इस कारण को सिद्ध करते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क जारी रहे। वर्तमान पाटन इस तथ्य को भी दर्शता है कि वर्तमान शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा।
- संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास विचाराधीन उत्पाद की व्यापक उत्पादन क्षमताएँ हैं और यदि वर्तमान शुल्क हटाया जाता है तो भारत में उस उत्पाद के गहन पाटन की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के उत्पादकों की उच्च निर्यात प्रतिशतता भी है। यह मौजूदा शुल्कों को हटाए जाने की स्थिति में भारत में विचाराधीन उत्पाद के बड़े हुए पाटन की संभावना स्पष्ट रूप से दर्शाता है, अतः काफी अधिशेष क्षमताओं तथा पर्याप्त निर्यात उन्मुखता के महेनजर यह कहा जा सकता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के पाटन का रुक्कान है। इस संबंध में, यह नोट करना व्यावहारिक है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए भारतीय मांग 2012-13 से पर्याप्त स्तर तक बढ़ी है और भारतीय मांग में वृद्धि के साथ यूरोपीय देशों से आयात भी 2007-08 से 2011-12 के दौरान यूरोपीय संघ से आयातों की तुलना में बढ़े हैं। इस समयावधि अर्थात् 2007-08 से 2011-12 में कोई तुलना करने की कोई संगति नहीं है क्योंकि 2013-14 से भारत में कुल मांग बढ़ी है। अतः समग्रता में पूरे परिवर्तन हैं कि यूरोपीय संघ से सामग्री पाटनरोधी शुल्कों में कोई कमी करने/उन्हें हटाने की स्थिति में अधिक मात्रा में आयात/पाटन होंगे। इससे यूरोपीय उत्पादक अपना क्षमता उपयोग वर्तमान लगभग 78 प्रतिशत के उपयोग की तुलना में और अधिक बढ़ाने में सक्षम होंगे।
- नियम 23 में उन मानदंडों का प्रावधान नहीं है जिनमें यह माप करने के लिए जांच किए जाने की आवश्यकता हो कि शुल्क समाप्ति से पाटन और निवल क्षति की संभावना होने वाली है। तथापि, इस प्रकार की जांच का कानूनी आधार जो हो सकता है, वह स्वयं याचिका में विस्तार से दिया गया है और उसे संक्षिप्तता के लिए पुनः नहीं दिया गया है। तथापि, निम्नलिखित अनुरोधों पर पुनः जोर दिया जाता है जो स्पष्ट रूप से पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शते हैं।

(क) **संबद्ध देशों में अत्यधिक उत्पादन क्षमता:** हमारी बाजार सूचना के अनुसार संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएँ हैं। अनुरोध है कि वर्तमान शुल्क को बंद किए जाने की स्थिति में संबद्ध देशों से पाटन निश्चित रूप से गहन होगा जिससे घरेलू उद्योग को गहन मात्रात्मक एवं कीमत संबंधी क्षति होगी। पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संबद्ध सामानों के आयात की मात्रा और अधिक बढ़ेगी ही। संबद्ध देशों के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित तथ्य दर्शती है अर्थात् उनकी अत्यधिक क्षमता तथा भारतीय बाजार की ओर उनके और अधिक बढ़ने की संभावना।

(क) इंडोनेशिया

- i. जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुए। यह समझा जाता है कि इंडोनेशियाई संयंत्र इस समय बंद है, परंतु संयंत्र के पुनरुद्धार के अवसर निकत हैं तथा शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति पुनः हो सकती है। यह एक तय स्थिति है कि शून्य आयातों से कोई संभावना नहीं है और जैसा कि नियमावली में परिकल्पित है, शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन एवं क्षति जारी रह सकती है अथवा पुनः हो सकती है।

(ख) ईरान

- i. ईरान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी पाटित दरों पर भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात करता रहा।
- ii. ईरान उत्पादक निर्यातोन्मुख भी हैं और भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए उनके पास क्षमताएँ हैं। वस्तुतः कुछ आयातकों द्वारा किए गए अनुरोध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मात्रा और मूल्य की दृष्टि से संबद्ध देशों से निर्यातों की काफी मात्रा है जो संबद्ध देशों की निर्यातोन्मुखता को सिद्ध करता है (सेंचुरी द्वारा 20.11.2017 के अनुरोध)।

- iii. सेंच्युरी द्वारा किए गए अनुरोध यह दर्शते हैं कि ईरान से कुल 9203 मी. टन के नियाति में से लगभग 2500 मी. टन 1.09 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की कीमत पर यूरोपीय संघ को था और लगभग 2000 मी. टन 1.13 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की कीमत पर टर्की को था जबकि वही भारत को 1.35 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम था। भारत को उच्च दर कीमत स्पष्ट रूप से लागू मौजूदा शुल्कों के कारण है और ऐसी पाटित कीमतों में नए स्तरों पर गिरावट आसन्न है। पाटनरोधी शुल्क की स्थिति में ईरान की नियाति कीमत में गिरावट इस प्रकार आसन्न है।
- iv. उपलब्ध साक्ष्य ईरान से पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शते हैं। याचिकाकर्ता के स्तर पर उपलब्ध तीसरे देश को नियाति संबंधी सूचना अनुरोध के साथ दी गई है।

(ग) जापान

- i. जापान पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी पाटित दरों पर भारत को संबद्ध सामानों का नियाति करता रहा।
- ii. जापानी उत्पादक नियातोन्मुख हैं और भारत में नियाति बढ़ाने के लिए उनके पास क्षमताएं हैं। जापान ने 2015-16 में यूरोपीय संघ को लगभग 8200 मी. टन का नियाति किया।
- iii. सेंच्युरी द्वारा किए गए अनुरोध यह दर्शते हैं कि 2016-17 में जापान से कुल 49000 मी. टन के नियाति में से लगभग 17000 मी. टन 0.99 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम की दर से यूरोपीय संघ को था जबकि वही भारत को 1.15 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम पर था। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को उच्चतर, परंतु पाटित कीमतें लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण थीं और जापान से नियाति वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में बढ़ जाएंगे। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में जापान की नियाति कीमत में गिरावट इस प्रकार आसन्न है।
- iv. हमारी सूचना के अनुसार जापान के पास लगभग 90000 मी. टन की क्षमता है और इसका लगभग आधा नियाति किया जाता है। घरेलू मांग काफी नहीं समझी जाती और शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में जापान भारत को और अधिक सामग्री भेजेगा।
- v. उपलब्ध साक्ष्य जापान से नियाति करने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शते हैं। याचिकाकर्ता के स्तर पर उपलब्ध तीसरे देश को नियाति संबंधी सूचना अनुरोध के साथ दी गई है।

(घ) यूरोपीय संघ

- i. यूरोपीय संघ पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी पाटित दरों पर भारत को संबद्ध सामानों का नियाति करता रहा।
- ii. यूरोपीय संघ के उत्पादक भी नियातोन्मुख हैं और भारत में नियाति बढ़ाने के लिए उनके पास क्षमताएं हैं। सेंच्युरी जैसे विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विश्व नियाति संबंधी सूचना सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि उपर्युक्त आंकड़े भारत को काफी कम मात्रा दर्शते हैं तथा जो डीजीसीआईएंडएस द्वारा उसी अवधि में सूचित किए गए हैं। सेंच्युरी द्वारा दिए गए सेंच्युरी डब्ल्यूआईआईएंडएस 6723 मी. टन दर्शता है।
- iii. उपलब्ध साक्ष्य यूरोपीय संघ से आयातों की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शते हैं।
- (i) यूरोपीय संघ/यूरोपीय आयोग द्वारा प्रकाशित चीन जन गण से मेलामाइन संबंधी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायिक समीक्षा से संबंधित नवीनतम अंतिम जांच परिणाम यूरोपीय संघ के बाजार में निप्पलिखित संगत मदों को दर्शते हैं जो संभावना बताते हैं।
- (ii) यूरोपीय संघ के पास लगभग कुल 479120 मी. टन की क्षमता है और क्षमता उपयोग लगभग 78 प्रतिशत था जिसका अर्थ यह है कि अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है। यद्यपि यह तर्क दिया जा सकता है कि यह कम उपयोग वहां कम से कम पिछले कुछ वर्षों से था। मुख्य विन्दु यह है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से भारत में नियाति बढ़ाने के लिए ऐसी क्षमताओं का उपयोग हो सकता है। चूंकि, पाटनरोधी शुल्क के बाद भी पाटन जारी रहा, अतः संभावना केवल यह है कि सामग्री भारत में भारतीय उद्योग को विवरित करते हुए कम कीमत पर ही पहुँचेगी।

(iii) यूरोपीय संघ में मांग उपर्युक्त जांच परिणाम के अनुसार 2015-16 के दौरान लगभग 392776 मी. टन थी। इस प्रकार, क्षमताएं स्पष्ट रूप से निर्यात बाजारों को लक्ष्य बनाकर स्थापित की जाती हैं और यूरोपीय संघ में अतिरिक्त क्षमता भारत में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को हटाने के लिए पर्याप्त होगी।

(iv) यूरोपीय संघ से किए गए आयातों की कीमतें कटौती स्तर पर हैं। कटौती, पाटित और क्षतिकारक स्तरों पर हैं जिससे और अधिक पाटन एवं क्षति होने की संभावना बहुत ही आसन्न है।

(v) उपर्युक्त अंतिम जांच परिणाम यह दर्शाते हैं कि यूरोपीय संघ के उत्पादक लगभग 34 प्रतिशत आरओआई प्राप्त कर रहे थे और अब भी यह पाया गया कि क्षति पुनः हो सकती है जबकि घरेलू उद्योग का आरओआई उससे काफी कम है। यूरोपीय संघ का उद्योग अर्थात् याचिकाकर्ता लगभग 15 प्रतिशत की विक्री पर लाभप्रदता प्राप्त कर रहा था जो कि बहुत अधिक है।

(vi) यूरोपीय संघ में चीन जन गण से आयात मांग के 2 प्रतिशत से कम था जबकि भारत में एससी का हिस्सा लगभग 26 प्रतिशत है और यूरोपीय संघ ने पाया कि चीन जन गण से भी इस मात्रा ने पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शाई।

(vii) यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया एमआईपी चीन जन गण से आयात से संबंधित 1153 यूरो प्रति मी. टन है। यह यूरोपीय उत्पादकों के लिए भी एक स्पष्ट निर्धारण कीमत होगी क्योंकि वे अपनी कीमतें आयातों के बराबर (2015-16 में कीमत 1149 यूरो थी) रखने का प्रयास करेंगे। यह एमआईपी यूरोपीय संघ के मामले में सामान्य मूल्य के लिए आधार हो सकता है। उपर्युक्त जांच परिणाम में दी गई मेलामाइन की लागत एवं कीमत वर्ष 2016-17 के लिए नहीं है और 2015-16 के लिए है, परंतु एमआईपी जांच की अवधि के लिए भी लागू है। साथ ही यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कच्ची सामग्री की लागत मेलामाइन के लिए कीमत का निर्धारक कारक नहीं है क्योंकि मेलामाइन की कीमतें मांग एवं आपूर्ति की स्थिति द्वारा शासित होते हैं। इस जांच परिणाम का महत्व यह है कि वर्ष 2015-16 के लिए दी गई यूरोपीय संघ में लागत उस लागत के समायोजन के साथ संभावित कीमत का संकेतक नहीं है जो 2016-17 के लिए यूरोपीय संघ में मेलामाइन के लिए सामान्य मूल्य हो सकती है। एमआईपी यह दर्शाता है कि इन कीमतों की स्थिति में भी सकारात्मक पाटन मार्जिन होगा।

(viii) उपर्युक्त आंकड़े बिन्दु यह दर्शाते हैं कि यूरोपीय संघ से निर्यातकों के पास भारत को अधिक निर्यात करने की क्षमता है और पाटित मात्रा में इस वृद्धि के अवसर बहुत ही आसन्न हैं। यूरोपीय संघ अकेला ही पूरी भारतीय मांग को ले सकता है यदि यूरोपीय संघ के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क न हो।

संबद्ध देशों से संभावित निर्यातों और अतिरिक्त क्षमता संबंधी साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि इन सभी स्रोतों से निर्यात शुल्क की समाप्ति से कम/पाटित कीमत स्तरों पर भी बढ़ेंगे और पाटन एवं क्षति की संभावना इस निमित्त बहुत ही आसन्न है।

(ब्य) घरेलू उद्योग की सुभेद्रता: इस कारक का इस बात से संबंध है कि क्या घरेलू उद्योग लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में वास्तविक क्षति के लिए संबंधित निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस पर विचार करना ही चाहिए कि क्या इस उद्योग का लागू पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के बाद आगे हास होगा। इस मामले में पाटित आयातों की सतत मौजूदगी यह दर्शाती है कि ऐसे पाटित आयातों के प्रति सुभेद्रता काफी दूर तक मौजूद है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को आयात कीमत के बराबर विक्री कीमतें कम करनी होंगी जिससे वास्तविक क्षति होगी, जैसा कि नीचे दिया गया है।

- वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग आयात कीमतों पर विक्री का विकल्प चुनता है तो घरेलू उद्योग को काफी कीमत संबंधी क्षति होगी। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग पहले ही आयातित कीमतों के बराबर अपने उत्पादों की विक्री करने के लिए मजबूर है।
- वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में और यदि घरेलू उद्योग वर्तमान विक्री कीमत बनाए रखना का विकल्प चुनता है तो घरेलू विक्री अत्यधिक कम हो जाएगी, संभवतः उसका स्वल्प बाजार हिस्सा रह जाएगा।
- साथ ही पूरा किया जा रहा क्षमता विस्तार भी प्रभावित होगा। इस प्रकार, वर्तमान क्षमता पर सुभेद्रता है और बढ़ती हुई क्षमता भी प्रभावित होगी।

(ग) **भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता:** इस उत्पाद की भारत में बहुत ही अधिक मांग है। जिस कीमत पर संबद्ध सामान संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे हैं, वे ऐसे स्तर पर हैं कि वे उस कीमत पर एक गंभीर दबाव बना रही हैं जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में सामान बेचे जा रहे हैं जो कि इस तथ्य में सिद्ध है कि यूरोपीय संघ और जापान से आयातों की स्थिति में कीमत कटौती सकारात्मक रही है तथा संबद्ध देशों के स्तर पर केवल थोड़ी सी नकारात्मक रही है। अतः शुल्क की समाप्ति की स्थिति में निर्यातिक भारतीय बाजार में अपने उत्पादन का फिर से चैनल बनाएंगे क्योंकि उनके पास पहले ही अत्यधित क्षमताएं और भारत में मांग ऐसे पाटन के लिए बहुत ही अनुकूल हैं।

(घ) **उपायों की गैर-मौजूदगी में कीमत कटौती:** जैसा कि पहले ही अनुरोध किया गया है कि यूरोपीय संघ और जापान से आयातों से जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती करते आ रहे हैं। यद्यपि ईरान नकारात्मक था। शुल्क हटाए जाने की स्थिति में स्थिति और भी बिंगड़ जाएगी और कीमत कटौती का स्तर ईरान के मामले में भी काफी सकारात्मक हो जाएगी।

(ङ) **पाटन के जारी रहने अथवा बार-बार होने की कोई संभावना न होने को सिद्ध किया ही जाना चाहिए:** यद्यपि ये बातें सिद्ध करती हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तथापि, यह अनुरोध है कि यह सिद्ध करने के लिए संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों पर है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना नहीं है। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया।

(च) **इंडोनेशिया से आयातों की स्थिति में क्षति की संभावना:** आयात सारांश विवरण से यह नोट किया जा सकता है कि पूरी क्षति की अवधि में इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों का कोई आयात नहीं हुआ है। यह अनुरोध है कि शून्य आयात वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना की गैर-मौजूदगी नहीं सिद्ध करता। इंडोनेशिया से आयात लागू पाटनरोधी शुल्कों के कारण शून्य हो गए हैं तथा पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति होगी, यदि इंडोनेशिया पर कोई पाटनरोधी शुल्क न लगे।

(छ) **पाटन एवं क्षति की संभावना का निष्कर्ष:** जीएसएफसी ने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने और उसके गहन होने की संभावना है। यह तथ्य कि पाटन लागू शुल्कों के बाद भी जांच की अवधि में संबद्ध देशों से जारी रहा, उन संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमताएं हैं जो भारत की ओर सामान भेजने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं, जापान और यूरोपीय संघ से सकारात्मक कीमत कटौती है तथा आयातों एवं घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत के बीच कीमत का अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में केवल गहन पाटन की संभावना ही नहीं है अपितु घरेलू उद्योग को गहन क्षति भी होने की संभावना है।

- मूल जांच में संबद्ध देशों के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन के अलावा, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए संबद्ध देशों की व्यापक क्षमता भी भारत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। याचिका में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के लिए रुक्मान और विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए उन संबद्ध देशों की व्यापक क्षमताएं जारी पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन की प्रबल संभावना सिद्ध करते हैं।
- उपर्युक्त के संबंध में यह अनुरोध है कि संबद्ध देशों में मांग की तुलना में उत्पादन के बीच भारी अंतराल है। ऑस्ट्रिया से 2016 के कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल निर्यात 32855 मी. टन था, जर्मनी से 89004 मी. टन था और जापान के लिए 41488 मी. टन था। अतः संबद्ध देशों में मांग के संदर्भ में और उनके प्रचुर उत्पादों के संबंध में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में घरेलू उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। संबद्ध देशों में अन्य महत्वपूर्ण प्रचालक कारकों पर विचार करना भी महत्वपूर्ण है जो उन्हें भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये कारक हैं – पंजीकरण के तहत प्रचालन होने वाले कठोर मानदंड, मूल्यांकन, प्राधिकार और रसायनों का प्रतिबंधिकरण, जिनकी अपेक्षा है तथा यूरोप में विचाराधीन उत्पाद की विक्री के लिए इन कारकों को अपनाया जाना चाहिए। अतः इन मानदंडों से बचने के लिए अथवा इन मानदंडों के तहत रद्द करने के लिए यूरोप आसानी से अपने विचाराधीन उत्पाद का भारी उत्पादन भारत में आसानी से पाटित कर सकता है। ईरान से विचाराधीन उत्पाद के भारत में पाटन की संभावना ईरान पर मौजूदा प्रतिबंधों के कारण समान रूप से अधिक है।

- यह भी पाया गया है कि संबद्ध देशों द्वारा भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद की निवल वापसी कीमत संबंधित देशों में मौजूद कीमत से कम है। यह सूचना ट्रेड मैप इंडिया से मेलामाइन की स्थल एवं संविदागत कीमतों के लिए आईसीएसएलओआर से उपलब्ध कीमत संबंधी रिपोर्ट से ली गई है।
- लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में विस्तारित क्षमता के साथ जीएसएफसी के नए संयंत्र गंभीर रूप से प्रभावित होंगे जिससे जीएसएफसी को अपने प्रचालन बंद करने होंगे।
- जीएसएफसी भारत में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र विनिर्माता है, अतः वह वर्तमान याचिका में घरेलू उद्योग है। जीएसएफसी का पहला संयंत्र 5000 एमटीपीए की संस्थापित क्षमता के साथ 1982 में स्थापित किया गया था और वह चेमी-लिंज ऑस्ट्रिया से प्रौद्योगिकी आधार पर था। उसके बाद, भारत में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 10000 एमटीपीए की संस्थापित क्षमता का दूसरा संयंत्र 1997 में स्थापित किया गया था जो उसी प्रौद्योगिकी पर आधारित था। वर्तमान में विचाराधीन उत्पाद की कुल संस्थापित क्षमता 15000 एमटीपीए है। तथापि, विचाराधीन उत्पाद की मांग 1997 से भारत में वर्तमान तक बढ़ गई है। अतः बढ़ती हुई मांग को देखते हुए जीएसएफसी भारत में उत्पाद के लिए स्थिर मांग को पूरा करने हेतु काफी क्षमताएं शामिल करने की प्रक्रिया में हैं और वे नई क्षमताएं निकट भविष्य में प्रचालनात्मक हो जाएंगी। अतः जीएसएफसी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए 40000 एमटीपीए का संयंत्र अतिरिक्त रूप से जोड़ रहा है। जीएसएफसी द्वारा किया गया कुल निवेश 1000 करोड़ रुपए का है और इस परियोजना के लिए घरेलू कीमत 1400 अमेरिकी डॉलर से 1500 पीएमटी तक है।
- इस संयंत्र का प्रचालन गैर अर्थक्षम होगा और संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क के अभाव में उद्योग को हताश करेगा। दी गई वर्तमान कीमतों के अनुसार, पाटनरोधी शुल्क संरक्षा के तहत जीएसएफसी अपने दोनों मेलामाइन संयंत्रों को उपयुक्त मार्जिन के साथ दक्षतापूर्वक प्रचालित करने में सक्षम रहा है। मेलामाइन की विक्री के मार्जिन जीएसएफसी द्वारा मेलामाइन की तीन विस्तार परियोजना के विस्तार को पूरा करने के लिए तथा घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। अतः पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.1 के अनुसार यह अनुरोध है कि शुल्क जब तक हो सके तथा जिस सीमा तक हो सकें लागू रखे जाएं ताकि पाटन के कार्य का सामना किया जा सके जो कि क्षति पहुँचा रहा है।
- विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रमुख कझी सामग्री यूरिया है। भारत में यूरिया का विनिर्माण करने वाली अनेक कंपनियां हैं, परंतु जीएसएफसी को छोड़कर किसी भी कंपनी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन स्थापित करने की चुनौती नहीं दी। जिन विभिन्न चुनौतियों ने अन्य कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए हतोत्साहित किया, वे गार्ड टैक्नोलॉजी, परिसर प्रचालन, विशेष अलॉय उपस्कर, उच्च पूंजी गहन परियोजना, चीन और खाड़ी देशों जैसे गैस की कम कीमत वाले देशों द्वारा पाटन आदि हैं। कठिनाई के बावजूद जीएसएफसी ने उपर्युक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने प्रचालन सफलतापूर्वक स्थापित किए। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि जीएसएफसी के प्रचालनों को भारी हानियों के कारण बंद होने से बचाया जाए, जो हानियां उसे पाटनरोधी शुल्क के अभाव में होंगी।
- जीएसएफसी पहले ही अपनी क्षमता का विस्तार करने की प्रक्रिया में है। अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का निर्णय काफी लम्बे समय से कार्यान्वयन के लिए लंबित रहा है। कार्यान्वयन में विलंब मेलामाइन 3 परियोजना के आर्थिक कारकों और अंतर्राष्ट्रीय मानक क्षमता संयंत्रों के तहत प्रचालित होने वाले कारकों के कारण हुआ है। तथापि, जीएसएफसी के अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं को स्थापित करने के प्रयासों को किस तथ्य से मेलामाइन 3 परियोजना के लिए उसने 650 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की थी। तथापि, उर्वरक विभाग, भारत सरकार के तहत नीतिगत अड्डचनों के कारण जीएसएफसी दहेज में अमोनिया-यूरिया परियोजना को लाने में सक्षम नहीं रहा। इसके परिणामस्वरूप दहेज में प्रस्तावित मेलामाइन परियोजना विफल रही।
- जहां तक सेंच्युरी प्लाईबोइर्स (आई) लि. द्वारा किए गए अनुरोधों का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सेंच्युरी के यह दावे कि पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है, किसी औचित्य के बिना नकारा जाता है। सेंच्युरी द्वारा जिन परिकलनों पर विश्वास किया गया है, वे अपनी सेवा करने वाले हैं तथा वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति नहीं दर्शते। प्राथिकारी विभिन्न जांचों पर विचार करते हुए याचिका द्वारा प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं और सेंच्युरी द्वारा किए गए अनुमानों पर विश्वास न करें जिनका वास्तविकता से स्पष्ट रूप से कोई संबंध नहीं है। सेंच्युरी ने घरेलू उद्योग की विक्री लागत तथा निवल विक्री कीमत और आयातों की पहुँच कीमत के बीच तुलना की है। यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि को ग्राहकों तक देने में सक्षम रहा।

है। अतः यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को कीमत न्यूनीकरण/ह्रास के प्रभाव के कारण भारी वित्तीय हानियों का आसन्न खतरा होगा क्योंकि वर्तमान में संबद्ध देशों के आयात जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों से कम पर बेचे जा रहे हैं।

- भारतीय बाजार के विपणन एवं बिक्री संबंधी प्रभाव के अनुसार विचाराधीन उत्पाद की बिक्री चैनल भागीदारों के माध्यम से प्रत्यक्ष बिक्री तथा अप्रत्यक्ष बिक्री, दोनों तरीके से की जाती है जिसका अनुपात क्रमशः 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत है। इस प्रकार, जीएसएफसी कठिन, मंद और दुलमुल बाजार की विकट स्थितियों को झेलते हुए हर प्रकार की बाजार स्थितियों में निरंतर अपने उत्पाद की बिक्री कर रहा है। इन बाजार स्थितियों में भारी आयात का प्रवाह, ग्राहकों के खरीददारी के बेमन व्यवहार आदि जैसे कारक शामिल हैं। चैनल भागीदारों को अप्रत्यक्ष बिक्री जीएसएफसी की निरंतर बिक्रियों का ध्यान रखती है जिनमें बहुविध सामग्री सारसंभाल, लघु एवं मध्यम ग्राहक आधार की मांग पूरी करना, क्रृष्ण भुगतान दिवस बढ़ाना, ग्राहकों की अनिवार्यता एवं असुरक्षित भुगतान शर्तों की लागत शामिल हैं। यह सच नहीं है कि वितरकों के माध्यम से मेलामाइन की लागत प्रत्यक्ष ग्राहकों को पेश की गई लागत से अधिक है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना व्यावहारिक होगा कि मैसर्स सेंच्युरी प्लाईवुड ने विचाराधीन उत्पाद की खरीद की (जीएसएफसी मेलामाइन का लगभग 26 मी. टन, जो मैसर्स सेंच्युरी प्लाईवुड द्वारा विचाराधीन उत्पाद की कुल वार्षिक आवश्यकता का केवल 1 प्रतिशत है) और सेंच्युरी पर भिन्न रूप से प्रभार नहीं लगाए गए। अतः मैसर्स सेंच्युरी प्लाईवुड के लिए उसके मामले को सिद्ध करने के लिए गलत दर्शाए गए आंकड़ों पर विश्वास करना गलत होगा।
- मैसर्स सेंच्युरी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध आयातों के संबंध में जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन के मामले में शुल्क बंद किए जाने चाहिए तथा कई पिछले मामलों पर उन्होंने उल्लेख किया है। यह अनुरोध है कि सेंच्युरी का अनुरोध स्वीकार न किया जाए। यह हमारे दावे के पूर्वाग्रह के बिना है कि क्षति मार्जिन जांच की अवधि में और जांच के अवधि के बाद की किसी भी अवधि में सकारात्मक होगा। तथापि, नकारात्मक क्षति मार्जिन से मौजूदा शुल्क रद्द नहीं हो सकते। क्षति मार्जिन मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के कारण घरेलू उद्योग की गैर सतत क्षति की स्थिति को दर्शा सकता है और नियम के तहत अपेक्षा लागू उपायों की समाप्ति के कारण क्षति की संभावना है। नई जांच में उपायों की मात्रा के प्रयोजन के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया जाता है क्योंकि भारत कम शुल्क नियम को अपनाता है और वर्तमान मामले में इस प्रकार की मात्रा की आवश्यकता मौजूद नहीं है क्योंकि वर्तमान जांच केवल एक निर्णयिक समीक्षा है। इस प्रकार, नकारात्मक क्षति मार्जिन वर्तमान शुल्कों को बंद करने का आधार नहीं हो सकता और किसी भी दशा में हमारे अनुरोध स्पष्ट रूप से वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शाते हैं।
- निरमा लि. बनाम यूओआई के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है कि संभावना के पहलुओं पर विचार करते समय क्षति मार्जिन एक असंगत कारक है तथा उपर्युक्त निर्णय आज भी इस भूमि का नियम है तथा अकेले इस निर्णय के आधार पर कोई भी शुल्क समीक्षा में नकारात्मक क्षति मार्जिन का उल्लेख करके रद्द किया जा सकता। इस प्रकार, सेंच्युरी का तर्क रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान गुणवत्ता अर्थात् मानक, नियमित और एमएस के आधार पर क्रमशः 90.48 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत तथा 3.02 प्रतिशत मेलामाइन के 3 ग्रेडों की बिक्री की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह जांच मेलामाइन की सभी ग्रेडों के संबंध में है तथा मूल जांच परिणाम में अथवा चीन से आयातों के अन्य पाटनरोधी शुल्कों के मामले में कोई पृथक उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) नहीं बनाई गई थी। एनआईपी, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत औसत आधार पर सभी ग्रेडों के लिए अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है तथा उत्पादित किए जा रहे एवं निर्यातित किए जा रहे ग्रेडों की किस्म के संबंध में कोई भी आंकड़े सूचित नहीं की गए हैं। अतः प्राधिकारी ने औसत आधार पर मेलामाइन की सभी ग्रेडों के लिए विश्वेषण पर विचार किया है।

27. जहां तक व्यापारियों को बिक्री के मुद्दे का संबंध है, प्राधिकारी ने एनएसआर का मूल्यांकन कारखानागत आधार पर किया है, जो छूट/कमीशन का निवल है। घरेलू उद्योग द्वारा व्यापारियों को बिक्री का अनुपात उसकी कुल बिक्री का लगभग 18 प्रतिशत है और भारी अनुपात की बिक्री नहीं है, जैसा कि आयातकों द्वारा दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त, घरेलू अथवा निर्यात में बिक्री

चैनल उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर है तथा इस मामले में घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में बिक्री तथा संबद्ध देशों से आयातों की बिक्री, दोनों में व्यापारी भी शामिल होते हैं। इसीलिए, प्राधिकारी ने सिद्धांत को अपनाते हुए कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री की तुलना के लिए सभी ग्रेडों और बिक्री चैनल के भारित औसत एनएसआर पर विचार किया है, जैसा कि मूल मामले में किया गया।

28. प्राधिकारी ने कद्दी सामग्री के निर्देशात्मक मूल्यों की उपयोगिता तथा खपत योग्य एवं जांच की अवधि के दौरान प्राप्त सर्वोत्तम क्षमता उपयोग पर विचार करते हुए जांच की अवधि के लिए तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए एनआईपी का परिकलन किया है। प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, नियोजित पूँजी पर आय की अनुमति दी गई है।
29. प्राधिकारी ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय निष्पादन संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में किया है।

च. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

च.1 मात्रात्मक प्रभाव

च.1.1 मांग एवं बाजार हिस्सा

30. निम्नलिखित तालिका अति की अवधि एवं जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग दर्शाती है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
यूरोपीय संघ से आयात	मीटन .	6,542	9,287	6,817	6,723
ईरान से आयात	मीटन .	6,052	5,240	10,074	5,304
जापान से आयात	मीटन .	1,040	2,060	1,280	740
इंडोनेशिया से आयात	मीटन .	-	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	मीटन .	13,634	16,587	18,171	12,767
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले अन्य देशों से आयात	मीटन .	22,582	24,262	18,284	23,305
अन्य देशों से आयात	मीटन .	4,614	9,702	16,196	12,674
कुल आयात	मीटन .	40,830	50,551	52,651	48,745
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री	मीटन .	15,378	14,283	15,096	15,341
मांग	मीटन .	56,208	64,834	67,747	64,086
मांग में हिस्सा					
यूरोपीय संघ से आयात	%	11.64	14.32	10.06	10.49
ईरान से आयात	%	10.77	8.08	14.87	8.28
जापान से आयात	%	1.85	3.18	1.89	1.16
इंडोनेशिया से आयात	%	-	-	-	-
संबद्ध देशों से आयात	%	24.26	25.58	26.82	19.92
पाटनरोधी शुल्क लगाने वाले अन्य देशों से	%	40.18	37.42	26.99	36.37

आयात					
अन्य देशों से आयात	%	8.21	14.96	23.91	19.78
कुल आयात	%	72.64	77.97	77.72	76.06
घरेलू उद्योग द्वारा विक्री	%	27.36	22.03	22.28	23.94

क्षति की अवधि और जांच की अवधि में मांग में निरंतर वृद्धि होती रही है। यद्यपि जांच की अवधि में स्वल्प गिरावट आई है जिसे क्षति के मामले के रूप में नहीं माना जा सकता।

छ.1.2 संबद्ध देश की आयात मात्रा तथा हिस्सा

31. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करने की अपेक्षा है कि क्या पाटित आयातों ने भारत में खपत अथवा उत्पादन की तुलना में अथवा पूर्ण रूप से काफी वृद्धि की है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उपर्युक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों ने भारत में खपत अथवा उत्पादन की तुलना में अथवा पूर्ण रूप से काफी वृद्धि की है।"

32. क्षति की अवधि के लिए आयात की मात्रा निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	13,634	16,587	18,171	12,767
यूरोपी संघ से आयात	मी. टन	6,542	9,287	6,817	6,723
ईरान से आयात	मी. टन	6,052	5,240	10,074	5,304
जापान से आयात	मी. टन	1,040	2,060	1,280	740
इंडोनेशिया से आयात	मी. टन	-	-	-	-
कुल आयात	मी. टन	40,830	50,551	52,651	48,745
कुल आयात में आयात का हिस्सा					
संबद्ध देश का हिस्सा	%	33.39	32.81	34.51	26.19
अन्य देशों का हिस्सा	%	66.61	67.19	65.49	73.81
की तुलना में संबद्ध देश से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	91.39	116.11	115.76	85.76
खपत	%	24.26	25.58	26.82	19.92

संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कम हुए हैं और उनका हिस्सा भी कम हुआ है।

छ.2 कीमत प्रभाव

छ.2.1 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

33. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर विक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के संर्वे में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल विक्री वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से

की गई है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के लिए तुलना पाठित आयातों के पहुँच मूल्य तथा घरेलू बाजार में घरेलू विक्री कीमत के बीच की गई थी। घरेलू उद्योग की निवल विक्री वसूली निर्धारित करने में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए करों, छूट, रियायत तथा कमीशन को समायोजित किया गया है। कम कीमत पर विक्री अति के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है; इस प्रकार प्राधिकारी ने अति रहित कीमत निकाली है और उसकी तुलना पहुँच मूल्य से की है ताकि कम कीमत पर विक्री की मात्रा निकाली जा सके। घरेलू उद्योग के लिए अति रहित कीमत का मूल्यांकन पाठनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। स्थिति निम्नलिखित है:

छ.2.2 कीमत कटौती तथा कम कीमत पर विक्री

34. प्राधिकारी ने उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित कारणों से शुल्क मुक्त आयातों के तहत इनपुट के पहुँच मूल्य का मूल्यांकन करने के बाद कीमत कटौती और कम कीमत पर विक्री का विश्लेषण पाठनरोधी शुल्क सहित और पाठनरोधी शुल्क के बिना, दोनों के साथ किया है।

विवरण	यूनिट	यूरोपीय संघ	ईरान	जापान	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	89.30	99.34	87.99	93.39
निवल विक्री वसूली	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	0 से 5	माइनस 5 से माइनस 10	0 से 5	0 से माइनस 5

उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि लागू पाठनरोधी शुल्क को ध्यान में रखने विना कीमत कटौती संबद्ध देशों के लिए संचयी आधार पर नकारात्मक है।

छ.2.3 कम कीमत पर विक्री

35. कम कीमत पर विक्री अति के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, इस प्रकार प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों की अति रहित कीमत निकाली है तथा उसकी तुलना कम कीमत पर विक्री की मात्रा निकालने के लिए आयातित सामानों के पहुँच मूल्य से की है।

विवरण	यूनिट	यूरोपीय संघ	ईरान	जापान	संबद्ध देश
पहुँच मूल्य	रु./कि. ग्रा.	89.30	99.34	87.99	93.39
गैर-अतिकारक कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कम कीमत पर विक्री/अति मार्जिन	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कम कीमत पर विक्री/(अति मार्जिन %)	% रेंज	0 से माइनस 5	माइनस 10 से माइनस 15	0 से माइनस 5	माइनस 5 से माइनस 10

उपर्युक्त तालिका से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर विक्री नकारात्मक है।

क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू विक्री

36. उत्पादन, विक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित है:

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
क्षमता	मी. टन	15,000	15,000	15,000	15,000
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
उत्पादन	मी. टन	14,918	14,285	15,698	14,886

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	105	100
क्षमता उपयोग	%	99.45	95.23	104.65	99.24
विक्री मात्रा	मी. टन	15,378	14,283	15,096	15,341
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93	98	100

घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा विक्री, क्षति की अवधि और जांच की अवधि में पूरी तरह स्थिर एवं सतत रहा है।

मालसूची

37. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

विवरण	शूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आरंभिक स्टॉक	मी. टन	509	47	48	649
अंतिम स्टॉक	मी. टन	47	48	649	194
औसत स्टॉक	मी. टन	278	48	349	422
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	17	125	152

मालसूची में अंतर स्टॉक बढ़ा होने के साक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं है।

लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

38. क्षति की अवधि में लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	शूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
विक्री की लागत	रु. कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	93.00	96.52	95.98
विक्री कीमत	रु. कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	99.02	104.74	101.97
लाभ/(हानि)	रु. कि. ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	357.10	457.30	359.04
लाभ/(हानि)	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	331.67	448.87	358.14
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	141.48	188.32	152.55
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	356.02	539.01	400.26

क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान लाभप्रदता तथा निवेश पर आय स्थिर और सकारात्मक रहे हैं।

रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

39. नीचे दी गई सूचना से प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की रोजगार की स्थिति जांच की अवधि के दौरान आधार वर्ष की तुलना में बिगड़ी नहीं है। उत्पादन प्रति दिन और उत्पादन प्रति कर्मचारी की दृष्टि से उत्पादकता इस अवधि में उसी स्तर पर रही है जो कोई प्रतिकूल प्रवृत्ति नहीं दर्शाती।

विवरण	यूनिट	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	94	98	95
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	129	181	149
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	107	105
प्रति दिन उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	105	100

पाठन की मात्रा

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाठन मार्जिन ईयू के लिए सकारात्मक है जबकि ईरान के लिए यह नकारात्मक है और जापान के लिए घरेलू उद्योग के अनुसार परिकलित सीएनबी के आधार पर सकारात्मक है, द्वितीयक म्रोतों से यह नकारात्मक है। इसके अलावा, पीओआई के बाद के लिए सभी तीन देशों के लिए पाठन मार्जिन नकारात्मक/न्यूनतम है।

वृद्धि

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विक्री, उत्पादन की दृष्टि से घरेलू उद्योग की विक्री आधार वर्ष से तुलना करने पर स्थिर रही है।

पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता

42. घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि उसने 7000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने की योजना बनाई है जो कई उत्पादों के लिए है। इसमें मेलामाइन की महत्वपूर्ण क्षमता का विस्तार शामिल है। कंपनी ने तर्क दिया है कि वह मेलामाइन के लिए 40000 मीट्रिक टन तक क्षमता बढ़ाने का इरादा रखती है। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि मेलामाइन के सतत पाठन से उत्पाद के संबंध में कंपनी की विस्तार योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के सतत पाठन और उत्पाद में वित्तीय हानियों से पूंजी निवेश बढ़ाने में घरेलू उद्योग की क्षमता निश्चित रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। यद्यपि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है, तथापि, इस उत्पाद के कारण घरेलू उद्योग के प्रचालनात्मक निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव से संबद्ध सामानों के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने में घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन से मेलामाइन के आयात पर पाठनरोधी उपाय लागू हैं जो वैश्विक क्षमता का लगभग दो तिहाई रखता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा उनकी नई विस्तारित सुविधा में उनके द्वारा किए गए निवेशों के संबंध में किए गए अनुरोध को नोट करते हैं जो मौजूदा पाठनरोधी उपाय हटाने से कुप्रभावित हो सकते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि पांच वर्षों के लिए मौजूदा पाठनरोधी उपायों से घरेलू उद्योग को एक अच्छा व्यापारिक क्षेत्र मिला है जो उसके सुधरे हुए निष्पादन मानदंडों में परिलक्षित है। भावी उत्पादन परियोजना, जो अभी आनी है, का संरक्षण आगे चलते रहने वाली निर्णायिक समीक्षा में हल नहीं किया जा सकता जिसमें मौजूदा आधार को क्षति की संभावना के संबंध में मूल्यांकन की जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा वह कर दिया गया है। घरेलू उद्योग की अतिरिक्त क्षमता के लिए स्तरीय व्यापारिक क्षेत्र पर उसके आने पर प्राधिकारी द्वारा उस समय मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर और पाठनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

कारणात्मक संपर्क

44. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में यह जांच की कि क्या ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है:

तीसरे देशों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध सामानों का प्रमुख आयात चीन से और कतर से है, जबकि चीन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क है। कतर से आयात व्यापक रूप में जीएसएफसी द्वारा किए गए हैं जिनकी जांच की गई है।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) ने यद्यपि निर्णायिक समीक्षा की जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद आयातित नहीं किया है, तथापि, उसने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान ईरान से क्रमशः 940 मी. टन और 100 मी. टन की मात्रा तक विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है तथा वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान जापान से क्रमशः 500 मी. टन और 600 मी. टन तक की मात्रा आयात की है। उसने कतर से वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 (जांच की अवधि) के दौरान क्रमशः 1500 मी. टन, 8280 मी. टन और 5379 मी. टन की सीमा तक गैर संबद्ध देश कतर से भी नियमित रूप से आयात किए हैं। जांच की अवधि के बाद की छः माह की अवधि में अर्थात 01.04.2017 से 30.09.2017 तक भी उसने कतर से 1140 मी. टन तक का आयात किया है।

47. मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएसएफसी) द्वारा कतर से आयात उन औसत कीमत से कम पर रहे हैं जो क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान अन्य आयातों द्वारा किए गए आयातों की थीं। कतर से आयात कीमत जापान की आयात कीमत से तुलनीय हैं, परंतु यूरोपीय संघ और ईरान की कीमत से कम हैं। आवेदक ने क्षति की अवधि के वर्षों के दौरान सतत रूप से उन कीमतों पर कतर से आयात किए, परंतु कतर से इन तुलनीय आयात कीमतों के कारण क्षति होने की सूचना नहीं दी/आरोप नहीं लगाए।

48. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा कतर से किए गए आयात इसलिए थे ताकि वे अपने दीर्घावधि ग्राहकों के आदेशों को पूरा कर सकें और उन्होंने केवल 2-2.5 प्रतिशत के मार्जिन पर ही उसका व्यापार किया तथा कई बार उन्हें हानियां भी हुईं। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इतनी मात्रा का व्यापार मार्जिन व्यापार परिवेश में विशिष्ट है तथा यह व्यापार हिस्सा जीएसएफसी के उत्पादन का 40 प्रतिशत है। फिर भी, यद्यपि कतर एक संबद्ध देश नहीं है, तथापि, जीएसएफसी द्वारा कतर से आयात देश में कीमतों की प्रवृत्ति निर्धारित करने वाला भी है जिसे संबद्ध देश के निर्यातिक निर्धारण मानेंगे। अतः संबद्ध देशों से आयात कीमतों की प्रवृत्ति संबद्ध देशों से उत्पादकों और निर्यातकों की कीमत नीति का कारण नहीं हो सकती, परंतु कतर से आयात कीमतों द्वारा प्रभावित होने की उम्मीद भी है जो आयात व्यापक रूप से जीएसएफसी द्वारा किए गए थे।

49. प्राधिकारी आवेदक द्वारा लगाए गए पाटन एवं क्षति के खतरे के आरोप तथा कारणात्मकता की जांच करते समय इस पहलू पर विचार करने के बाद मानते हैं कि जिन परिस्थितियों में जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान क्षति मार्जिन संबद्ध देशों से नकारात्मक है और कतर से कीमतें या तो तुलनीय हैं अथवा संबद्ध देश की कीमतों से कम हैं। वहां क्षति का खतरा संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हो सकता।

मांग में संकुचन तथा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति की अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। उत्पाद के लिए मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है।

प्रौद्योगिकी में विकास

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शने के लिए ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं जिनके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

प्रतिस्पद्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाठियां

52. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और घरेलू उद्योग संबद्ध सामानों का पूरा उत्पादक है।

घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

53. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन संगत नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग में केवल कीमत और लाभप्रदता दी गई है तथा घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से प्राधिकारी द्वारा इसकी जांच की गई है।

अन्य उत्पादों का निष्पादन

54. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति की संभावना का किया गया दावा विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है। याचिकाकर्ता ने वह सूचना दी है जो केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है। वित्तीय सूचना विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दी गई है।

क्षति एवं कारण के संबंध में निष्कर्ष

55. प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंड स्थिर हैं तथा संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति होना प्रतीत नहीं होता। यह तथ्य कतर से आयात घरेलू उद्योग द्वारा समान कीमतों पर किए गए हैं, यह दर्शाता है कि ये आयात कीमतें क्षति रहित हैं। जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि, दोनों में नकारात्मक क्षति मार्जिन इस पहलू को और भी सिद्ध करता है।

ज. अन्य मुद्दे

ज.१ आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

56. आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(क) मैसर्से सेंचुरी प्लाइबोइर्स प्रा. लि.

- जांच की शुरूआत में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का उल्लेख नहीं है।
- जीएसएफसी ने अपनी बिक्री नीति को गोपनीय होने का दावा किया है, वह सीधे ही अंतिम प्रयोक्ताओं को बिक्री नहीं करता। व्यापारियों को बिक्री और अंतिम प्रयोक्ताओं को बिक्री के बीच कीमत का अंतर जीएसएफसी द्वारा गलत परिपाठियों के कारण है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सही एवं स्पष्ट मुद्दों के संबंध में सूचना नहीं दी है जिन पर वह पक्षकारों को सुनना चाहता है। प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद एक मौखिक सुनवाई भी निर्धारित की जानी चाहिए।
- मौखिक सुनवाई बाद में की जाए और पुनः निर्धारित की जाए।

(ख) मैसर्से अग्रवाल केमिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्से इंटरनेशनल ट्रेड रेमिडीज एंड प्रैक्टिसेस

- याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। आगे के उत्तर के लिए आंकड़े दिए जाएं।
- याचिकाकर्ता ने उपाय के जारी रहने के तहत निर्धारित शुल्क चाहा है। वस्तुतः इस जांच को रद्द किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) मैसर्से संदीप ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

- याचिकाकर्ता के पास मांग पूरी करने के लिए उचित क्षमता नहीं है।
- याचिकाकर्ता सरकारोन्मुख कंपनी है।
- याचिकाकर्ता की एकाधिकारिक स्थितियां हैं।

(घ) मैसर्स एक्सिजम कॉर्प इंडिया प्रा. लि ने अनुरोध किया है कि जीएसएफसी प्रयोक्ता की बिक्री संबंधी पूछताछ का उत्तर देने के बजाए अपने व्यापारियों को उत्तर देने का निर्देश देती है।

ज.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

57. प्राधिकारी विभिन्न आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं कि अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, एक आयातक/अंतिम प्रयोक्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना नहीं दी गई है और यह कि जांच की शुरूआत दोषपूर्ण थी क्योंकि प्राधिकारी के समक्ष आंकड़े साफ-साफ नहीं थे। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की शुरूआत प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध विभिन्न तथ्यों के आधार पर है जिनके लिए समुचित वैधता तथा विश्लेषण की अपेक्षा है जिसमें कुछ मामलों में सही एवं समान निर्णय पर पहुँचने के लिए जांच की शुरूआत के बाद की जांच अपेक्षित हो सकती है। जहां तक सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना उपलब्ध कराए जाने का संबंध है, प्राधिकारी ने कारणों के आधार पर तथा संगत पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकार्यता के आधार पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के दावों पर विचार करने की अपनी स्थापित परिपाठी को अपनाया है। अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक फाइल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं जो डीजीएडी में उनका निरीक्षण कर सकते हैं। उपर्युक्त याचिका और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अर्धन्यायिक जांच के कार्य ढांचे के मद्देनजर सूचना का अधिकार अधिनियम के मुद्दे को किसी और उत्तर की आवश्यकता नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना का उत्तर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित किए गए अनुसार निर्दिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा एक पृथक कार्यकारी प्रकार्य के रूप में दी जाती है जो इस मामले में भी किया गया था।

58. जहां तक उन मुद्दों की सूची प्रदान करने का संबंध है, जिन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी मौखिक सुनवाई में सुनना चाहेंगे, यह माना जाता है कि सभी हितबद्ध पक्षकार उस किसी मुद्दे पर मौखिक सुनवाई में निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सुनना वह संगत मानते हैं। यह परिपाठी निरंतर अपनाई गई है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार, जो मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लेना चाहता, के पास ऐसा करने का विकल्प है क्योंकि भाग लेना अनिवार्य नहीं है।

जांच की अवधि के बाद संभावना का विश्लेषण

59. पाटन एवं क्षति की संभावना:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	यूरोपीय संघ	ईरान	जापान
1.	सीएनवी (घरेलू उद्योग के सीओपी आंकड़े)	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***
2(a)	एक्स-ईपी	डॉलर/कि. ग्रा.	1.189	1.233	1.196
2 (b)	सीआईफ	डॉलर/कि. ग्रा.	1.339	1.325	1.129
3. पाटन मार्जिन	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***	***
	% रेंज	0 से 5	0 से माइनस 5	0 से 5	
4.	क्षति रहित कीमत	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***
5.	क्षति मार्जिन	डॉलर/कि. ग्रा.	***	***	***
6.	क्षति मार्जिन	% रेंज	माइनस 5 से माइनस 10	माइनस 5 से माइनस 10	माइनस 5 से माइनस 10

60. उत्पादकों/निर्यातिकों की अधिशेष क्षमता तथा भारतीय बाजार की आकर्षकता

प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास यूरोपीय संघ, ईरान और जापान में क्रमशः 450000 मी. टन, 20000 मी. टन और 90000 मी. टन की दावा की गई बाजार क्षमता है। यूरोपीय संघ की मेलामाइन की क्षमता का दावा 30 जून, 2017 के यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में सूचित किए गए आंकड़ों से मेल खाता है। वर्ष 2015-16 में जांच परिणाम में सूचित किए गए अनुसार, क्षमता उपयोग लगभग 78 प्रतिशत है। विश्व व्यापार मानचित्र के आंकड़ों के अनुसार, ईरान और जापान के संबंध में 10000 मी. टन और 49000 मी. टन तक के उच्चतम वैश्विक निर्यात प्रमाणित हैं। यह तथ्य कि जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में क्षति मार्जिन नकारात्मक है, तथा ये भी कि जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि में पाटन मार्जिन काफी नहीं है, इनसे व्यापार को भारत में ले जाने की संभावना होना प्रतीत नहीं होता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि देश में मेलामाइन की वार्षिक मांग लगभग 70000 मी. टन है और यहां तक कि घरेलू उद्योग की क्षमता अभिवृद्धि से मांग एवं आपूर्ति का अंतर आयातों से पूरा किए जाने की आवश्यकता है। आकर्षकता की अपेक्षा यह अंतराल वस्तुतः मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि जांच की अवधि के बाद की अवधि में क्षति मार्जिन को एक संभावना के संकेत के रूप में लिया जाता है तो वह भी नकारात्मक है, जैसा कि जांच की अवधि के दौरान का मामला भी है।

61. जहां तक इंडोनेशिया से आयात का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया उत्पादकों/निर्यातिकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं और इंडोनेशिया से आयात क्षति की अवधि, जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में शून्य हैं। अतः इंडोनेशिया से आयातों पर पाटनरोधी उपाय अनौचित्यपूर्ण होने माने जाते हैं तथा और आगे जारी रखने की आवश्यकता भी नहीं है।

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां62. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- यह प्रकटन विवरण एक पक्षकार अर्थात् मैसर्स संदीप अर्गेनिक्स प्रा. लि. द्वारा किए गए अनुरोधों और उसकी प्रतिभागिता के संबंध में है। तथापि, उपर्युक्त पक्षकार ने कोई भी अनुरोध सार्वजनिक फाइल में अब तक नहीं रखे हैं और याचिकार्कर्ता वर्तमान प्रकटन की प्राप्ति तक ऐसी किसी प्रतिभागिता से अवगत नहीं है। आरंभ में हम उपर्युक्त पक्षकार के सभी दावों को औचित्यपूर्ण न होने के निमित्त नकारते हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व में दिए गए उत्तर पत्र भी ऐसे आयातक द्वारा किए गए अनुरोध से संबंधित हैं।
- निर्धारित एनआईपी भी पूर्णतः स्थिति नहीं दर्शाती तथा अनुचित रूप से कम है जिसकी पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के साथ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित मेलामाइन के लिए प्रस्तावित एनआईपी के ब्यौरे बताए हैं। हमारे रिकार्ड में उनकी जांच करने के बाद यह महसूस किया गया है कि प्रस्तावित एनआईपी अनुचित रूप से कम है तथा कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद की लागत के संगत तथ्यों और अपनाए गए कुछ सिद्धांतों को न मानते हुए निर्धारित की गई है जिसे प्राधिकारी द्वारा स्वयं पिछली परिपाटी के अनुरूप नहीं समझा गया है। हम परिकलन में निम्नलिखित विसंगतियां देख सकते हैं तथा प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए उसको ध्यान में रखें।
- हमें बताई गई एनआईपी के परिकलन के अनुसार, मेलामाइन के लिए परिकलित कार्यशील पूंजी *** लाख रुपए है। हमारे परिकलन के अनुसार, जो हमारी समझ में है, एक सतत परिपाटी के रूप में कार्यशील पूंजी का परिकलन करने के लिए डीजीएडी द्वारा अपनाए गए सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके आंकड़े *** लाख रुपए निकलते हैं जिसके लिए विस्तृत परिकलन संलग्न है। यह अनुरोध है कि आंकड़ों को अनुचित रूप से अस्वीकार करने से बहुत कम एनआईपी हुई है जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है और जिससे हमारे वैध हितों को गंभीर क्षति होगी। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इसे पुनः देखें।
- अमोनिया के व्यवहार के संबंध में हमारी गंभीर चिंताएँ हैं जो कि मेलामाइन का उत्पादन करते समय उप उत्पाद के रूप में तैयार किया जाता है। स्थल सत्यापन के दौरान डीजीएडी के दल को यह स्पष्ट किया गया था कि अमोनिया, जो मेलामाइन का उत्पादन करते समय उप उत्पाद के रूप में निकलता है, वापस अमोनिया संयंत्र में जाता है। उसे औद्योगिक उत्पाद में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें बहुत ही अधिक अंतर्निहित गैस की मात्रा *** प्रतिशत होती है।

- चूंकि मेलामाइन के उत्पादन के समय उप उत्पाद के रूप में अमोनिया सृजित होता है, जिसका प्रयोग उपर्युक्त शुद्धता के मुद्दे के कारण मेलामाइन के संयंत्र में नहीं किया जा सकता, अतः प्राधिकारी को उसे उसी लागत तथा लागत/अमोनिया की कीमत पर नहीं मानना चाहिए जिसका प्रयोग मेलामाइन के लिए किया जाता है। इससे कंपनी द्वारा उत्पादित मेलामाइन की अंतिम रूप से कम लागत निर्धारित हुई है। उप उत्पाद के रूप में सृजित अमोनिया की उपर्युक्त स्थिति को समुचित रूप से दिए जाने की आवश्यकता है और उप उत्पाद अमोनिया को अन्य अमोनिया के समान मानना तकनीकी रूप से भी सही नहीं है।
- हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कंपनी द्वारा उत्पादित मेलामाइन के लिए लागत एवं एनआईपी का भी निर्धारण करते समय उप उत्पाद के रूप में सृजित अमोनिया को मानने की पुनः जांच करें। हम प्राधिकारी के प्रति इस बात के लिए आभारी होंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि एनआईपी के निर्धारण में जीएसएफसी के साथ कोई अन्याय न किया जाए ताकि अंतिम जांच परिणाम में सही परिणाम सुनिश्चित हों।
- प्रकट किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों से घरेलू उद्योग को क्षति एवं पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है।
- पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 में एक जांच के लिए प्रावधान है कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति तथा पाटन जारी रखने तथा बार-बार होने की संभावना है। यह नियम इस प्रकार शुल्क की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन एवं क्षति की किसी संभावित स्थिति को पूर्णतः जानने की अपेक्षा रखता है जहां यह भी मानता है कि पाटन एवं क्षति की स्थिति लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप कम होनी चाहिए। इस प्रकार, ऐसी संभावना के कम से कम अवसर से शुल्क जारी रहेंगे और वर्तमान मामले में निम्नलिखित तथ्य यह दर्शाते हैं कि वर्तमान मामले में मौजूदा शुल्क जारी रखना क्यों अनिवार्य है।
- संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के विरुद्ध लागू शुल्कों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार आया है। तथापि, घरेलू उद्योग फिर भी इंडोनेशिया को छोड़कर संबद्ध देशों से ऐसे आयातों के क्षति कारक प्रभाव के लिए सुभेद्र है। ये आयात उस कीमत पर भारतीय बाजार में भी पहुँच गए हैं, जिनसे मौजूदा शुल्कों के अभाव में घरेलू उद्योग का निष्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है जो कि संबद्ध देशों से आयातों की स्थिति में सकारात्मक कीमत कटौती से सिद्ध है। इस तर्क कि ये आयात मांग एवं आपूर्ति के अंतराल के कारण आवश्यक हो गए थे, में कोई अच्छा कानूनी एवं वास्तविक आधार नहीं है क्योंकि इस योजना की आवश्यकता एवं प्रयोजन घरेलू उद्योग की दी गई स्थिति में घरेलू उत्पादन एवं आयातों के बीच सही भूमिका सुनिश्चित करना है और सम्पूर्ण भारतीय मांग को पूरा करना घरेलू उद्योग के परिप्रेक्ष्य से बाजार में सही कार्य के लिए पूर्वापेक्षा नहीं हो सकती।
- पाटित आयात संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में चलते आ रहे हैं और उनका बाजार में मुक्त रूप से प्रवाह लागू शुल्कों से ही रुका है। वर्तमान शुल्क की समाप्ति से बढ़े हुए स्तर पर ऐसे पाटित आयातों के लिए एक पुनः प्रवेश की मद बन जाएगी।
- प्रकटन विवरण यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन (भारतीय लागत पर सामान्य मूल्य आधारित) यूरोपीय संघ और जापान से आयातों की स्थिति में सकारात्मक रहा है तथा वह सामान्य मूल्य के आधार पर यूरोपीय संघ के मामले में गौण आधार पर सकारात्मक रहा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुल्कों के बाद भी यूरोपीय संघ से पाटन एक आक्रामक तरीके से जारी रहा और जापान, इंडोनेशिया और ईरान से आयातों पर शुल्क के कम प्रभाव रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में वर्तमान शुल्कों की स्थिति में पाटन की संभावना आसन्न है, जैसा कि नियम में परिकल्पित है।
- जांच की अवधि के बाद की अवधि में निर्धारित पाटन मार्जिन भी यूरोपीय संघ और जापान के मामले में सकारात्मक पाटन मार्जिन दर्शाता है। यह तथ्य यह भी सिद्ध करता है कि यह कहने के लिए कोई वास्तविक आधार नहीं है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पुनः पाटन नहीं होंगे। पाटन जारी रहा और जारी है। इस प्रकार, उसका सामना करने के लिए शुल्क अनिवार्य हैं।
- प्रकटन विवरण जांच की अवधि में यूरोपीय संघ से आयातों के मामले में सकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाता है और अन्य संबद्ध देशों के मामले में नकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाता है। सभी संबद्ध देशों के मामले में क्षति मार्जिन जांच की अवधि के बाद की अवधि में नकारात्मक दिया गया है। हमारा अनुरोध है कि ऐसे नकारात्मक मार्जिन की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमने ऊपर यहां यह अनुरोध किया है कि निर्धारित एनआईपी उसके निर्धारण के लिए तथ्यों को पूर्णतः नहीं दर्शाता है जिसको पुनः माने जाने की आवश्यकता है। पूर्वाग्रह के बिना यह हमारा अनुरोध है कि नकारात्मक क्षति मार्जिन को इस कारण से

क्षति की संभावना निर्धारित करने के लिए मानदंड के रूप में नहीं देखा जा सकता कि लागू पाटनरोधी शुल्क से घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और इस प्रकार हुई क्षति पर शुल्कों के ऐसे कम प्रभाव क्षति मार्जिन में दर्शाए जाने चाहिए। शुल्कों से घरेलू उद्योग को सामान्य रूप में और दक्षतापूर्वक प्रचालन करने में मदद मिली है तथा उसे क्षति मार्जिन की स्थिति में दर्शाया जाना होगा, परंतु तथ्य यह है कि यह नकारात्मक क्षति मार्जिन लागू शुल्कों का परिणाम है और उपर्युक्त शुल्कों की समाप्ति से समग्र क्षति एवं सकारात्मक क्षति मार्जिन की स्थिति एक बार पुनः बनेगी।

- संबद्ध देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ से संभावित नियर्यातों के तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शते हैं कि उस तरीके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसमें नियर्यात भारत में किए गए थे और प्रयोक्ता ऐसे स्रोतों से पाटित कीमतों पर सामग्री आयात करने के लिए अब भी अत्यधिक इच्छुक हैं तथा यूरोपीय संघ जैसे स्रोत ने पाटित एवं यहां तक कि अधिक हानिकारक कीमतों पर मेलामाइन देने के लिए उपयोग न की गई काफी क्षमताएं हैं।
- यह भी नोट किए जाने की आवश्यकता है कि कोई भी नियर्यातिक प्राधिकारी के समक्ष नहीं आया। प्राधिकारी ने तीसरे देशों आदि से उनके नियर्यातों की विस्तृत जांच करने के लिए उसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे मामले में शेष सुविधा किसी संभावना को नकारने के लिए नहीं होनी चाहिए, परंतु उसका उपयोग ऐसे पक्षकारों के विरुद्ध किया जाना चाहिए जो भाग न लेने का विकल्प चुनते हैं।
- प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की अतिरिक्त क्षमता के लिए कार्य क्षेत्र, जब भी वह बने, उस समय और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, मौजूद परिस्थितियों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा विचार मिलाया जा सकता है। हम इस विचार पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना करते हैं कि क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक निवेश पहले ही घरेलू उद्योग द्वारा किए जाते हैं और नई क्षमता में उत्पादन अब से कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा। यह वह मामला नहीं है जिसमें घरेलू उद्योग भावी निवेश के लिए संरक्षण की मांग कर रहा है, परंतु उसकी चिंता स्पष्ट रूप से पहले से ही किए गए निवेशों के संबंध में है और ऐसे निवेश संबंधी निर्णय इस पूर्वानुमान के आधार पर थे कि बाजार में अच्छा कार्य जारी रहेगा तथा हम विश्वास करते हैं कि वर्तमान शुल्कों के अभाव में अच्छा कार्य समाप्त हो जाएगा। पूर्ण की जा रही परियोजना की अर्थक्षमता मेलामाइन के लिए बाजार में सही कीमत पर निर्भर करती है तथा ऐसे कीमतें प्राप्त करना तब संभव नहीं है, यदि व्यापक नियर्यात करने वाले देश यथा यूरोपीय संघ, जापान और ईरान आदि को शुल्कों के बिना छोड़ दिया गया। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2015 और 2016 के दौरान भारत को ईरान से नियर्यात क्रमशः 9140 मी. टन और 5516 मी. टन की मात्रा तक 1.35 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो ग्राम की औसत कीमत पर थे। भारत को अधिक कीमत लागू मौजूदा शुल्कों के कारण स्पष्ट रूप से हैं और नए स्तरों में ऐसी पाटित कीमतों में गिरावट आसन्न है। पाटनरोधी शुल्क की स्थिति में ईरान की नियर्यात कीमत में गिरावट इस प्रकार आसन्न है। ऐसी भी संभावना है कि नियर्यातिक भारत में एक बार नई क्षमता प्रचालनात्मक होने पर बाजार में बने रहने के लिए अपनी कीमतें काफी कम कर देंगे और कम अवधि के लिए भी ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को अपूर्णीय क्षतियां हो सकती हैं। पाटनरोधी नियम इस प्राधिकारी को अधिकार करते हैं कि वे संभावित क्षति की स्थिति पर ध्यान दें और इससे प्राधिकारी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे पहले नुकसान होने वें और फिर बाद में हल की ओर देखें। हम प्रार्थना करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पहले ही निवेश कर दिए हैं जिन्हें समुचित रूप से देखे जाने की आवश्यकता है और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे क्षमता अभिवृद्धि के पहलू के संबंध में अपने विचार पर पुनः विचार करें।
- प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है कि संबद्ध देशों से आयात कीमतों की प्रवृत्ति संबद्ध देशों से उत्पादकों/नियर्यातिकों की कीमत संवृद्धि नीति के कारण ही नहीं हो सकती, अपितु उसके कतर से आयात कीमतों से प्रभावित होने की भी आशा है जो कि व्यापक रूप से जीएसएफसी द्वारा किए गए थे। हमारा अनुरोध है कि प्राधिकारी की टिप्पणी पर इस तथ्य के मद्देनजर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है कि यह टिप्पणी संभावित जांच के संदर्भ में पूर्ण नहीं है। जीएसएफसी का ध्यान हमेशा अपने संयंत्र में सामानों का उत्पादन करने पर है और उसकी संबद्ध सामानों का आयात तथा विक्री सामान्य एवं लाभरहित कीमत पर करने में कोई रुचि नहीं है। कतर से आयात मांग एवं आपूर्ति के अंतराल में उसका आधार था और कंपनी ने यह कार्य अपना ग्राहक आधार बनाए रखने, विशेष रूप से ऐसे समय पर किया जब नया संयंत्र सक्रिय होने के लिए लगभग तैयार है। नई क्षमता में एक बार उत्पादन आरंभ हो जाए तो कतर से आयात जीएसएफसी द्वारा शून्य हो जाएंगे। कतर से जांच की अवधि के दौरान किए गए आयातों की कीमत से घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसा कि क्षति संबंधी आंकड़ों से देखा जा सकता है और जीएसएफसी द्वारा ऐसे आयातों का संभावित प्रभाव स्वतः भी शून्य है क्योंकि नई लाइन में उत्पादन आरंभ होने के बाद जीएसएफसी द्वारा इस प्रकार के कोई आयात नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार, संबद्ध देशों से उत्पादकों/नियर्यातिकों की कीमत संवृद्धि नीति का आधार जो बन रहा है, वह जीएसएफसी द्वारा आयात नहीं है बल्कि जीएसएफसी द्वारा निश्चित रूप से क्षमता अभिवृद्धि है जो अकेले ही वर्तमान मामले में पाटन एवं क्षति की संभावना सिद्ध करता है। नियर्यातिकों को जीएसएफसी को

वर्तमान क्षमता के शीर्ष पर अपने संयंत्र से उत्पादित मेलामाइन की विक्री करने से रोकने के लिए अपनी कीमतें कम करनी होंगी तथा कीमतों में इस कमी से आगे पाठन एवं क्षति होगी।

- ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने यह मानने का विचार बनाया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंड स्थिर हैं और संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति होना प्रतीत नहीं होता तथा यह तथ्य कि कतर से आयात घरेलू उद्योग द्वारा समान कीमतों पर किए गए हैं, यह दर्शाता है कि ये आयात कीमतें क्षति रहित हैं और जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि दोनों के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन इस पहलू को और भी सिद्ध करता है।
- हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इन टिप्पणियों में किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए इस प्रस्तावित दृष्टिकोण की पुष्टि न करें कतर से आयातों के तथ्य को एक बार पुनः दोहराया जाता है तथा कतर से आयातों के तथ्यों को ऐसी कमियों में देखे जाने की आवश्यकता है। निर्यातिक अपनी कीमत का निर्धारण लागू शुल्क के आधार पर कर रहे हैं तथा किसी भी रूप में ये शुल्क हटाए जाने से संबद्ध देशों से कीमत में गिरावट आएगी। जीएसएफसी द्वारा कतर से आयातों ने कीमत पर प्रभाव नहीं डाला क्योंकि ऐसे आयातों ने जीएसएफसी पर कोई कीमत संबंधी दबाव नहीं बनाया, परंतु संबद्ध देशों से निर्यातिकों द्वारा पेश की गई कीमतें, लागू शुल्कों से संचालित होती हैं और ऐसी कीमतों में इस कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया कि पाटनरोधी शुल्क लागू हैं। साथ ही, क्षति मार्जिन के दृष्टिकोण पर निर्धारित एनआईपी में वास्तविक अपर्याप्तियों के मद्देनजर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, चीन जन गण पर शुल्क हैं तथा यूरोपीय संघ ने भी चीन जन गण से यूरोपीय संघ में मेलामाइन के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया है। वर्तमान शुल्क की समाप्ति से केवल यूरोपीय संघ से निर्यात बढ़ेंगे क्योंकि वे भारत में उत्पादन में आने वाले नई क्षमताओं के अलावा चीन जन गण के बाजार को लेने का भी प्रयास करेंगे। इस प्रकार, कतर से आयात कोई निर्धारित कारक नहीं है, परंतु यूरोपीय संघ से निर्यात सीधे ही वर्तमान शुल्कों की मौजूदगी अथवा समाप्ति से जुड़े हैं और शुल्क की समाप्ति की स्थिति में बाजार एक बार पुनः यूरोपीय संघ से पाठित आयातों के कारण ले लिया जाएगा जो बहुत ही कम समय में घरेलू उद्योग की स्थिति को विघटित कर देगा।
- हमारा यह सुविचारित अनुरोध है कि इस अवधि में घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाठित आयातों के कारण हुई क्षति वसूल की है और यदि इन स्रोतों के विरुद्ध लागू उपाय समाप्त करने की अनुमति दी जाती तो यह संभावना है कि क्षति बार-बार होती क्योंकि घरेलू उद्योग इन पाठित आयातों से कीमत के काफी दबाव में आ जाता। शुल्क समाप्त करने से कीमतें भी कम होंगी और संभवतः पाठित आयात भी बढ़ते तथा कोई तिलमात्र तथ्य भी नहीं है जो यह दर्शाए कि निर्यात की स्थिति शुल्क समाप्ति के बाद भी बनी रहेगी तथा घरेलू उद्योग की स्थिति स्थिर बनी रहेगी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थिति केवल बिगड़ेगी तथा यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग फिर भी स्थिर स्थिति में होगा।
- साथ ही, चीन जन गण से मेलामाइन के आयात के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णयित समीक्षा के मामले में यूरोपीय संघ ने यह पाया कि ऐसी संभावना है कि यूनियन बाजार में चीनी आयातों का कम कीमत पर आने से तत्काल ही कीमतें कम हो जाएंगी, यदि उपाय समाप्त करने की अनुमति दे दी जाए।
- मेलमाइन की कीमत भारतीय बाजार में भी एक संवेदनशील मुद्दा रहता है। एक भी कारक ऐसा नहीं है जो यह बताए कि संबद्ध देशों से निर्यातिक शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत में और अधिक बाजार हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें कम नहीं करेंगी और घरेलू उद्योग ऐसे कम कीमत वाले आयातों पर भी काफी कीमतें प्राप्त करने में सक्षम होगा। मेलमाइन की कीमत संवेदनशीलता यूरोपीय आयोग जैसे पाटनरोधी प्राधिकारी द्वारा कुछ स्वीकार की गई है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यूरोपीय संघ जैसे निर्यातोन्मुख संबद्ध देशों से उत्पादक/निर्यातिक घरेलू उद्योग तथा अन्य निर्यातिकों देशों की अपनी नियर्यातोन्मुखता तथा अतिरिक्त क्षमता के कारण अधिक बाजार प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें कम नहीं करेंगे। ऐसे परिदृश्य में घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होगा और प्रकटन विवरण में कोई भी तथ्य यह नहीं दर्शाता है कि आयात कीमतें कम नहीं होंगी तथा घरेलू उद्योग प्रतिकूल आयात कीमतों की स्थिति में अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर नहीं होगा। यह बहुत ही स्पष्ट है कि यदि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करनी पड़ीं तो क्षति निश्चित ही बहुत आसन्न है।
- प्राधिकारी द्वारा यह भी पाया गया है कि भारत में क्षमता विस्तार के बाद भी आयातों की आवश्यकता हुई। इस संबंध में वास्तविक तथ्य यह है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो ऐसे आवश्यक आयातों के प्रतिकूल प्रभाव इतने गंभीर होंगे कि बाजार में कीमत प्रतिकूलताएं होंगी। उसका कारण यह है कि यूरोपीय संघ जैसे देशों में अनुमानित अतिरिक्त क्षमता अकेले ही भारतीय मांग की अपेक्षा काफी अधिक है और निर्यातिक भारत में ऐसी छोड़ी गई मांग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा करेंगे जो प्रयोक्ताओं को इन पाठित स्रोतों की ओर आकर्षित करेंगे तथा घरेलू उद्योग अपनी अच्छी

कीमतें बनाए रखने की स्थिति में नहीं होगा। शुल्क जारी रखना, जो कि पाटन के हासमान प्रभावों को समाप्त करने के लिए एक उचित मार्जिन के सिवाय कुछ नहीं है, घरेलू उद्योग के लिए और साथ ही समान रूप से प्रयोक्ताओं के लिए लाभकारी होगा।

- यह अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विगत में पाटन के क्षतिकारक प्रभाव से उभरने के लिए घरेलू उद्योग को सहायता मिली है। क्षति संबंधी मानदंडों ने स्थिति अच्छी होना दर्शाया है, तथापि, पाटित दरों पर काफी आयात हुए हैं जो यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग एक बार फिर पाटन एवं क्षति के लिए अत्यधिक सुभेद्य है।
- वर्तमान पाटन दर्शाता है कि यह अत्यधिक संभावना है कि पाटन जारी रहेगा और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में गहन होगा। इसके अतिरिक्त, जीएसएफसी ने यह दर्शाया है कि संबद्ध देशों में संबंधित उत्पाद के उत्पादकों के पास काफी अधिशेष क्षमताएं हैं और ये उत्पादक एवं निर्यातक काफी नियर्तोन्मुख हैं तथा भारत एक संभावित तथा आकर्षक बाजार बना रहता है कि ऐसे आयातों से पाटन एवं क्षति संबद्ध देशों से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संभव है। परिकलित एनआईपी की पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वह काफी कम सूचित किया गया है और बहुत ही कम है तथा यह कि यह सिद्ध है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति से घरेलू उद्योग ने पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करें।

आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों/अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

63. मैसर्सी सीतारमण एसोसिएट का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्सी एक्जिम कॉर्प

- हम इन टिप्पणियों का स्वागत करते हैं कि प्राधिकारी का यह मानने का विचार है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंड स्थिर हैं और संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति होना प्रतीत नहीं होता। यह तथ्य कि कतर से आयात घरेलू उद्योग द्वारा समान कीमतों पर किए गए हैं, यह दर्शाता है कि ये आयात कीमतें क्षतिकारक नहीं हैं। जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन भी इस पहलू को सिद्ध करता है। हम डीजीएडी से अनुरोध करते हैं कि वे इन टिप्पणियों को अपने तर्कसंगत निष्कर्ष में दें और कोई उपाय लगाए बिना जांच को समाप्त करें।
- इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त टिप्पणियां दो महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में डीजीएडी से कतिपय आकस्मिक जांच परिणाम की मांग करती हैं, अर्थात् जीएसएफसी घरेलू उद्योग के लिए योग्य नहीं हैं; और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से संबंध रखे बिना निर्णायिक समीक्षा की शुरूआत स्वतः नहीं होगी और प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे इन दो मुद्दों के संबंध में विशिष्ट जांच परिणाम दें।
- हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे इस संबंध में भी जांच परिणाम दें कि घरेलू उद्योग ने क्षति रहित कीमत कैसे प्रस्तावित की थी और यह कि उपर्युक्त कीमत पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निहित कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती।

64. मैसर्सी अग्रवाल केमिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्सी इंटरनेशनल ट्रेड रेमिडीज एंड ऐक्टिव्स

- प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि नियम 2(ब) के प्रावधानों में कि पाटित आयातों के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की जांच किए जाने की अपेक्षा है जो केवल संबद्ध देशों के संबंध में ऐसी जांच तक सीमित है। "यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग द्वारा लिया गया नियम 2(ब) का निर्वचन प्रतिबंधात्मक है। यदि कानून का प्रारूप बनाने वालों का इरादा यह होता कि घरेलू उत्पादकों के आयातों की जांच संबद्ध देशों के लिए ही की जानी है तो वे "पाटित वस्तु" शब्दों के स्थान पर "संबद्ध देश (देशों)" शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग करते।"
- वर्तमान जांच में निष्कर्ष का आधार बनाने वाले कतर के आयातों की जांच और प्रयोग इस तथ्य को सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की जांच संबद्ध देशों तक प्रतिबंधित नहीं की जा सकती, परंतु अन्य देशों के लिए भी जांच किए जाने की अपेक्षा है। अतः घरेलू उद्योग द्वारा जांच की अवधि में 40 प्रतिशत तक काफी आयात के मद्देनजर वर्तमान जांच पहले स्थान पर शुरू नहीं की जा सकती थी, यदि आयातों की पूर्ण सूचना जांच की शुरूआत से पूर्व दी गई होती क्योंकि इतनी अधिक मात्रा के घरेलू उद्योग द्वारा आयात इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि घरेलू उद्योग पर आयातों के संबंध में बहुत ज्यादा विश्वास किया जा रहा है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग वर्तमान जांच में आधार नहीं रखता।

- संबद्ध देशों अर्थात् यूरोपीय संघ, ईरान और जापान के लिए सीएनवी के निर्धारण हेतु तथ्य एवं सिद्धांत को मिलाया गया है और स्पष्ट रूप से नहीं समझे जाते हैं। हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया उन्हें अंतिम जांच परिणाम में उपयुक्त रूप से स्पष्ट करें। पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध है कि हम सीएनवी के लिए घरेलू उद्योग की लागत का प्रयोग करने का तर्क समझने की स्थिति में नहीं है। यह देखा जा सकता है कि सीएनवी के निर्धारण के लिए अपनाई गई परिपाटी के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर कहीं सामग्री की लागत के लिए समायोजित की जाती है और इसमें कहीं सामग्री के सर्वोत्तम खपत मानक अपनाए गए हैं। यह भी देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत वर्तमान जांच में प्रयुक्त किए जाने के लिए न हो क्योंकि संबद्ध सामानों की लागत वर्ष 2015-16 के लिए यूरोपीय संघ के जांच परिणामों से उपलब्ध है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत की तुलना में अधिक विश्वसनीय और अधिकृत है तथा उसे 2016-17 के लिए, घरेलू उद्योग की सूचना से यूरिया के खपत मानदंड और 5 प्रतिशत लाभ की दर से, यूरिया की कहीं सामग्री की कीमतों के लिए समायोजित किया जाए। अतः हम माननीय प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे सीएनवी के लिए घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना का उपयोग न करें। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि यूरोपीय संघ के जांच परिणामों से 2015-16 के लिए यूरोपीय संघ की घरेलू कीमतों के आधार पर जांच की अवधि 2016-17 के लिए सीएनवी 2015-16 की तुलना में 2016-17 में आईसीएसएलओआर में मेलामाइन की स्थल कीमतों के बीच अंतर के लिए उन्हें समायोजित करने के बाद निम्नलिखित के मद्देनजर उपयोग में न लाया जाएः

(क) यह स्पष्ट नहीं है कि क्या 2015-16 और 2016-17 के लिए यूरोपीय संघ द्वारा डब्ल्यूटीए से वैश्विक कीमतों के बीच अंतर अथवा यूरोपीय संघ में स्थल कीमतों पर विचार करते हुए 2015-16 के लिए यूरोपीय संघ की कीमतों में समायोजन 2015-16 और 2016-17 के लिए आईसीएसएलओआर कीमत के बीच अंतर के आधार पर किया गया है। यह अनुरोध है कि उपर्युक्त दो आधारों में से किसी भी आधार पर सीएनवी का निर्धारण सही नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यूरोपीय संघ के जांच परिणामों अथवा आईसीएसएलओआर में सूचित की गई कीमतें व्यापारियों/उत्पादकों की हैं, क्या इसमें कोई क्रृण अवधि शामिल हैं, क्या कीमतें कारखानागत स्तर पर अथवा व्यापार के किसी अन्य स्तर पर हैं और क्या वे व्यापार की सामान्य अवधि में हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त, हमारी सूचना के अनुसार आईसीएसएलओआर में सूचित की गई कीमतें पूरे यूरोप के लिए हैं न कि केवल यूरोपीय संघ के लिए। यह देखा जा सकता है कि यूरोप ने भी कई अन्य देशों को शामिल किया है जो यूरोपीय संघ के भाग नहीं हैं। अतः अकेले यूरोपीय संघ के लिए इस महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में, यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में सूचित और जांच की अवधि के लिए आईसीएसएलओआर की कीमतों के लिए समायोजित यूरोपीय संघ की कीमतों को यूरोपीय संघ तथा ईरान और जापान के लिए सीएनवी हेतु नहीं माना जा सकता। माननीय सेसेट ने डाई स्टफ मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार 2003 (157) ईएलटी 154 (ट्रि. - डेल.) के मामले में अपने आदेश में भी यह माना है कि संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य अपूर्ण सूचना के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ख) स्थल कीमतें हमेशा वस्तुतः संविदागत कीमतों से अधिक होती हैं और इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यूरोपीय संघ में कीमतें स्थल आधार पर हैं। यह देखा जा सकता है कि घरेलू बाजार में कीमतें सामान्यतः संविदागत कीमतें होती हैं।

(ग) यूरोपीय संघ के लिए सीएनवी का परिकलन करने की सर्वोत्तम पद्धति यूरोपीय जांच परिणामों में प्रकट की गई मेलामाइन की लागत का उपयोग करना है और उसे 2017-18 के लिए यूरिया की कीमतों के लिए विधिवत समायोजित करना है। मूल जांच में भी सीएनवी का निर्धारण यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, अन्य लागत और 5 प्रतिशत की दर से लाभ के आधार पर किया गया था। ईरान और जापान के लिए भी सीएनवी का निर्धारण कहीं सामग्री यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों अथवा डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों और उपर्युक्त यूरोपीय संघ के जांच परिणामों से अन्य लागतों तथा 5 प्रतिशत की दर से लाभ के आधार पर किया जाए। हम वर्तमान जांच में सिद्धांत में परिवर्तन को नहीं समझ पा रहे हैं। उपर्युक्त आधार पर यूरोपीय संघ के लिए सीएनवी के ब्यौरे तथा साक्ष्य हमारे प्रत्युत्तर अनुरोधों के भाग के रूप में पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

- यूरोपीय आयोग के लागत आंकड़ों और 5 प्रतिशत लाभ के रूप में तुलना करके सीएनवी 1045 डॉलर मी. टन बनता है। हमारे द्वारा परिकलित यूरोपीय संघ के लिए सीएनवी ईरान और जापान को भी किया जाए।
- हम जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए सीएनवी हेतु संबद्ध देशों की तीसरे देशों की कीमतों का प्रयोग करने के लिए प्रकटन विवरण के पैरा 20 की विषय वस्तु का तर्क एवं आधार भी नहीं समझ पाए हैं। तथापि, जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए तीसरे देशों की कीमतों के आधार पर सीएनवी के कोई ब्यौरे वर्तमान

जांच में प्रकट नहीं किए गए हैं। यह भी देखा जा सकता है कि तीसरे देशों की कीमतों पर विश्वास करने से पूर्व उन्हें ओसीटी परीक्षण पास करने की अपेक्षा होती है जिसे पुनः संबद्ध सामानों की लागत के अभाव में नहीं लाया जा सकता। अतः हम यूरोपीय संघ के लागतों और अंतर्राष्ट्रीय कम्बी सामग्री कीमतों तथा 5 प्रतिशत की दर से लाभ के आधार पर सीएनवी के निर्धारण का अनुरोध करते हैं।

- प्रकटन विवरण में ईरान और जापान के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में भी कोई व्यौरे नहीं हैं। हम माननीय प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणाम में उसके प्रकटन का अनुरोध करते हैं। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि ईरान और जापान के लिए भी सामान्य मूल्य अंतर्राष्ट्रीय यूरिया कीमतों, यूरोपीय संघ से अन्य लागतों और 5 प्रतिशत की दर से लाभ के आधार पर निर्मित किया जाए।
- प्रकटन विवरण के पैरा 21-13 में यूरोपीय संघ, ईरान और जापान की कारखानागत निर्यात कीमत के निर्धारण के व्यौरे प्रकट कर दिए गए हैं। यह अनुरोध है कि यूरोपीय संघ के लिए समुद्री भाड़े के समायोजन, सीआईएफ कीमतों से किए जाने वाले प्रस्तावित समुद्री बीमा अधिक प्रतीत होता है और ऋण लागत के लिए कोई समायोजन न किया जाए।
- एक्स-ईपी के परिकलन में कुछ त्रुटि प्रतीत होती है जिसकी जांच की जाए और जांच की अवधि के बाद की अवधि उल्लिखित की जाए।
- प्रकटन विवरण के पैरा 28 में यह रिकार्ड किया गया है कि जांच की अवधि में और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए एनआईपी परिकलित की गई है। तथापि, विशिष्ट अवधि, जिसके लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए एनआईपी निर्धारित की गई है, प्रकट नहीं की गई है। हम अंतिम जांच परिणाम में जांच की अवधि के बाद की अवधि को प्रकट करने का अनुरोध करते हैं।
- प्रकटन विवरण के पैरा 32 में यह रिकार्ड किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद कम हुए हैं और यह कि उनका हिस्सा भी कम हुआ है। अनुरोध है कि जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष 2013-14 में आयातों की तुलना में आंशिक रूप से कम हुए हैं। अतः संबद्ध देशों से आयात कुल मिलाकर आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में समान स्तर पर हैं।
- जांच की अवधि के लिए कम कीमत पर विक्री के व्यौरे दिए गए हैं जो संबद्ध देशों के लिए काफी नकारात्मक हैं। तथापि, जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए पहुँच मूल्य, एनआईपी और कम कीमत पर विक्री के व्यौरे नहीं दिए गए हैं।
- हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अंतिम जांच परिणाम में यह भी रिकार्ड करें कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन के 40 प्रतिशत की सीमा तक आयातों पर अधिक विश्वास किया है, अतः क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में कोई विश्वेषण भ्रामक है तथा वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत असंगत है।
- लाभप्रदता, नकद प्रवाह और आरओआई के संबंध में हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया अंतिम जांच परिणामों में यह भी रिकार्ड करें कि क्षति संबंधी जांच की अवधि में इन कारकों में काफी सुधार है।
- प्राधिकारी जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए पाटन मार्जिन के निष्कर्ष के संबंध में व्यौरे अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड करें।
- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह सही-सही रिकार्ड किया है कि भावी उत्पादों की योजना, जो अभी आनी है, का संरक्षण आगे चलते रहने वाले निर्णयिक समीक्षा में हल नहीं किया जा सकता जिसमें मौजूदा विनिर्माण आधार को क्षति की संभावना संबंधी मूल्यांकन की जांच किए जाने की आवश्यकता है। घरेलू उद्योग की अतिरिक्त क्षमता, जब भी वह आए, के लिए अच्छे कार्य का क्षेत्र उस समय मौजूद परिस्थितियों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नहीं माना जा सकता।
- प्रकटन विवरण में यह उल्लेख है कि जीएसएफसी द्वारा आयात मात्रा और कीमतों के व्यौरे दिए गए हैं। चूंकि, यह महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त सूचना जान बूझकर घरेलू उद्योग द्वारा द्विपार्श्व गई थी और सही तरीके से वर्तमान जांच की शुरूआत से पूर्व आवेदन पत्र के भाग के रूप में नहीं दी गई थी, अतः वर्तमान जांच शुरू नहीं की जा सकती थी।

- प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह सही-सही रिकार्ड किया है कि यद्यपि कतर एक संबद्ध देश नहीं है, तथापि, जीएसएफसी द्वारा कतर से आयात देश में कीमतों की प्रवृत्ति निर्धारित करने वाला भी है, जिसे संबद्ध देशों से नियर्यातिक निःसन्देह निर्धारित करते। अतः संबद्ध देशों से आयातों कीमतों की प्रवृत्ति संबद्ध देशों से उत्पादकों/नियर्यातिकों की कीमत संबंधी नीति के कारण ही नहीं हो सकती, परंतु कतर से आयात कीमतों द्वारा प्रभावित होने की भी उम्मीद है जो कि जीएसएफसी द्वारा व्यापक रूप से किए गए थे।
- प्रकटन विवरण में यह रिकार्ड किया गया है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन मानदंड स्थिर हैं और संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति होना प्रतीत नहीं होता। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणामों में यह भी रिकार्ड करें कि क्षति की जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी सुधार हुआ है।
- प्रकटन विवरण में यह भी रिकार्ड किया गया है कि कतर से आयात घरेलू उद्योग द्वारा समान कीमतों पर किए गए हैं जो यह दर्शाता है कि वे आयात कीमतें क्षति रहित हैं और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान नकारात्मक क्षति मार्जिन इस पहलू को और भी सिद्ध करता है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया निष्कर्ष के भाग के रूप में अंतिम जांच परिणामों में रिकार्ड करें कि घरेलू उद्योग द्वारा कतर से आयातों की कीमतें संबद्ध देशों की कीमतों से काफी कम हैं। यह भी अनुरोध है कि जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में नकारात्मक क्षति मार्जिन दर्शाता है कि वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं है और न ही घरेलू उद्योग को कोई क्षति होने की संभावना है।
- यह देखा जा सकता है कि सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) तथा भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1च) के अनुसार, निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क तभी बढ़ाए जा सकते हैं जब घरेलू उद्योग यह सिद्ध कर दें कि पाटन एवं क्षति, दोनों के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है। शुल्क बढ़ाए नहीं जा सकते तथा दो स्थितियों में से किसी एक स्थिति में ही शुल्क वापस लिए जाने की अपेक्षा होती है अर्थात् पाटन की संभावना अथवा क्षति की संभावना, निर्णायक समीक्षा जांच में मौजूद न हों। यह अनुरोध है कि वर्तमान जांच में पाटन एवं क्षति, दोनों के जारी रहने अथवा बार-बार होने का अभाव है। अतः वर्तमान जांच में कृपया शुल्क हटा दिए जाएं।
- प्रकटन विवरण में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आधार पर पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन की संभावना संबंधी व्यौरे दिए गए हैं जिनका उल्लेख अंतिम जांच परिणाम में किया गया है। अनुरोध है कि जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए संबद्ध देशों के लिए सीएनवी घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित न किया जाए और सीएनवी यूरिया की कक्षी सामग्री कीमतों, यूरोपीय संघ के जांच परिणामों के आधार पर अन्य लागत और 5 प्रतिशत की दर से लाभ मार्जिन के आधार पर निर्धारित किया जाए। यह देखा जा सकता है कि मूल जांच में सामान्य मूल्य भी यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर निर्मित किया गया था। अतः हम जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए भी वर्तमान जांच में समान आधार पर सीएनवी निर्धारित किए जाने का अनुरोध करते हैं। यह दर्शाएँगा कि नकारात्मक पाटन मार्जिन है और शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन की कोई संभावना नहीं है। यहां तक कि प्रकट किए गए व्यौरों के आधार पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि पाटन मार्जिन काफी और नकारात्मक ही है। यह भी दर्शाता है कि शुल्कों के हटाए जाने की स्थिति में पाटन की कोई संभावना नहीं है।
- जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए संबद्ध देशों, यूरोपीय संघ, ईरान और जापान के लिए पहुँच मूल्य तथा सीआईएफ कीमतों के व्यौरे प्रकट नहीं किए गए हैं। हम अंतिम जांच परिणाम में उन्हें प्रकट किए जाने का अनुरोध करते हैं, जैसा कि जांच की अवधि के लिए वह प्रकट किए गए हैं। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे अंतिम जांच परिणाम में रिकार्ड करें कि चूंकि, प्रत्येक संबद्ध देश के लिए क्षति मार्जिन काफी नकारात्मक है, अतः शुल्क हटाए जाने की स्थिति में वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- अन्य बाजारों में संबद्ध सामानों के संबद्ध देशों की कीमतें भारतीय बाजार की अपेक्षा अधिक हैं, अतः उनके भारतीय बाजार में जाने की कोई संभावना नहीं है और शुल्कों की वापसी के बाद घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।
- हम प्राधिकारी से वर्तमान जांच को रद्द करने तथा शुल्क वापस लिए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं।

- घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी; प्रकटन विवरण के पैरा 13 में और क्षति के संबंध में पैरा 48 में उल्लिखित की गई है।
- उत्तरदाता हितबद्ध पक्षकार ने विश्लेषण में अनुरोध किए थे कि जांच की अवधि में तथा तीसरे देश में क्षति मार्जिन नकारात्मक है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के पैरा 60 में जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में क्षति मार्जिन नकारात्मक होने के संबंध में नोट किया है।
- प्रकटन विवरण के पैरा 61 में प्राधिकारी की टिप्पणी उल्लिखित की गई है।
- अन्य अनुरोध निम्नलिखित हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क जारी रहने का इस कारण कोई औचित्य नहीं है कि इस बात का अपर्याप्त साक्ष्य है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन एवं परिणामस्वरूप क्षति की संभावना है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत उस उचित कीमत से काफी अधिक है जिसकी जीएसएफसी द्वारा उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार, प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में वर्तमान अवधि में क्षति मार्जिन नकारात्मक हैं।

ग. पूरी क्षति अवधि में इंडोनेशिया से मेलामाइन का कोई आयात नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, याचिका में इंडोनेशिया से आयातों से क्षति के बार-बार होने की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत की घरेलू उद्योग की विक्री कीमत और घरेलू उद्योग की एनआईपी से तुलना स्पष्ट रूप से दर्शती हैं कि घरेलू उद्योग की विक्री कीमत आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और एनआईपी से निरंतर तथा काफी अधिक थी।

इ. यद्यपि जीएसएफसी द्वारा मूल्यांकित मांग 64086 मी. टन के क्षेत्र में है, तथापि जीएसएफसी के पास क्षमता केवल 15000 मी. टन है और क्षमताओं का विस्तार करने में जीएसएफसी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। आश्वासनों के बावजूद, जीएसएफसी मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के क्षमता विस्तार के तर्क पर विचार किया है और प्रकटन विवरण में माना है कि प्रस्तावित विस्तारों को आगे चलते रहने वाली पाटनरोधी जांच में चिंता नहीं माना जा सकता। यह अनुरोध है कि जब जीएसएफसी क्षमता विस्तार के लिए लगभग एक दशक पहले बाजार में सार्वजनिक विवरण दे रहा था तो तथ्य यह रहा है कि कंपनी ने आज की तारीख तक अपनी क्षमता के विस्तार नहीं किया है।

ज. कतर से आयात कीमत वस्तुतः संबद्ध देशों से आयात कीमत की अपेक्षा कम है। यदि संबद्ध देशों की आयात कीमत कतर से आयात कीमत से अधिक है और यदि इन आयातों का काफी अनुपात जीएसएफसी द्वारा है तो संबद्ध देशों से आयात से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा भी माना गया है।

झ. आयात पूर्ण रूप में तथा सापेक्ष संदर्भ में कम हुए हैं, जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी संबद्ध देशों से पहुँच कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना नकारात्मक कीमत कटौती है। यह दर्शता है कि घरेलू उद्योग पर आयातों का कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा। उत्पादन, विक्री और उपयोग इष्टतम स्तरों पर हैं। क्षति की अवधि में लाभ, नकद प्रवाह और आरओआई काफी बढ़े हैं। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को कोई सतत क्षति नहीं है।

ज. प्राधिकारी ने इन आधारों पर पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की सिफारिश की है कि संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में जांच की अवधि में क्षति मार्जिन चीन से सफेद सीमेंट, जिंक ऑक्साइड, जापान और थाइलैंड से एसिटोन, जापान और थाइलैंड से फिनोल और चीनी तैपाइ से कास्टिक सोडा जैसे मामलों में नकारात्मक है।

झ. जीएसएफसी ने स्वीकार किया कि इंडोनेशिया से मेलामाइन का कोई आयात नहीं है। वस्तुतः जीएसएफसी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचित किया गया था, जिसका प्राधिकार भी जात नहीं है, कि इंडोनेशिया में संयंत्र बेकार हो सकता है, फिर भी जीएसएफसी ने यह दर्शाए विना क्षति की संभावना का दावा किया है कि इंडोनेशिया से शेष देश को क्या-क्या निर्यात होते हैं।

और इस तथ्य के बावजूद कि मेलामाइन का अपना पूर्ण सीमा शुल्क वर्गीकरण है। प्राधिकारी ने सही निष्कर्ष निकाला है कि इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं, इस प्रकार इंडोनेशिया से पाटन एवं क्षति की कोई संभावना नहीं है।

ब. प्राधिकारी ने ईरान और जापान से 10000 मी. टन और 49000 मी. टन तक का निर्यात पाया है। तथापि, यहां जो नोट करना व्यावहारिक है, वह कीमत भी है जिस पर इन सामानों का निर्यात किया गया है। हमने पूर्व में भी रिकार्ड अनुरोध किए थे और अंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि यूरोपीय संघ, ईरान और जापान द्वारा तीसरे देशों के निर्यातों के संदर्भ में नकारात्मक क्षति मार्जिन है। वैश्विक व्यापार उचित कीमत को नहीं रोकता और उसे रद्द नहीं किया जाता है। इस प्रकार, वर्तमान स्थिति में जांच की अवधि में, जांच की अवधि के बाद की अवधि में और तीसरे देशों के निर्यात में क्षति मार्जिन सब जगह नकारात्मक है और पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की आवश्यकता है।

ट. इसके अतिरिक्त, प्रकटन विवरण से यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यूरोपीय संघ, ईरान और जापान में क्षमता क्रमशः 4,50,000 मी. टन, 20,000 मी. टन और 90,000 मी. टन है। यूरोपीय संघ ने क्षमता के लिए प्रकटन विवरण में उल्लिखित मेलामाइन के समीक्षा जांच परिणामों में निम्नलिखित भी उल्लिखित हैं:

इस काफी बाजार हिस्से के बावजूद, तीसरे देशों से आयात का यूनियन उद्योग पर कोई क्षतिकारक प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि यह नीचे दिए गए अनुसार क्षति संकेतकों के विकास से देखा जा सकता है। कारण यह है कि यद्यपि उनका औसत कीमत स्तर एमआईपी से कुछ कम था (पूरी विचाराधीन अवधि में 1000 यूरो/टन की रेंज में), (2) वह कभी भी इतना कम नहीं था जितना चीनी कीमतों में सूल जांच के दौरान अथवा शेष विश्व को वर्तमान चीनी निर्यात कीमतों में पाया (लगभग 855 यूरो/टन को सीआईएफ यूनियन फ्रंटियर में समायोजित)। और भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इन सभी स्रोतों के पास अपेक्षाकृत सीमित उत्पादन क्षमता है (अधिकतर 50000 टन से लेकर 60000 टन वार्षिक की रेंज में), (3) जिसका अभिप्राय यह है कि उनका मेलामाइन के बाजार के आपूर्ति/मांग शेष पर समान विवरणकारी प्रभाव नहीं है, जैसा कि पीआरसी सूल जांच में बताने में सक्षम था।

- इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने एनिलिन के संबंध में विगत समीक्षा के जांच परिणाम में नोट किया और माना है कि केवल अधिशेष क्षमता की उपलब्धता का तथ्य अपने आप में जांच परिणाम का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संबद्ध देश से पाटन बार-बार होगा अथवा जारी रहेगा तथा शुल्कों के हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाएगा।
- अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हो रही है, घरेलू उद्योग का निष्पादन काफी सुधरा है, पाटन एवं क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है और इसके अतिरिक्त, याचिकार्ता स्वयं तुलनीय कीमत पर अथवा संबद्ध देशों से कम कीमत पर भी कतर से काफी मात्रा में आयात कर रहा है और इन कीमतों से वह क्षति महसूस नहीं कर रहा है। स्थिति ऐसी होने से याचिकार्ता को वर्तमान संबद्ध देशों से क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः पाटनरोधी शुल्क जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और वर्तमान उपाय रोक दिए जाने चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण के उत्तर में विभिन्न हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित रूप में की है:

66. प्राधिकारी मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. द्वारा कतर से किए गए आयातों के कारण पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ब) के अनुसार, उसे घरेलू उद्योग न मानने के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि यह मामला निर्णायिक समीक्षा का है और कतर से विचाराधीन उत्पाद के पर्याप्त आयातों के बावजूद जीएसएफसी ने पाटनरोधी शुल्क के उपाय लगाए जाने के बाद विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन बंद नहीं किया। इसके बजाए, वह निकट भविष्य में उसकी क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त, देश में एकमात्र वही मेलामाइन का उत्पादक है। पाटनरोधी शुल्क मूल जांच में मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु लगाया गया था जिसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ब) के अनुसार, उस समय घरेलू उद्योग के रूप में पहचाना गया था। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. ने काफी मात्रा में गैर-संबद्ध देश कतर से आयात किए। प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, पाटित वस्तु के आयात और निर्यातकों/आयातकों के साथ संबंध पर विचार करते हुए आवेदक के घरेलू उद्योग के आधार का मूल्यांकन नियम 2(ब) के अनुसार अपेक्षित है, तथापि, दूसरे स्रोतों से कोई आयात अथवा उनके साथ संबंध के मुद्दा, जिनका दावा नहीं किया गया

हैं/जिनके पाटित होने की पहचान नहीं की गई है, की यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारणात्मक रास्तों के संबंध में समुचित जांच की अपेक्षा होगी कि घरेलू उद्योग को क्षति के उपयुक्त कारणों की सही रूप से पहचान की गई है। अतः जीएसएफसी के घरेलू उद्योग के रूप में आधार के मुद्दे गलत बताए गए हैं और प्राधिकारी मानते हैं कि जांच के अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात न होने के कारण जीएसएफसी नियम 2(ख) की अपेक्षाओं को पूरा करती है, यह दोहराया जाता है कि कितर से जीएसएफसी द्वारा काफी आयातों की घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में संबद्ध देशों से आयातों की कारणात्मकता और उद्योग को क्षति के तहत समुचित रूप से जांच की गई है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान तीन संबद्ध देशों यूरोपीय संघ, ईरान और जापान के लिए सीएनवी के परिकलन के सिद्धांत पर प्रश्न उठाया है। अग्रवाल केमिकल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स इंटरनेशनल ट्रेड रेकिटेस ने उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर सीएनवी, आईसीएसएलओआर जैसे गौण स्रोत और विश्व व्यापार मानचित्र (तीसरे देश की कीमतें), यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में सूचित की गई घरेलू कीमतें, सभी समुचित नहीं हैं और यह कि 5 प्रतिशत लाभ से यूरोपीय संघ में सूचित की गई लागत अथवा यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कद्दी सामग्री की कीमतें ही अपनाई जाएं। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि लागू किए जाने की आवश्यकता है जब सीएनवी के लिए तीसरे देश की कीमतें अपनाई जाएं। समायोजन इस सिद्धांत में शामिल किया जाए।

68. इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मैसर्स अग्रवाल केमिकल्स ने समायोजनों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, मैसर्स अग्रवाल केमिकल्स ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में देरी से अनुरोध किया कि वे मौखिक सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं और जबकि उनके द्वारा कई अनुरोध किए गए हैं, उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर जिस समायोजन की वकालत की है, उसको सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, जब किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है, तो प्राधिकारी ने नियम 6(8) तथा डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अनुसार, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना का समुचित रूप से संदर्भ दिया है तथा सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए उपयुक्त सिद्धांत को अपनाया है। यूरोपीय संघ के मामले में, यूरोपीय संघ के जांच परिणाम की उपलब्धता में संदर्भ के लिए विश्वसनीय दस्तावेज दिए गए हैं। आईसीएसएलओआर जैसे गौण स्रोत और विश्व व्यापार मानचित्र को प्राधिकारी द्वारा विगत में उन विशिष्ट मामलों के आधार पर वैधता के प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से विश्वसनीय आंकड़ों के स्रोत के रूप में अपनाया है जहां वे आंकड़े उपयुक्त रूप से उपलब्ध हैं। प्राधिकारी ने अपनी सतत परिपाटी को अपनाते हुए, जैसा कि इन मामलों में किया गया है, घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर सीएनवी निर्मित किया है और साथ ही यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में अन्य आंकड़ों, आईसीएसएलओआर, विश्व व्यापार मानचित्र के आंकड़ों की मौजूदगी को नोट किया है जो प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि अर्थात 01.04.2017 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए परिकलित सीएनवी से सह संबंध रखते हैं। प्रकटन विवरण और अंतिम जांच परिणाम में मानी गई जांच की अवधि के बाद की अवधि छः माह की अवधि है जिसे प्राधिकारी द्वारा निर्णयिक समीक्षा के मामलों में सतत रूप से अपनाया गया है। यह अनुरोध कि यूरोपीय संघ के जांच परिणाम में सूचित की गई लागत अपनाई जाए और केवल 5 प्रतिशत लाभ जोड़ा जाए, उपयुक्त नहीं है क्योंकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के प्रावधान और डब्ल्यूटीओ अनुच्छेद 2.2.2 के अनुसार सामान्य मूल्य के लिए सामान्य लाभ का संदर्भ दिया जाता है न कि 5 प्रतिशत का। इस मामले में यूरोपीय आयोग के जांच परिणाम में मौजूदा घरेलू कीमतें प्रकाशित की गई हैं जिनमें वास्तविक लाभ शामिल है। व्यापार परीक्षण की सामान्य अवधि भी उत्पादक/निर्यातक की विशिष्ट लागत तथा कीमत आंकड़ों पर लागू की जा सकती है न कि औसत आधार पर सामूहिक रूप से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए। प्राधिकारी यह पुष्ट करते हैं कि जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए अपनाया गया सिद्धांत समुचित है।

69. जहां तक एक्सेप ने सूचित की गई कुछ त्रुटियों तथा जांच की अवधि के बाद की अवधि अर्थात 01.04.2017 से 30.09.2017 तक की सीआईएफ कीमतें प्रकट करने के अनुरोध का संबंध है, एक्सेप ने कुछ शुद्धि समुचित रूप से आगे के पैराग्राफों में कर दी गई है जिससे पाटन मार्जिन में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, जैसा कि प्रकटन विवरण में सूचित किया गया है। जांच की अवधि के बाद की अवधि की सीआईएफ आयात कीमतें जांच की अवधि के बाद की जांच के तहत पैरा 59 में भी उल्लिखित की गई हैं। जहां तक गौण स्रोतों से जांच की अवधि के बाद की अवधि में "सीएनवी" के परिकलन का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि में पाटन एवं क्षति के महत्वपूर्ण मानदंडों का मूल्यांकन और उसके बाद संबद्ध देशों से क्षति रहित आयात कीमतें अन्य गौण स्रोतों पर सीएनवी का आगे परिकलन नगण्य कर देता है।

70. जहां तक एनआईपी का पुनः परिकलन करने, विशेष रूप से कार्यशील पूँजी की पुनः जांच करके और उत्पादन प्रक्रिया में उप उत्पाद मेलामाइन की कीमत की जांच करके पुनः परिकलन करने का संबंध है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है, प्राधिकारी अनुबंध-III के पैरा (viii) के प्रावधान को नोट करते हुए मानते हैं कि मैसर्स जीएसएफसी बहु उत्पाद/स्थान वाली कंपनी है और उसके दो व्यापारिक क्षेत्र हैं, यथा उर्वरक उत्पाद तथा औद्योगिक उत्पाद। चूंकि, कोई भी कार्यशील पूँजी के द्वारे मेलामाइन के संबंध में उपलब्ध नहीं हैं, अतः कार्यशील पूँजी का काल्पनिक परिकलन वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार, निवल चालू परिसंपत्ति मेलामाइन के बिक्री राजस्व के डीजीएटी में अपनाई गई परिपाटी के अनुसार, जीएसएफसी के कुल बिक्री राजस्व में प्रतिशत अनुपात में निकाली गई है। घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया कार्यशील पूँजी का परिकलन कुछ अवधारणाओं पर आधारित प्रतीत होता है जिनका न तो कोई समर्थन है और न ही वे स्पष्ट हैं।

71. जहां तक अमोनिया के संबंध में सह उत्पाद का संबंध है, कंपनी ने कड़ी सामग्री के रूप में प्राकृतिक गैस की खपत की और उसमें विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे सिंथेसिस गैस – अमोनिया – सल्फ्यूरिक एसिड – यूरिया उत्पादित मेलामाइन को अपनी बड़ीदा यूनिट में स्थित अपने संयंत्र में लगाकर किया। आईपी उत्पादों के लिए एनजी की आवश्यकता बाजार कीमत पर खरीदी गई प्राकृतिक गैस पर आधारित है जिस पर सब्सिडी नहीं है और इसीलिए मेलामाइन से लिए गए अमोनिया का मूल्यांकन अमोनिया की चार्जिंग दर पर किया गया है।

72. प्राकृतिक गैस की कीमत अंतिम प्रयोग के आधार पर होती है। उर्वरक के प्रयोग के लिए प्राकृतिक गैस की दरें शासित कीमत तंत्र (एपीएम) पर होती हैं और औद्योगिक उत्पाद के लिए बाजार दर के अनुसार होती हैं। औसत प्राकृतिक गैस की दरें वर्ष 2016-17 के दौरान जीएसएफसी के आंकड़ों के अनुसार, उर्वरक प्रयोग के लिए ***रुपए और औद्योगिक प्रयोग के लिए ***रुपए प्रति यूनिट थीं तथा तदनुरूपी अमोनिया दर उर्वरक उत्पादों के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, *** रुपए प्रति मी.टन तथा औद्योगिक उत्पाद के लिए *** रुपए प्रति मी.टन थीं। अमोनिया की कीमत एक रुप है और कंपनी की लेखा बहियों में कोई ग्रेड नहीं है। लेखाओं में अंतर्निहित गैस की मात्रा के आधार पर कोई लागत नहीं दर्शाई गई है।

73. किसी भी दशा में *** रुपए प्रति मी.टन की उप उत्पाद कीमत सब्सिडीयुक्त अमोनिया की न्यूनीकृत कीमत है। घरेलू उद्योग ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि अमोनिया की औसत सीएफआर कीमत 2016-17 के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की तुलना में 2015-16 के दौरान *** अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन थी। एनआईपी के कार्यचालन में सब्सिडी रहित उत्पाद के लिए माने गए उप उत्पाद की कीमत के साथ वह कीमत तुलनीय है। अतः प्राधिकारी घरेलू उद्योग को गोपनीय आधार पर पहले ही प्रकट की गई एनआईपी की पुष्टि करते हैं।

74. इसके अतिरिक्त, उन्हीं आयातकों ने उन्हें एनआईपी के प्रकटन की मांग की है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली में गोपनीयता के प्रावधानों के अनुसार तथा उसकी सतत परिपाटी के अनुसार उन्होंने सभी हितबद्ध पक्षकारों को एनआईपी के परिकलन के संबंध में अगोपनीयता के सिद्धांत बताए हैं और इसके बाद किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक फाइल में किसी आयातक द्वारा किए गए कुछ अनुरोधों की अनुपलब्धता के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावों के संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि सार्वजनिक फाइल को समय-समय पर अद्यतन किया गया था और किसी भी दशा में सभी हितबद्ध पक्षकारों के उचित अनुरोधों को सभी हितबद्ध पक्षकारों के लाभार्थ प्रकटन विवरण में उल्लिखित किया गया था जो अनिवार्य रूप से अतिव्यापन प्रकृति के थे।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

75. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के तर्क की जांच करने के बाद और उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों, सीमाओं और विश्लेषण के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

- (i) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के आर्थिक वित्तीय मानदंड स्थिर हैं और अच्छे हैं। संबद्ध देशों अर्थात् यूरोपीय संघ, ईरान और जापान से आयातों के कारण कोई भी क्षति नहीं है। क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि और यहां तक कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से आयात शून्य हैं। इसके अतिरिक्त, जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं है।

- (ii) कतर से जीएसएफसी द्वारा किए गए आयात क्षति की अवधि, जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान काफी रहे हैं जो या तो संबद्ध देशों से आयात कीमत से कम कीमत पर हैं अथवा तुलनीय हैं। अतः कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, संबद्ध देशों से निर्यातों के कारण नहीं हो सकता।
- (iii) पाटनरोधी का संरक्षण संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति को हल करने के लिए जीएसएफसी की मौजूदा क्षमता के लिए था तथा जीएसएफसी द्वारा स्थापित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद की अतिरिक्त क्षमता, जिसे अभी आना है, के लिए नहीं दिया जा सकता।
- (iv) उपर्युक्त के महेनजर प्राधिकारी यह उपर्युक्त नहीं मानते कि यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान से संबद्ध सामानों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की जाए तथा इस जांच को एतद्वारा पाटनरोधी नियमावली के नियम 14(ब) के अनुसार रद्द करते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2018

FINAL FINDINGS

Subject : Anti-dumping investigation (Sunset Review) concerning imports of “Melamine” originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan.

F. No. 7/14/2017-DGAD.—Having regard to Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules).

A. Background

1. The Customs Notification regarding the final findings dated 1st June, 2012 of the original investigation on imports of Melamine from EU, Iran, Indonesia and Japan was notified through Customs Notification No. 48/2012-Customs (ADD) dated 8th October, 2012. Based on the 1st sunset review (SSR) initiated vide Notification No 7/14/2017-DGAD dated 22nd September, 2017, the existing Anti-Dumping Duty has been extended till 7th October, 2018 through Customs Notification No. 47/2017-Customs (ADD) dated 6th October, 2017.

B. PROCEDURE

2. The procedure described below has been followed:

- a) The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), under the above Rules, received a written application from M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. (hereinafter referred to as the “petitioner”) as domestic industry of the subject goods, alleging continued dumping and injury of Melamine (hereinafter also referred to as “subject goods”) originating in or exported from European Union, Iran, Indonesia and Japan (hereinafter referred to as the “subject countries”) The domestic industry also submitted regarding threat/liability of Dumping and Injury in event of withdrawal of existing ADD.
- b) The Authority, on the basis of evidence submitted by the petitioner to justify initiation of the investigation, decided to initiate the Sunset review investigation against imports of the subject goods from the subject countries.
- c) The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
- d) The Authority issued a public notice dated 22nd September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations Sunset review concerning imports of the subject goods from the subject countries.

- e) The Authority forwarded a copy of the public notice to all known exporters (whose details were made available by the Petitioner) and gave them opportunity to make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- f) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of the subject goods in India and industry associations and advised them to make their views in writing within forty days from the date of the letter.
- g) The Authority provided a copy of the non-confidential version of application to the known exporters and the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules. A copy of the Application was also provided to other interested parties, wherever requested.
- h) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

DSM Melamine OCI Melamine Europe Mijnweg-1, PO Box No.601 6160 AP Geleen, Netherlands	Agrolinz Melamine International GMBH A-3021 Linz, St.Peters Strasse-25 Austria.
Nissan Chemical Industries Ltd. 635 Sasakura , Fuchu Machi, Toyama-9322792, Japan	Khorasan Petrochemical Company Vanak Avenue, PO Box No.19395-4583 Tehran, Iran
Iran Petrochemical Commercial Co., No.1339, Valisar Avenue, Vanak Square Post Box No.19697 Tehran, Iran	PT.DSM Kaltim Melamine Kawasan Indstri, PT Pupuk Kalimantan, Timur-75313, Indonesia
PT Sri Melamin Rejeki Plaza Aminta, 9th Floor JI.Let.Jend T.B. Simatupang, Kav.10 Pondok Pinang, Jakarta-12310, Indonesia	

- i) In response to the initiation notification, no exporters/producers from the subject countries have responded.
- j) Questionnaire was sent to the following known importers/users/associations of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule6(4)of the AD Rules:

Century Plyboards (I) Limited. 6, Lyons Range, Kolkata 700001	Greenply Industries Ltd. E/176-179, Phase II Riico Industrial Area , P.O.Behrор-391 701, Rajasthan
Merino Industries Ltd. Village : Accheja Delhi Hapur Road, Hapur Uttar Pradesh	Merino Panel Products Ltd. Village : Rohad,44KMS Stone, Delhi Rohtak Road, Haryana
Golden Laminates Ltd. 192-193, Ind. Area,Panchkula Phase - I, Haryana	Surya Vikas Plywood Pvt. Ltd. Vill.- Damla, Delhi Road, Yamuna Nagar,
Katyani Chemtech India Ltd.	Rushil Décor Ltd.

Vill.- Bhagwanpur,Derabassi-Barwala Road Derabassi.	1 Krinkal Apartment,Mahalaxmi Society, Paldi, Ahmedabad, Gujarat.
Sundek India Ltd. 1421 Rajpur,Kalol Mehsa Highway, KADI, North Gujarat	Bloom Dekor Ltd. Dhanlaxmi Chambers,Ashram Road Ahmedabad, Gujarat.
HEF India Private Ltd. New No. (Old No.2),Third Class Street, C.I.T Colony, Mylampore, Chennai	Managlam Timber Products Ltd. Birla Building,7th Floor, R.N. Mukharjee Road, Kolkata
Virgo Industries Village: Rampur, Jatan,Nahan Road, Himachal Pradesh	Alfa Ica Ltd. 204, Uma Industrial Estate, Sanand, Ahmedabad, Gujarat
The Bombay Burmah Trading Co. Plot No. 23 to 26, 46 to 48 Sector 5, II E Pant Nagar Industrial Estate, Rudrapur (Uttranchal)	

k) The following importers/users of the subject goods have responded in the form of questionnaire responses or provided comments to the initiation of the investigation.

- (i) M/s Exim Corp India Pvt. Ltd.
- (ii) M/s Century Plyboards (I) Ltd.
- (iii) M/s Virgo Industries
- (iv) M/s Agarwal Chemicals
- (v) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.

l) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. The public file was inspected by various interested parties, who requested copies of the documents from the public file, which were provided the same.

m) Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis, which was made available through public file.

n) Further information was sought from the petitioner and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.

o) The Non-injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') considering the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has also been worked out to ascertain extent of injury.

p) Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2016 to 31st March 2017 (12 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the POI.

- q) As the investigation is an SSR, post POI period (1.4.2017 to 30.9.2017) data has also been examined to evaluate threat of Dumping/Injury.
- r) In accordance with Rule 6(6) of the Anti-dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a oral hearing held on 2nd January 2018. The parties, who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- s) The Authority issued a disclosure statement under Rule 16 on 5/2/2018 and provided an opportunity to give comments to the disclosure statement till 12th February, 2018.
- t) Exchange rate for conversion of US\$ to Rs. is considered for the POI as Rs.67.95 as per customs data.
- u) In this final findings, *** represents information furnished by the interested parties on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

3. The product under consideration in the present investigation is Melamine. In the original case, the Final Findings issued vide Notification No. 14/35/2010-DGAD, dated 1st June, 2012 defined the product under consideration as follows.

“Product under consideration in the present investigation is Melamine, a tasteless, odorless, and non-toxic substance. Melamine formaldehyde resin is used for laminates as it offers good hardness, resistance to scratch, stain, water and heat. Laminates used in some electrical applications possess high mechanical strength, good heat resistance and good electrical insulating properties. Asbestos filled Melamine resins possess very high dielectric strength and high resistance. Beside the best dimensional stability, Melamine Formaldehyde moulding powder gives clear and bright colors, easily moldable and offers resistance to surface scratching. Melamine is reacted with formaldehyde and made into resins or moulding powder for making innumerable products of beauty and utility. Melamine is used for making melamine formaldehyde, which in turn is used in producing downstream products.

Melamine has a dedicated Custom Sub Heading 29336100 of Chapter 29 of the Customs Tariff Act. The product falls under OGL category and is freely importable.”

C.1 Views of the Domestic Industry

4. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration: -

- The product under consideration in the present Sunset Review application is Melamine. As submitted in the petition, present investigation being a sunset review investigation, the scope of the product under consideration remains the same as has been in the original investigation which is Melamine. There is no known difference in the product under consideration produced and exported from the subject countries and the subject goods produced by the domestic producer / GSFC. The subject goods produced by the domestic producer and those imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

C.2 Views of Importers, Consumers and other Interested Parties

5. Following interested parties have raised issues with regard to the product under consideration.

- (a) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd has submitted the following:
 - Even, sgs cannot test the product under consideration in India.
 - There are various raw materials used to manufacture the product under consideration.
 - There are various grades of the product under consideration.
 - Different packing of PUC has different price.

- Different grades have different price & usage/application.
- There is difference in quality & usage due to difference in grades.

(b) M/s Exim Corp has submitted the following:

- There are different grades of Melamine. Imports are of top quality grade while domestic industries grades are of different qualities and net sales realization is not a true and fair depiction of domestic prices

C.3 Examination by the Authority

6. The Authority notes that since the present investigation is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as that of the original investigation. The product under consideration, Melamine, is classified under Chapter 29 under subheading 29336100. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.
7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

8. The application filed is for the review and continuation of the quantum of the anti-dumping duty in force, and the issue of like article has been already dealt with in the previous investigations. In the earlier investigations the Authority has already held that the subject goods produced by the domestic industry is like article to the subject goods imported from the subject countries.
9. As regards the argument of different grades of product under consideration, it is noted that none of the exporters of the product under consideration cooperated or provided any information regarding different grades of product under consideration. Certain importers raised concerns about different grades of PUC which have been appropriately dealt in later paragraphs.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. Rule 2 (b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers"

D.1 Views of the Domestic Industry

11. The domestic industry has made the following submissions with regard to the 'domestic industry': -

- GSFC is the sole producer of the subject goods and constitute domestic industry within the meaning of Rule 2.
- It has been an argument by certain interested parties that GSFC has imported the subject goods from Qatar which is a non-subject country and this should lead to the qualification of GSFC as a domestic industry. It is humbly submitted that the issues coined has no legal basis.
- It is very clear from Rule 2 (b) of AD Rules that the reference given in the context of imports is the imports of dumped article and not imports from a non-dumped source. In other words, to become importers themselves the company might have imported from the subject countries and import from a non-subject country would not come under the purview of imports as provided in Rule 2 (b). Notwithstanding the above, if the contention is that the word used is 'imports thereof' and it may include other imports as well then it is a wrong reading and interpretation of the Rule. The proviso should be read in its entirety and the dumped article made applicable in case of relation with exporters/imports is what relevant for the imports also. In case, should there be a doubt in the interpretation, the language of WTO AD Agreement needs to be relied upon as ordered by the Hon'ble

Supreme Court in GM Exports case (in short) and the WTO AD Agreement defines the position of importers themselves as follows;

“Article 4.1 (i) when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers;”

- The Agreement clearly mentions alleged dumped product and the Indian AD Act and Rule cannot mean a different thing while defining the domestic industry that the contentions of the opposing parties has to be rejected as bereft of any merit and it should be held that GSFC constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b).
- It is once again clarified that the imports made from Qatar by the company are only to meet certain customer demand and not to lose those customers in the long run that too when the company is about to complete large capacity expansions. The focus of the company is only production in its plant and imports were not made as a core trading activity. Company did not target any notable profits from such imports and as submitted such imports were performed to retain the long term customer looking at the future production by the company. The credentials of GSFC continue to be that of a responsible Indian producer and the investments undertaken by it underlines such credentials. Had the focus of company been imports, it would not have considered such investments.

D.2 Views of Importers, Consumers and other Interested Parties

12. Following interested parties have raised issues with regard to the scope and standing of the domestic industry.

- (a) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - The petitioner is importing the product under consideration from Qatar.
 - What are the reasons the petitioner is trading instead of manufacturing?
- (b) M/s Exim Corp India Pvt. Ltd has submitted that GSFC has no standing as Domestic Industry under Rule 2 (b) of AD Rules.

D.3 Examination by the Authority

13. The Authority notes that application for the sunset review has been filed by M/s. Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., the domestic industry in the original investigation. The petitioner company is not related (neither directly nor indirectly) to any exporter in the subject country or importer of product under consideration in India. Further the petitioner has not imported the subject goods from subject countries during the period of investigation. The petitioner made some imports of PUC from the subject countries in years prior to PoI and from Qatar during PoI and in the injury period in significant quantities. The provisions of Rule 2 (b) requires to examine imports by Domestic Industry with reference to dumped article thereby limiting such examination to the subject countries only. While this is with regard to the eligibility as Domestic Industry, imports made by Domestic Industry from non-subject countries is a matter of examination to evaluate the claims of injury and causality which the Authority has evaluated in later paragraphs. The Authority holds that despite the above company continues to be a producer undertaking production and even enhancing capacity and domestic industry therefore qualifies to hold the status as within the meaning of the Rule 2(b) and that the petition satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the AD Rules.

E. ASSESSMENT OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Submissions made by importers and other interested parties/ other parties

14. Following submissions have been made by importers, subject countries and other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin

- (a) M/s International Trade Remedies & Practices representing M/s Agarwal Chemicals
 - Adjustments made by Domestic Industry on export price are not on evidence and cannot be considered.

- MIP prescribed in EU's finding cannot be considered as 'Normal Value' but be based on EU's cost of production in 2015 – 16 as per findings and be adjusted further with urea price in 2016 – 17 and 5% profit be added, which would not imply dumping.

(b) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.

- Oci Nitrogen B.v., P.O. Box 601, 6160 Ap Geleen, the Netherlands is the manufacturer in EU. There are two more manufacturers in Europe.
- Exports of Melamine from Europe is very less

(c) M/s Century Plyboards Pvt. Ltd.

- DA should have evaluated normal value on the basis of published accounts of exporters or conducted market enquiries or examined the export prices to 3rd countries.
- If normal value is so high in the exporting countries then Domestic Industry should also export in those markets.

(d) M/s Exim Corp India Pvt. Ltd.

- Initiation of SSR is not automatic in light of the judgment by Hon'ble High Court Delhi in W.P. 146/2017 and 147/2017. Petition does not meet the requirements of AD Rules. Construction of NV has not been disclosed and adjustments claimed on export price are extremely high. Petitioner's claim on CNV should not have been accepted and that GSFC should have made efforts to obtain domestic prices in subject countries.
- Petitioner has claimed high adjustment on export price for example marine insurance as 0.5% while it should be 0.125%.

E.2 Submissions made by Domestic Industry

15. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin:

- a) The estimates of normal value of different basis and the comparison of the same with export price into India shows positive dumping margin in case of subject countries except Indonesia as there were no imports from Indonesia.
- b) There have been continued imports from EU, Japan and Iran. Even though it can be argued that the imports necessitated because of demand supply gap, the fact of the matter is that such imports were made at dumped rates and behavior of the producers/exporters from the subject countries still continues unchanged and when dumping continued when AD duties are in force, it is beyond any doubt that dumping will continue in an aggravated manner if duties are allowed to expire.

E.3 Examination by Authority

Normal Value

16. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

- (i) *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
- (ii) *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*
 - (a) *Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section(6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of exporter there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

17. The Authority notes that many interested parties have submitted referencing of other secondary source data to evaluate 'normal value' in subject countries. The Authority has therefore also referenced EU findings, ICSLOR and World Trade Atlas data for this purpose besides the CNV computed on the basis of cost data of the domestic industry.
18. EU in final findings dated 30th June, 2017, on an Anti-Dumping investigation on imports of Melamine from China had reported in its finding domestic selling price of 1179 Euros/MT for the period 2015 – 16. The Domestic Industry has also provided ICSLOR spot prices prevailing in EU for the period 2015 – 16 and 2016 – 17. The domestic prices reported in EC's findings correlate with the ICSLOR's reported domestic prices of 1178 Euros/MT in 2015 – 16.
19. The Authority has also considered the world prices of Melamine from EU to India and other countries during 2015 – 16 and 2016 – 17 reported by WTA. The domestic selling prices as reported in EU's findings for 2015 – 16 has been appropriately adjusted for 2016 – 17 by an adjustment of average prices difference of Melamine global exports from EU to World during 2015 – 16 and 2016 – 17.
20. The Authority therefore holds that in an SSR investigation, the trade diversion in global exports of a subject country in event of cessation of an existing Anti-Dumping Duty requires examination of 3rd country prices of the subject countries in POI and post POI and therefore World Trade Atlas data on 3rd country prices of these subject countries has been considered to construct normal value along with CNV computed on the basis of Domestic Industry's data. Both CNV on Domestic Industry's data and 3rd country export prices of subject countries as per World trade Atlas data have been referenced and considered.

Export Price

Export Price of European Union

21. The Authority has adopted the DGCIS data for PoI and injury period to evaluate CIF price and the landed value. The weighted average CIF for PoI is evaluated as 1.216 \$/Kg. The adjustments on CIF price have been allowed as per the consistent practice/norms to an extent of 0.1 \$/Kg on ocean freight and 0.5 % of CIF on Ocean Insurance. Further adjustments of commission, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost to an extent of 0.5%, 0.5%, 1%, 0.5%, 1% have been allowed respectively on FoB. The ExEP is evaluated as 1.071 \$/Kg.

Export Price of Iran

22. The Authority has adopted the DGCIS data for PoI and injury period to evaluate CIF price and the landed value. The weighted average CIF for PoI is evaluated as 1.353 \$/Kg. The adjustments on CIF price have been allowed as per the consistent practice/norms to an extent of 0.04 \$/Kg on ocean freight and 0.5 % of CIF on Ocean Insurance. Further adjustments of commission, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost to an extent of 0.5%, 0.5%, 1%, 0.5%, 1% have been allowed respectively on FoB. The ExEP is evaluated as 1.260 \$/Kg.

Export Price of Japan

23. The Authority has adopted the DGCIS data for PoI and injury period to evaluate CIF price and the landed value. The weighted average CIF for PoI is evaluated as 1.199 \$/Kg. The adjustments on CIF price have been allowed as per the consistent practice/norms to an extent of 0.05 \$/Kg on ocean freight and 0.5 % of CIF on Ocean Insurance. Further adjustments of commission, port expenses, inland freight, bank charges and credit cost to an extent of 0.5%, 0.5%, 1%, 0.5%, 1% have been allowed respectively on FoB. The ExEP is evaluated as 1.102 \$/Kg.

Determination of Dumping Margin

24. Dumping margin based on CNV as per Domestic Industries cost of production data and other appropriate secondary sources (EU's finding, world trade atlas and ICSLOR) is computed as under:

S. No.	Particulars	Unit	EU	Iran	Japan
1.	CNV (DI's CoP Data)	\$/Kg	***	***	***
2.	CNV (Secondary Sources)	\$/Kg	***	***	***
3.	ExEP	\$/Kg	1.071	1.260	1.102
6. DM as per (1) above	\$/Kg	***	***	***	***
	% range	5 to 10	Minus 5 to minus 10	0 to 5	
7. DM as per (2) above	\$/Kg	***	***	***	***
	% range	20 to 25	Minus 5 to minus 10	0 to Minus 5	

F. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Submissions made by the importers and Other Interested Parties/ other parties

25. Following are the submissions made by importers and other interested parties/ other parties:

(a) M/s Century Plyboards Pvt. Ltd.

- As imports from Indonesia are Nil, there is no likelihood of dumping or injury from Indonesia
- GSFC has admitted that there are no excess capacity in EU yet claimed likelihood of injury from EU
- Fixation of benchmark price of Anti-Dumping Duty has helped DI.
- Cost of production of GSFC cannot exceed 77000 Rs/MT and therefore injury margin cannot be positive.
- NIP was determined ignoring the value of captive inputs recorded in books and creating artificial value of Urea to create imposition of ADD.
- It is surprising that if natural gas price and electricity have declined from 2013 – 14 to 2016 – 17 how cost of melamine has moved up from Rs. 60469/MT to Rs. 103796/MT.
- DGAD should examine the NIP determination as per AD Rules and also visit the NIP determined during 2nd SSR in case of imports from China.
- Neither the urea produced by GSFC has used natural gas nor melamine production uses Urea. The NIP is fraudulently fixed. These has been a departure in methodology for computing NIP now.
- Net sales realisation of DI would be atleast Rs. 15000/MT more than NIP of Rs. 74000/MT.

(b) European Commission

- As Per Article 11.1 of the WTO ADA, which provides that “An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury”. It is clear that, in case of non-continuation of injury (or where injury is not caused by the dumped imports), the duty should be terminated.
- In the application it is claimed that imports from the subject countries continue to be dumped, even though it is impossible for parties to understand the calculation of normal value due to the lack of relevant data that were

redacted in the non-confidential version of the complaint. However, the data provided on injury clearly shows that there is no continuation of injury to the domestic industry. On the contrary, the domestic industry seems to be in a healthy and profitable situation, where almost all economic parameters show a very positive and increasing trend.

- In particular: there is no sign of a slow-down in production, nor in the volumes of sales, which both remained stable during the whole period considered. The sales value even shows a slight increase (from 100 to 102, indexed).
- At the same time, the cost of sales decreased and the selling price increased, resulting in an impressive increase in profitability which, at the end of the period, had more than tripled (from 100 to 352, indexed).
- A positive and increasing trend can also be observed in the level of wages (+50%), productivity and return on investments.
- As regards market share, it decreased by 12% over the period considered. But the decrease in market share needs to be read in light of an increase in demand of 14%. With a capacity utilization rate of almost 100%, the domestic industry was not able to satisfy the increasing demand, which has obviously resulted in an increase in imports. Nevertheless, this increase in imports did not come from the subject countries but from other countries. Their import volumes increased by 175% and their market share more than doubled.
- As the domestic industry is not, at present, suffering material injury, the only possibility to extend the measures would be the likelihood of recurrence of injury. In this regard, and based on the data provided by the petitioner, it seems very unlikely that any injury caused by dumping would recur in the future. In fact, import volumes from the subject countries have decreased (-7%) over the period considered and so did their share in import volumes (-22%) and their share in demand (-18%). At the same time, their imports prices have increased (+4%) and they were not undercutting domestic prices during the POI. This shows that the subject countries do not have any propensity to cause injury to the domestic industry.
- In view of the lack of injury to the domestic industry and the unlikelihood that injury would recur, the cause of any difficulty the domestic industry might be suffering (which the abovementioned positive trends contradict) must lie elsewhere. The data provided by the petitioner show that, while imports from the subject countries have decreased, imports from countries already subject to measures (mainly China) and from other countries have increased.
- As regards imports from countries already subject to measures, GSFC holds a market share of 36%, which is almost equal to the market share of the imports from the subject countries and from other countries altogether. Moreover, it is surprising that, despite the measures in force, their import prices dropped by 28% over the period considered. During the POI, they were significantly lower than the prices from both the subject countries (26% less) and other countries (29% less), thus it seems very likely that they were significantly undercutting domestic prices.
- As regards imports from other countries, there was a substantial increase, both in volumes (from 4614 to 12 674 MT) and in market share (more than doubled). But, as highlighted above, in a situation where the demand increased and the domestic industry was clearly not able to satisfy it, imports represented the only source of supply and necessarily increased.
- Therefore in view of Article 11.1 of the WTO ADA, it is reiterated that “an anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury”.
- In the petition there is an indication that the domestic industry is investing in additional capacity, in order to be able to satisfy the increasing demand. Even if economically it makes sense for an industry to invest in its capacity in view of an increase in demand, it is certainly not the objective of anti-dumping measures to protect the domestic industry’s investment plans.
- Extending measures in these circumstances would clearly be WTO inconsistent, as in the present case the domestic industry is not suffering injury and injury is unlikely to recur; thus the measures are no longer necessary.

(c) M/s International Trade Remedies & Practices representing M/s Agarwal Chemicals

- Petitioner cannot claim protection for their new investment, as AD is to eliminate trade distorting effect and not to protect future investment. EC's findings in Pure silk typewriter ribbon fabrics from People's Republic of China (98/349/EC) is relevant in this context. Rather capacity expansion needs to be seen as a positive sign for petitioner's growth.
- The domestic producer can cater to only 23% demand of country and that end users are forced to pay price for continuous inability of Domestic Industry to satisfy demand. In fact for last 10 years the imports have been constant at a level to meet demand in the country despite ADD being in place.
- DI is manipulating by importing from Qatar which is about 40% of their production and at the same time seeking AD measure on other countries, thus taking advantage of both the worlds.
- No evidence has been provided by Domestic Industry on likelihood of injury, surplus capacities and high export intensity of these exporting countries.
- For diversion of EU's exports to India in view of 78% capacity utilisation in EU of product under consideration, no evidence on diversion to India has been provided. There is no price attractiveness to export to India as prices of exports from EU are higher than that of Indian market.
- As there are no exports from Indonesia, ADD on the imports from Indonesia may be withdrawn as was the case of FDY wherein SSR investigation was not initiated against Vietnam from where there were no exports.
- The price undercutting be considered on cumulative basis and not individual subject country wise.
- DI's submissions that ROI for EU producers was 34% and it was found that injury can reoccur are misplaced as ROI in EU is computed on NFA basis and not on capital employed. Further the AD extension in SSR can be on parameters of likelihood and not level of ROI.

(d) Government of Indonesia

- As provided in the petition, the domestic industries in India shows positive development whereby the demand of subject goods showed improvement by 4.5% while production increased slightly by 0.9% and the total import of subject goods increased by 5.9%. This is a clear indication that India still needs imports to meet their domestic demand. Moreover, the return of investment showed significant improvement by 57.2%.
- In view of the above, the continuation of the imposition of antidumping duties is strongly not advisable under Article 3.1 of the WTO anti-Dumping Agreement ("ADA"), which states that WTO Members could extend their imposition of anti-dumping measure if "the investigation is conducted in accordance with the agreement and the determination is made that (a) dumping is occurring, (b) the domestic industry producing the similar product in the importing country is suffering material injury, and (c) there is a causal link between the two previous results"
- Based on the aforementioned subject, the GOI requests the DGAD not to extend the imposition of Anti-Dumping Duty on import of Melamine especially from Indonesia since domestic industries no longer suffer material injury.
- Government of Indonesia has verified the existence of the two alleged companies, namely PT. DSM Kaltim melamine and PT. Sri Melamine Rejeki and that both companies were no longer exist and have declared bankruptcy.
- The above fact supports the data in the petition (Proforma IV Par 1 page 44) which shows that no importation of subject goods from Indonesia since 2013 to 2017.

(e) M/s Exim Corp India Pvt. Ltd.

- The sales realization by GSFC in last 5 years include lower and reject grades and therefore are not comparable and should be excluded for computing the weighted average NSR.
- DGAD should publish NIP for us to make submissions.

- AD measure is not a tool to earn superlative profit margins. DI can sell their product at remunerative prices without ADD.
- There is no evidence regarding likelihood of dumping or injury and these are mere assertions.
- There are WTO's jurisprudence on credible evidence viz. WTO panel in Guatemala – AD investigation regarding port land cement from Mexico and panel in US final determination on softwood lumber from Canada. DI's petition has no credible evidence on dumping and injury.
- GSFC has claimed excessive confidentiality by not providing evidence behind deductions on the exfactory export price.
- GSFC has neither suffered injury on volume nor on price and therefore has not suffered material injury at all.
- Actual NIP was determined at Rs. 74300/MT which was erroneously converted to USD.
- Petitioner has evaded disclosure of costs and NIP in India
- The average sales realization in EU varied from Euro 1013 to Euro 1149 per MT during 2012 to 2016 and therefore normal value should be in this range.
- The Authority should examine various factors of EU's findings also and that NIP of DI cannot be more than Rs. 58500/MT now.
- Authority should establish risk of recurrence as positive finding rather than likelihood of recurrence as a negative finding. While there are no positive words for public interest in AD Rules neither there are any negating words, DA should give an appropriate analysis on the interests of downstream industries

F.2 SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- Share of dumped imports remained at about 26% from subject countries which are a substantial percentage and relevance of such percentage is that they were made at dumped rates.
- The overall situation of the domestic industry remained positive in the POI which does not show any serious material injury as a positive effect of AD duties in force.
- Notwithstanding the above, capacity utilization which was 104.65 in 2015-16 was reduced into 99.23% in the POI.
- ROCE also slightly declined over the previous year during the POI
- Price Undercutting from EU and Japan were positive without ADD. Iran was negative and no imports from Indonesia. Overall PU is only slightly negative.
- The presence of the dumped imports at such significant level signified that there is a great likelihood such imports at dumped rates getting aggravated and soon the company turning to losses. The performance of the DI as per the proformas shows that it is still vulnerable to dumped imports and what has been helping the domestic industry to maintain its performance is the ADD in force and the expiry of the same is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. It is likely that the expiry of the present anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- The likelihood of dumping and injury gravely exists in case of expiry of the present Anti-dumping duties on imports of subject goods from subject countries. It is submitted that the subject goods are being imported into India from the subject countries at dumped prices. There exists current dumping from the subject countries during the Period of Investigation ("POI"). In this regard, it is also submitted that the dumping margins determined in respect of the subject countries in the original investigation indicates the propensity for dumping of the subject countries producers. Therefore, the fact that there is significant dumping margin in the present case, despite the existence of anti-dumping duties, further substantiates the reason for the Hon'ble Authority to continue with the present anti-dumping duty. Current dumping signifies the fact that

dumping will be continued in case of expiry of the present duties.

- The producers in the subject countries have large production capacities of the PUC, and if the present duty is revoked then there exists a strong possibility/likelihood of intensified dumping of the product in India. Further, the producers of the subject countries have a high export percentage as well. This clearly indicates likelihood of enhanced dumping of the PUC to India in case of revocation of existing duties. Therefore, in view of the significant surplus capacities and considerable export orientation, it can be verily said that the subject countries have a propensity to dump the subject goods. In this regard, it is pertinent to note that the Indian demand of the PUC has currently increased to substantial level since 2012-13, and along the Indian demand increase, the imports from EU countries have also increased as compared to imports from EU during 2007-08 to 2011-12. Any comparison to this time period, i.e. of 2007-08 to 2011-12, shall not have any relevance, as since 2013-14, due to increased total demand in India. Therefore, there are all chances in totality that material from EU shall be imported/dumped in more quantities in the event of any reduction/removal of Anti-Dumping duties. This shall enable the EU producers to increase their capacity utilization further as compared to the current utilization of about 78%.
- Rule 23 do not provide the set of parameters which needs to be examined to gauge whether the expiry of the duty is going to lead to the likelihood of dumping and injury. However, what can be the legal basis of such an examination is provided in detail in the petition it- self and the same is not reproduced for sake of brevity. However, following submissions are reemphasized which clearly demonstrates the likelihood of dumping and injury.

(a) Excessive Production capacity in Subject Countries: As per our market information, the producers in the subject countries have excessive production capacities. It is submitted that in case of cessation of the present duty, dumping from the subject countries would certainly intensify, causing intensified volume and price injury to the domestic industry. In case of revocation of anti-dumping duties, the volume of import of subject goods is bound to increase further. The available information on subject countries shows the following facts viz. their excess capacities and the potential to divert more to Indian market;

a) Indonesia

- i. There were no imports from Indonesia during the POI. It is understood that the Indonesian plant is currently shut down. But the chances of the revival of the plant are imminent and dumping and injury may resume in case of expiry of duties. It is a settled position that nil imports do not suggest any likelihood and as envisaged in the Rule, expiry of the duty may lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

b) Iran

- i. Iran continued to export the subject goods to India at dumped rates even after imposition of ADD.
- ii. Iran producers are also export oriented and have capacities to increase the exports to India. In fact, the submission by certain importers clearly stated that there are significant volume of exports from subject countries in terms of volume and value which further substantiates the claim of export orientation of subject countries (Submissions by Century dated 20.11.2017)
- iii. Submissions by Century shows that out of total export of 9203 MT from Iran, about 2500 MT was to EU at a price of USD1.09/Kg and about 2000 MT was to Turkey at a price of 1.13/kg whereas the same to India was at USD 1.35/kg. Higher price to India are apparently on account of existing duties in force and a decline in such dumped prices to new levels is so imminent. Decline in export price Iran in the event of AD duty is, thus, imminent.
- iv. Available evidences show likelihood of dumping and injury from Iran. Information on third country exports as available at the end of the petitioner is provided along with this submission.

c) Japan

- i. Japan continued to export the subject goods to India at dumped rates even after imposition of ADD.
- ii. Japanese producers are also export oriented and have capacities to increase the exports to India. Japan exported about 8200 MT to EU in 2015-16.

- iii. Submissions by Century show that out of total export of 49000 MT from Japan in 2016-17, about 17000 MT was to EU at a rate of USD0.99/per Kg whereas the same to India was at USD 1.15/kg. It can be ascertained that the higher but dumped prices to India were on account of AD duties in force and exporters from Japan would increase exports to India in the event of expiry of present duties. Decline in export price Japan in the event of AD duty is thus imminent.
- iv. As per our information, Japan has a capacity of about 90000MT and about half of it is exported. The domestic demand is understood to be insignificant and Japan would divert more material to India in the event of expiry of duties.
- v. Available evidences show likelihood of dumping and injury in case of exports from Japan. Information on third country exports as available at the end of the petitioner is provided along with this submission.

d) EU

- i. EU continued to export the subject goods to India at dumped rates even after imposition of ADD.
- ii. EU producers are also export oriented and have capacities to increase the exports to India. Information on world export submitted by opposing parties like Century do not appear correct since the said data shows a significantly lower volume to India viz. what is reported by DGCI&S in the same period. Century WTA data provided by Century shows 4681 MT exports to India whereas DGCI&S shows 6723.
- iii. Available evidences show likelihood of dumping and injury in case of imports from EU
- i) A latest final finding concerning SSR of ADD on Melamine from China PR published by EU/EC shows the following relevant points qua the EU market which suggests likelihood
- ii) EU has a total capacity of about 479120 MT and the capacity utilization was about 78% which means there is a spare capacity available. Though it can be argued that such underutilization was there for at least past few years, the moot point is that the expiry of present duties may lead to utilization of such capacities to increase the exports to India. Since, dumping continued even after ADD, the possibility is only that the material will reach India at an even lower price dismantling the Indian Industry.
- iii) The demand in EU was about 392776 MT during 2015-16 as per the said finding. Thus the capacities are set up clearly targeting the export markets and the excess capacity in EU would be sufficient to take away the market share of domestic industry in India.
- iv) The prices at which imports have made from EU are at undercutting, dumped and injurious levels that the likelihood of further dumping and injury is very imminent.
- v) The said final finding shows that the EU producers were achieving about 34% ROI and still it was found that the injury can still recur whereas ROI of DI is much lower than that. EU industry was achieving a profitability on sales of about 15% which is also very high viz. the petitioner.
- vi) Imports from China PR into EU was less than 2% of the demand whereas the share of SC in India is about 26% and EU found that even such volume from China PR showed the likelihood of dumping and injury.
- vii) The MIP imposed by EU is 1153 EURO per MT concerning import from China PR. This would be the apparent bench mark price for European producers also as they would try to keep their prices at par with imports (Price in 2015-16 was 1149 EURO). Such MIP can be a basis for Normal Value in case of EU. The cost and price of Melamine given in the said finding are not for the year 2016-17 and are for 2015-16. But MIP is applicable for POI as well. Also, it is an admitted fact in the EU finding that the raw material cost is not the determining factor of price for Melamine as the Melamine prices are governed by demand supply situation. The significance of this finding is that the cost in EU provided for 2015-16 is not indicative of probable price with adjustments for cost which can be the normal value for Melamine in EU for 2016-17. The MIP shows that there shall be positive dumping margins in case of such prices as well.
- viii) The above data points shows that the exporters from EU have a potential to export more to India and the chances of such increase in dumped volume is very imminent. EU alone can eat out the entire Indian demand should there be no ADD against EU.

The evidences on excess capacity and potential exports from subject countries shows that the exports from all such sources will surge at an even lower/dumped price levels with the expiry of duty that the likelihood of dumping and injury is very imminent on this count.

(b) Vulnerability of the Domestic Industry: This factor relates to whether the Domestic Industry would be susceptible to material injury in the event of expiry of anti-dumping duty which is force. In this regard, the Designated Authority must consider whether the industry will deteriorate further upon expiry of anti-dumping duties in force. In the instant ease, continued presence of dumped imports shows that the vulnerability to such dumped imports exists at large. In the event of expiry of current anti-dumping duties, the Domestic Industry will have to reduce the selling price to match the import price which will lead to material injury as is substantiated below:

- i In the event of cessation of current anti-dumping duty and if domestic industry chooses to sell at import prices, the domestic industry would suffer significant price injury. The subject imports are already forcing the domestic industry to sell the product at par with imported prices.
- ii In the event of cessation of current anti-dumping duty and if the domestic industry chooses to maintain the current selling price, domestic sales would drastically reduce, possibly leading to a minuscule market share.
- iii Also, the capacity expansion being completed also would be impacted. Thus, there is vulnerability on the current capacity and also the upcoming capacity.

(c) Price Attractiveness of the Indian Market: The product has a very significant demand in India. The prices at which subject goods are being imported from the subject countries are at a level creating serious pressure on the price at which the goods are being sold in the Domestic Market by the domestic industry which is evident in the fact that the Price undercutting have been positive in case of imports from EU and Japan and only slightly negative at subject countries level. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as they are already holding excessive capacities and the demand in India is very conducive for such dumping.

(d) Price Undercutting In the Absence of Measures: As submitted earlier, imports from EU and Japan have been undercutting the prices of the Domestic Industry in the POI though Iran was negative. In the event of revocation of duty, the situation would deteriorate further and the level of price undercutting will turn significantly positive in case of Iran as well.

(e) No likelihood of continuation or recurrence of dumping must be established: While the foregoing establishes that the present anti-dumping duties should be extended further, it is submitted that it is incumbent upon the producers/exporters from subject countries to establish that dumping and injury is unlikely to continue or recur in the event of revocation of anti-dumping duties. However, none of the producer/exporters have participated in the present investigation.

(f) Likelihood of injury in case of imports from Indonesia: It can be noted from the import summary statement that there haven't been any import of subject goods from Indonesia in the entire injury period. It is submitted that zero import does not establish absence of likelihood of dumping and injury in the event of expiry of present duties. Imports from Indonesia have become zero on account of the anti-dumping duties in force and dumping and consequent injury would resume, should there be no anti-dumping duties on Indonesia.

(g) Conclusion to likelihood of dumping and injury: GSFC submits that the above facts establishes that dumping and injury is likely to continue and intensify in the event of expiry of existing anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject countries. The facts that dumping continued from subject countries in the POI even after duties in force, substantial excess capacities with producers in the subject countries which has the potential to be diverted to Indian, positive price under cutting from EU and Japan and the price difference between imports and the domestic industry's non-injurious price clearly show that not only is there likelihood of intensified dumping in the event of expiry of anti-dumping duties, but also of intensified injury to the Domestic Industry.

- Apart from the dumping margins determined in respect of the subject countries in the original investigation, the large capacity of the subject countries to produce PUC can also adversely affect India. It is clearly indicated in the Petition that the propensity for dumping of the PUC from subject countries and the large capacities of such subject countries to produce the PUC establishes a strong likelihood of dumping of PUC in India, in the absence of the on-going Anti-dumping duty.

- In the above regard, it is submitted that there is huge gap between production *vis-à-vis* the demand in the subject countries. The total export during calendar year of 2016 from Austria was 32855 MT, Germany was 89004 MT and for Japan was 41488 MT. Therefore, in terms of the demand in the subject countries and their abundant production, it can be clearly stated that in the absence of Anti-Dumping duty, the domestic industry will gravely suffer. It is also important to consider the other significant operating factors in the subject countries which can force them to dump the PUC in India. Such factors like, stringent norms operating under Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals are to be required and followed for sale of PUC in Europe. Hence, in order to avoid these norms or rejection under these norms, Europe can easily dump its large production of PUC in India. The possibility of dumping of PUC from Iran to India is equally high due to prevailing sanctions over Iran.
- It has also been observed that the Net back price of the PUC exported by the subject countries to India is lower than the prevailing price in the respective countries. This information is gathered from the price reports available from the ICIS LOR data for Spot and contract prices of Melamine from Trade Maps India.
- In the event of any expiry of Anti-dumping duty in force, the new plant of GSFC with expanded capacity will gravely suffer, thereby causing GSFC to shut its operations
- GSFC is the only manufacturer of PUC in India, therefore constituting Domestic Industry in the present petition. The first plant of GSFC which was established in 1982 with an installed capacity of 5000 MTPA, the same was based on technology from Chemie-Linz, Austria. Thereafter, in view of the growing demand in India, the second plant of installed capacity 10000 MTPA was established in 1997, based on the same technology. At the present, the total installed capacity of PUC is 15000 MTPA though the demand of PUC has grown from 1977 till the present in India. Therefore, in view of the growing demand, GSFC is in the process of adding significant capacities to meet the stable demand for the product in India and such new capacities shall be operational in the near future. Therefore, GSFC is additionally adding 40000 MTPA plant to cater domestic demand. The total investment made by GSFC is to the tune of Rs. 1000 crores and the breakeven domestic price for this project is to the tune of USD 1400 to 1500 PMT.
- The operations of this plant will become un-viable and frustrate in the absence of Anti-dumping duty from the subject countries. As per the current prices given, under the Anti-dumping duty protection, GSFC has been able to operate its both Melamine plants efficiently with a reasonable margin. The margins of Melamine sales have been roped in by GSFC for meeting the expenses of Melamine 3 expansion project and to support its commitment to supply PUC to Domestic Industry. Hence, it is submitted in terms of Article 11.1 of the Agreement of Anti – Dumping that duty shall remain in force as long as and to the extent necessary to counter the act of dumping which is causing injury.
- The major raw material for production of PUC is Urea. There are a number of companies manufacturing Urea in India, but no other player except of GSFC took the challenge of establishing production of the PUC in India. The various challenges which have discouraged other companies to manufacture PUC are Guarded Technology, Complex Operations, Special Alloy Equipment's, High Capital Intensive project, dumping by Low Gas Price Countries like China & Gulf Countries etc. Inspite the difficulty, GSFC has successfully established its operations using the aforesaid technology. Hence, it is extremely important to save the operations of GSFC from shutting down due to express losses that it will suffer in the absence of the anti-dumping duty.
- GSFC is already in the process of expanding its capacity. The decision to establish additional capacity has been pending execution from a very long time. The delay in execution had been caused due the economic factors of the Melamine 3 project and factors operating under International standard capacity plants. However, the efforts of GSFC to establish its increased capacities can be gauged from the fact that it decided to establish a Fertilizer & Petrochemical Complex at Dahej for which it acquired 650 acres of land. However, due to policy constraints under Department of Fertilizer, Government of India, GSFC was unable to bring Ammonia-Urea Project at Dahej. This resulted in failing of the proposed Melamine Project at Dahej.
- As regards to Submissions by Century Plyboards (I) Ltd DI has submitted that the claims of Century that there is no likelihood of dumping and injury is denied as bereft of any merit. The calculations relied upon by Century are self- serving and do not show the factual position of the case in hand. The Authority may rely upon the actual data submitted by the petitioner considering various examinations and not to rely upon the estimations made by Century which is apparently has no nexus to the reality. Century has made a comparison between the cost of sales and net selling price of the Domestic Industry and the landed price of imports. It may be noted that the domestic industry has been able to pass on increase in cost of production to the customers as a result of the current Anti-dumping duty in force. Hence, if the current Anti-dumping duty is removed then the domestic

industry shall face an imminent threat of significant financial losses on account of price suppression/depression effects in as much as at present the subject countries imports are underselling the prices of the domestic industry during the POI.

- As per the marketing and sales dynamics of the Indian Market, the PUC is sold in both ways *i.e.* direct sales and indirect sales through Channel partners. The ratio of which is 30% and 70% each respectively. By this way GSFC is able to sell the product consistently in all market conditions thus overcoming the vagaries of difficult, dull, tumultuous market conditions which includes factors like, heavy flow of imports, indifferent buying behavior of consumers etc. The indirect sales to channel partners takes care of GSFC consistent sales, involving multiple material handling, catering to small/medium customer base, extend credit payment days, risk and cost of the unfixed and unsecured payment terms of consumers. It is not true that the cost of Melamine through distributors is higher than the same offered to direct customers. In this regard, it would be pertinent to mention that M/s Century Plywood has purchased PUC (approximately 26 MT of GSFC Melamine, which barely forms 1% of the total annual requirement of PUC by M/s Century Plywood) and Century was not charged differently. Therefore, it is wrong for M/s Century Plywood to rely on misrepresented data in order to prove its case.
- It has been argued by M/s Century that in case of negative injury margin in the POI and Post POI period concerning subject imports the duties should be discontinued and have cited certain past cases. It is submitted that the submission of Century should not be accepted. This is without prejudice to our claim that the injury margin will still be positive in the POI and any post POI period. However, even a negative injury margin cannot lead to termination of existing duties. Injury margin may reflect the non-continued injury situation of the domestic industry because of existing anti-dumping duties and the requirement under the Rule is likelihood of injury on account of expiry of the measures in force. In a fresh investigation, injury margin is determined for the purpose of quantification of measures as India follows lesser duty rule and no such requirement of quantification exists in the present case as the present investigation is only a sunset review. Thus, negative injury margin per se cannot be a ground to discontinue the present duties and in any case our submissions clearly demonstrates likelihood of dumping and injury in the event of expiry of present duties.
- In the judgment of the Hon'ble High Court of Gujarat in the matter Nirma Ltd Vs UOI the Hon'ble High Court has ruled that injury margin is an irrelevant factor while considering the likelihood aspect and the said judgment is the Rule of the land as of today and based on this judgment alone no duty can be terminated in a review by citing negative injury margin. Thus, the contention of Century needs to be rejected.

F.3 Examination by the Authority

- The Authority notes that the DI has sold 3 grades of Melamine based on quality *i.e.* standard, regular and MS to an extent of 90.48%, 6.5% and 3.02% respectively during POI. The Authority notes that the investigation is on all grades of Melamine and that no separate product control number (PCN's) were made in the original finding or in the other ADD case of imports from China. The NIP, NV and export price has been adopted for all grades on an average basis. Further no producer/exporter has cooperated and hence no data on type of grades being produced and exported have been reported. The Authority therefore has considered the analysis for all grades of Melamine on an average basis.
- As regards issue of sales to traders, the Authority has evaluated 'NSR' on an exfactory basis which is net of discounts/commissions. The proportion of sales to traders by DI about 18% of its total sales and is not of a large proportion as claimed by importers. Further the sales channel in domestic or export is dependent on nature of the product and in the instant case, the sales both in domestic market by Domestic Industry and on imports by importers from subject countries include traders as well. The Authority therefore has considered the weighted average NSR of all grades and sales channel for comparison of price undercutting and underselling adopting the methodology as done in the original case.
- The Authority has computed NIP for POI and post POI by considering normated values of raw material, utility and consumable and best capacity utilization attained during the POI. A return on capital employed as per Authority's consistent practice has been allowed.
- The Authority has evaluated various economic and financial performance parameters of Domestic Industry during POI as under:

G. Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

G.1 Volume Effect

G.1.1 Demand and market share

30. The table below shows the demand of product under consideration during injury period and PoI

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Imports from EU	MT	6,542	9,287	6,817	6,723
Imports from Iran	MT	6,052	5,240	10,074	5,304
Imports from Japan	MT	1,040	2,060	1,280	740
Imports from Indonesia	MT	-	-	-	-
Imports from Subject countries	MT	13,634	16,587	18,171	12,767
Imports from other countries Attracting ADD	MT	22,582	24,262	18,284	23,305
Imports from Other Countries	MT	4,614	9,702	16,196	12,674
Total Imports	MT	40,830	50,551	52,651	48,745
Sales by Domestic Industry	MT	15,378	14,283	15,096	15,341
Demand	MT	56,208	64,834	67,747	64,086
Share in Demand					
Imports from EU	%	11.64	14.32	10.06	10.49
Imports from Iran	%	10.77	8.08	14.87	8.28
Imports from Japan	%	1.85	3.18	1.89	1.16
Imports from Indonesia	%	-	-	-	-
Imports from Subject countries	%	24.26	25.58	26.82	19.92
Imports from other countries	%	40.18	37.42	26.99	36.37
Imports from Other Countries	%	8.21	14.96	23.91	19.78
Total Imports	%	72.64	77.97	77.72	76.06
Sales by Domestic Industry	%	27.36	22.03	22.28	23.94

The demand has been rising consistently over the injury period and PoI though there has been a minuscule decline in PoI which cannot be considered as a case of injury.

G.1.2 Import volumes and share of subject country

31. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”

32. The import volumes for the injury period are as under:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Imports from Subject countries	MT	13,634	16,587	18,171	12,767
Imports from EU	MT	6,542	9,287	6,817	6,723
Imports from Iran	MT	6,052	5,240	10,074	5,304
Imports from Japan	MT	1,040	2,060	1,280	740
Imports from Indonesia	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	40,830	50,551	52,651	48,745
Share of imports in total Imports					
Share of Subject countries	%	33.39	32.81	34.51	26.19
Share of other countries	%	66.61	67.19	65.49	73.81
Subject countries import in relation to					
Indian Production	%	91.39	116.11	115.76	85.76
Consumption	%	24.26	25.58	26.82	19.92

The imports from subject countries have reduced after imposition of ADD and that their share has also come down.

G.2 PRICE EFFECT

G.2.1 Price effect of dumped imports and impact on domestic industry

33. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject country have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject country. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non-injurious price and compared the same with the landed value to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of Annexure III of the Anti-dumping Rules. The position is as follows:

G.2.2 Price Undercutting and Underselling

34. The Authority has made price undercutting and price underselling analysis both with and without anti-dumping duty after evaluating the Landed Value of inputs under the duty free imports for the reasons as mentioned in the foregoing paras.

Particulars	Units	EU	Iran	Japan	Subject Countries
Landed Value	Rs/KG	89.30	99.34	87.99	93.39
Net sales realisation	Rs/KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/KG	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	0 to 5	Minus 5 to minus 10	0 to 5	0 to minus 5

The above data indicates that price undercutting, without taking into account the antidumping duty in force, is negative on a cumulative basis for the subject countries.

G.2.3 Price Underselling

35. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out non-injurious price of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling.

Particulars	Units	EU	Iran	Japan	Subject Countries
Landed Value	Rs/KG	89.30	99.34	87.99	93.39
Non-Injurious Price	Rs/KG	***	***	***	***
Price Underselling/IM	Rs/KG	***	***	***	***
Price Underselling/(IM%)	% Range	0 to minus 5	Minus 10 to minus 15	0 to minus 5	minus 5 to minus 10

From the above table, the Authority notes that during the POI, the price underselling are negative.

Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

36. Performance of the domestic industry with regard to production, sales, capacity and capacity utilization are as follows:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Capacity	MT	15,000	15,000	15,000	15,000
Trend	Index	100	100	100	100
Production	MT	14,918	14,285	15,698	14,886
Trend	Index	100	96	105	100
Capacity Utilisation	%	99.45	95.23	104.65	99.24
Sales Volume	MT	15,378	14,283	15,096	15,341
Trend	Index	100	93	98	100

The production capacity utilization and sales of Domestic Industry has been quite stable and consistent over the injury period and PoI.

Inventories

37. From the information given below, the Authority notes that the inventory position of domestic industry has declined during period of investigation.

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Opening Stock	MT	509	47	48	649
Closing Stock	MT	47	48	649	194
Average Stock	MT	278	48	349	422
Trend	Index	100	17	125	152

The variation in inventory is not wide enough to evidence any stock piling.

Profits, return on investment and cash flow

38. Performance of the domestic industry with regard to profits, return on investment and cash flow over the injury period was as follows:

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
Cost of Sales	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	93.00	96.52	95.98
Selling Price	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	99.02	104.74	101.97
Profit/(Loss)	Rs. Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	357.10	457.30	359.04
Profit/(Loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	331.67	448.87	358.14
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	141.48	188.32	152.55
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	356.02	539.01	400.26

Profitability and RoI have been stable and positive during the injury period and PoI.

Employment, wages and productivity

39. From the information given below, the Authority notes that the employment position of the domestic industry has not deteriorated during period of investigation as compared to base year. Productivity in terms of production per day and production per employee remained within the same range over the period showing no adverse trend.

Particulars	Units	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
No. of Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Index	100	94	98	95
Wages	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Trend	Index	100	129	181	149
Productivity per Employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	107	105
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Index	100	96	105	100

Magnitude of dumping

40. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject countries during POI is positive for EU during POI, however, for Iran it is negative and for Japan while it is positive on the basis of 'CNV' constructed as per Domestic Industry's data, it is negative on secondary sources. Also for post POI, the dumping margins for all three subject countries become negative/de minimis.

Growth

41. The Authority notes that the growth of domestic industry in terms of sales, production, has been stable when compared to the base year.

Ability to raise Capital Investment

42. The domestic industry contended that it has planned capital investment of Rs.7,000 crores, which is for a number of products. This includes substantial capacity expansion for Melamine. The company has argued that it intends to enhance the capacity for Melamine by 40,000 MT. The domestic industry argued that continued dumping of Melamine is adversely impacting the expansion plan of the company with regard to the product. It is noted that continued dumping of the product and financial losses in the product are bound to adversely impact the ability of the domestic industry to raise capital investments. Though the domestic industry is a multi-product company, the adverse impact on the operating performance of the domestic industry on account of this product could affect the ability of the domestic industry to raise capital investment for the subject goods.

43. The Authority notes that Anti-Dumping measures on imports of Melamine from China are in place which holds almost 2/3rd of the global capacity. The Authority notes the submissions by the domestic industry regarding the investments made by them in their newly expanded facility which may get hampered on withdrawal of existing Anti-Dumping measure. The Authority holds that the existing Anti-Dumping measures for 5 years provided a fair playing field to the Domestic Industry which is reflected in its improved performance parameters. The protection for future production plan which is still to come up cannot be addressed in the ongoing SSR wherein the assessment on likelihood of injury to the

existing manufacture base needs to be examined and has been done so. The level playing field for the additional capacity of Domestic Industry whenever it comes up can be considered by the Authority based on the circumstances prevailing at that time and as per the provisions of AD Rules.

Causal Link

44. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

Volume and prices of imports from third countries

45. The Authority notes that during POI, major imports of the subject goods from countries other than the subject country are from China and Qatar. While imports from China are attracting ADD, imports of Qatar have been made largely by GSFC which have been examined.

46. The Authority notes that M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. (GSFC) has though not imported PUC from the Subject Countries during the POI of sunset review, it has undertaken imports of PUC to an extent of 940 MT and 100 MT from Iran during 2013 – 14 and 2014 – 15 respectively and to an extent of 500 MT and 600 MT from Japan during 2013 – 14 and 2014 – 15 respectively. It has also regularly undertaken imports from Qatar a non-subject country to an extent of 1500 MT, 8280 MT and 5379 MT during 2014 - 15, 2015 – 16 and 2016 – 17 (POI) from Qatar respectively. In post POI period of 6 months i.e. 1/4/2017 to 30/9/2017 also it has imported to an extent of 1140 MT from Qatar.

47. The imports by M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. (GSFC) from Qatar have been at an average price less than the imports done by other importers during the injury period and PoI. The import price from Qatar is comparable with import price of Japan but lower than that of EU and Iran. The applicant during the years of injury period consistently undertook imports from Qatar at such prices but did not report/allege injury on account of these comparable import prices from Qatar.

48. The Authority notes that Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd. has submitted that imports made by them from Qatar were to enable them to fulfil orders of their longtime customers and that they merely traded on same with a margin of just 2-2.5% and even made losses at times. The Authority however notes that trading margins of such a Quantum are typical in a trading environment and that this trading share is 40% of GSFC's production. Even though Qatar is not a Subject Country, the imports from Qatar by GSFC is also a trendsetter of prices in the country which the exporters from Subject Countries would no doubt benchmark. Therefore trend of import prices from the Subject countries cannot only be attributed to the pricing policy of the producers/exporters from the Subject Countries but is also expected to be impacted by the import prices from Qatar which were largely by GSFC.

49. The Authority after considering this aspect while examining causality and the threat of Dumping and Injury as alleged by the applicant holds that such circumstances where the injury margin during POI and post POI is negative from subject countries and prices from Qatar are either comparable or lower than subject country prices, threat of injury cannot be attributed to imports from the subject countries.

Contraction of demand and changes in the pattern of consumption

50. The Authority notes that there is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.

Developments in technology

51. The Authority notes that none of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the DI.

Conditions of competition and trade restrictive practices

52. The Authority notes that the subject goods are freely importable and the domestic industry is the sole producer of the subject goods.

Export performance of the domestic industry

53. The export performance of the domestic industry is not relevant since price and profitability only in the domestic has been provided and examined by the Authority for the purpose of assessing injury to the domestic industry.

Performance of other products

54. The claimed likelihood of dumping and injury by the domestic industry is on product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration. The financial information has been provided with regard to product under consideration.

Conclusion on Injury and Causation

55. The Authority holds that the performance parameters of Domestic Industry are stable and no injury due to imports from subject countries seems to exist. The fact that imports from Qatar have been carried out by domestic industry at similar prices, indicate that such import prices are non-injurious. Negative injury margin both during POI and post POI further substantiate this aspect.

F. Other Issues

H.1 Submissions made by the Importers/ users/ other Interested Parties/ other parties

56. Following submissions have been made by the importers/ users/other interested parties/ other parties

- (a) M/s Century Plyboards Pvt. Ltd.
 - The initiation does not mention submissions made by the other interested parties
 - GSFC has claimed its sales policy as confidential. It does not sell directly to end users. The price difference between sales to traders and end users are account of malpractices by GSFC
 - DA has not informed on the exact and precise issues on which it wants to hear the parties. An oral hearing must also be scheduled after issuance of disclosure statement oral hearing may be postponed and refixed.
 - DA has not provided information in response to the RTI query.
- (b) M/s International Trade Remedies & Practices representing M.s Agarwal Chemicals
 - The petitioner has claimed excessive confidentiality. The data may be provided for further response
 - Petitioner has desired fixed duty under continuance of measure. The investigation in fact needs to be terminated.
- (c) M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd.
 - The petitioner is not having proper capacity to cater demand.
 - The petitioner is government oriented company.
 - The petitioner is having monopolistic situations.
- (d) M/s Exim Corp India Private Limited has submitted that GSFC instead of responding to sales enquiry of a user directs its traders to respond.

H.2 Examination by the Authority

57. The Authority notes submissions by various importers/users that excessive confidentiality have been claimed, information sought under RTI by one of the importers/end users has not been provided and that initiation was faulty as the data before Authority was not fair. The Authority holds that initiation is based on various facts as available *prima facie* which require appropriate validation and analysis which in certain cases may require investigation post initiation to arrive at a fair and equitable judgment. As regards information to be made available to all interested parties the Authority adopted its established practice of considering claims of confidentiality by any interested party based on reasons and its acceptance by Authority as per relevant AD Rules. The non-confidential versions of submissions are made available through public file to all interested parties who may inspect the same in DGAD. In view of the above

position and the framework of quasi-judicial investigation by Designated Authority as per AD Rules the issue of RTI requires no further response. The reply to RTI is provided by the Designated CPIO as per the prescribed rules under RTI Act, as a separate executive function which was done in this case as well.

58. As regards providing list of issues which DA would prefer to hear in an oral hearing, it is held that all interested parties have the liberty to express their views to DA in the oral hearing on any issue they feel is relevant for DA to hear. This practice has been consistently followed. Any interested party who chooses not to participate in an oral hearing has the option to do so as participation is not mandatory.

Post POI Likelihood analysis

59. Likelihood of Dumping and Injury

S. No.	Particulars	Unit	EU	Iran	Japan
1.	CNV (DI's CoP Data)	\$/Kg	***	***	***
2(a)	ExEP	\$/Kg	1.189	1.233	1.196
2(b)	CIF	\$/Kg	1.339	1.325	1.129
3.DM		\$/Kg	***	***	***
		% range	0 to 5	0 to minus 5	0 to 5
4.	NIP	\$/Kg	***	***	***
5.	IM	\$/Kg	***	***	***
6.	IM	% range	Minus 5 to minus 10	Minus 5 to minus 10	Minus 5 to minus 10

60. Surplus capacity of producers/exporters and attractiveness of Indian market

The Authority notes that domestic industry has claimed market capacity of 450000MT, 20000 MT and 90000 MT in EU, Iran and Japan respectively. The claim of EU's capacity of Melamine matches with the data reported in EU's finding dated 30th June, 2017. The capacity utilization is about 78% as reported in the finding in the year 2015 – 16. As regards Iran and Japan as per World Trade Atlas data highest global exports to an extent of 10000 MT and 49000 MT are evidenced. The fact that injury margin in POI and post POI are negative, and also that dumping margin in POI and post POI are not significant, these does not appear to be a likelihood of trade getting diverted to India. The Authority notes that annual demand of Melamine in the country is about 70000 MT and even with capacity addition of DI the demand supply gap is required to be met by imports. This gap rather than attractiveness is in-fact a necessity of filling in the demand supply gap. The Authority notes that the injury margin which if taken as an indicator of likelihood in post POI is also negative as also is the case during POI.

61. As regards imports from Indonesia the Authority notes that the producers/exporters in Indonesia have closed their operations and imports from Indonesia are nil during the injury period, POI and post POI. Therefore the AD measure on imports from Indonesia is felt to be non-justified and also does not warrant any further continuation.

Post disclosure comments

62. Submissions made by the Domestic Industry

- The Disclosure statement talks about participation and submissions made by one party namely M/s Sandeep Organics Pvt. Ltd. However, the said party did not place any submissions in the public file so far and the petitioner is not aware of any such participation till the receipt of the present Disclosure. At the outset, we deny

all the claims of the said party also as bereft of any merit and the rejoinders provided earlier *inter alia* deals with submission by such importer also.

- The NIP determined is grossly underrepresented and is unduly low which requires re-examination. The Authority has shared the details of the NIP proposed for Melamine produced by the DI along with the Disclosure statement. After cross checking the same along with our records, it is felt that the NIP proposed is unduly low and are determined by not appreciating the relevant facts of cost of the product produced by the Company and also some methodologies adopted which is understood to be inconsistent with the past practice of the Authority itself. We could observe the following discrepancies in the calculation and humbly request the Authority to take notice of the same for the purpose of Final Finding.
- The working capital calculated for melamine as per the NIP calculation shared with us is Rs. *** lakhs. As per our calculation, which is in our understanding, is consistent with the methodology adopted by the DGAD to calculate working capital as a consistent practice, the figure works out to Rs. *** Lakhs for which detailed calculation is enclosed. It is submitted that undue disallowances of figures has caused very low NIP which is not justified and would cause serious damages to our legitimate interests. We request the Authority to relook into the same.
- We have serious concerns on the treatment of Ammonia which is generated as a by-product while producing Melamine. It was explained to the DGAD team during the on the spot verification that the Ammonia which comes out as a by-product while producing Melamine goes back to the Ammonia plant. The same cannot be used in industrial product as the same has very high inert gas content ***%.
- Since the Ammonia generated as a by-product at the time of production of Melamine which cannot be used in Melamine plant due to the above said purity issue, the Authority should not treat the same at the same cost/price of Ammonia which is used for Melamine. This has led to determination of unduly lower cost of Melamine produced by the Company. The above position of Ammonia generated as by-product needs to be properly accorded and treating the by- product ammonia at par with the other ammonia is incorrect technically also.
- We request the Authority to re-examine the treatment of Ammonia generated as a by-product while determining the cost and also NIP for Melamine produced by the Company. We shall be grateful to the Authority for ensuring no injustice is done to GSFC in the determination of NIP so that a fair outcome is ensured in the final finding.
- The facts as disclosed clearly demonstrate that the expiry of the present anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- Rule 23 of AD Rules provides for an examination whether the expiry of the present anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The Rule, thus, requires pre-empting any likely situation of dumping and injury as a result of such expiry wherein it also presumes that the situation of dumping and injury must have mitigated as a result of the duties that have been in force. Thus, even merest chance of likelihood should lead to the continuation of duties and the following facts in the present case shows why is it essential to continue the existing duties in the present case;
- Performance of the domestic industry improved as a result of duties in force against dumped imports of subject goods from subject countries. However, the DI is still vulnerable to injurious effect of such imports from subject countries, except Indonesia. Such imports have also reached the Indian market at a price which can negatively influence the performance of the DI in the absence of existing duties which is evident from the positive price undercutting in case of imports from subject countries. The argument that such imports were necessitated due to demand supply gap hold no good legal or factual ground as the need and purpose of the scheme is to ensure fair play between domestic production and imports with the given condition of the DI and meeting the entire Indian demand cannot be a prerequisite for fair play in the market from a DI perspective.
- The dumped imports have been looming around in the Indian market from subject countries and what prevented their free flow are the duties in force. Expiry of present duty shall provide a re-entry point for such dumped imports at an aggravated level.
- The Disclosure statement shows that Dumping Margin (NV based on Indian cost) has been positive in case of imports from EU and Japan and the same has been positive in case of EU based on NV on secondary basis. This clearly shows dumping continued from EU in an aggressive manner even after duties and there have been mitigating effects of duties on imports from Japan, Indonesia and Iran. In such a scenario, likelihood of dumping is imminent in the event of present duties as envisaged in the Rule.
- Even the dumping margin determined in the post POI period shows positive dumping margin in case of EU and Japan. This fact further establishes the fact that there are not any factual grounds to say that dumping will not recur in case of expiry of present duties. Dumping continued and continues, thus, duties are essential to counteract the same.
- The Disclosure statement shows positive injury margin in case of import from EU in the POI and negative in case of other subject countries. The injury margin in case of all the subject countries is provided as negative in the post POI period. It is our submission that such negative margins needs to be re-examined as we have submitted herein above that the NIP determined is grossly unrepresentative of the facts for determination of NIP

which requires appreciation. Without prejudice, it is our submission that negative injury margin cannot be seen as a parameter to determine likelihood of injury for the reason that AD duties in force have led to improvement in performance of the DI and such mitigating effects of duties on injury caused is also supposed to be reflected in the injury margin. The duties have helped the DI to operate moderately and efficiently and the same would be reflected in the injury margin position. But the fact remain such negative injury margin is the result of the duties in force and any expiry of the said duties will lead the situation once again to that of overall injury and positive injury margin.

- The facts of potential exports from subject countries especially EU clearly shows that there have not been any shift in the way in which exports were made to India and the users are still very much inclined to import the material at dumped prices from such sources and source like EU have significant unutilised capacities to offer Melamine at dumped and even more harmful prices.
- It is also needs to be noted that none of the exporters have come before the Authority have not permitted it to conducted detailed examinations of their exports to third countries etc. The balance of convenience in such a case should not be to rule out any likelihood but it should be used against such parties who chose not to participate.
- It has been observed by the Authority that level playing field for the additional capacity of Domestic Industry whenever it comes up can be considered by the Authority based on the circumstances prevailing at that time and as per the provisions of AD Rules. We pray for a reconsideration of this view. Large investments to increase the capacity are already made by the DI and production in the new capacity shall commence in a few months from now. It is not a matter the DI is seeking protection for a future investment but it's concern is clearly about investments already made and such investment decisions were based on an anticipation that the fair play in the market shall continue and we believe that the fair play shall disappear in the absence of present duties. The viability of the project being completed is dependent on fair price in the market for Melamine and achieving such prices is not feasible if large exporting countries like EU, Japan, Iran etc are left without any duties. It is significant to mention in here that the Exports from Iran during the year 2015 and 2016 to India of quantity 9140 MT and 5516 MT respectively was at an average price of USD 1.35/kg. Higher price to India are apparently on account of existing duties in force and a decline in such dumped prices to new levels is so imminent. Decline in export price Iran in the event of AD duty is, thus, imminent. There is a possibility that the exporters will sharply reduce their prices to retain the market once the new capacity in India goes operational and such imports even for a shorter period can cause irreparable damages to the DI. The AD rule as such empowers this Authority to take note of potential injury situation and it does not mandate the Authority to first let the harm happen and later approach it for solution. We pray that the DI has already made the investments needs proper appreciation and we request the Authority to reconsider its view on the aspect of capacity additions.
- It is has been observed by the Authority that trend of import prices from the subject countries cannot only be attributed to the pricing policy of the producers/exporters from the subject countries but is also expected to be impacted by the import prices from Qatar which were largely by GSFC, it is our submission that the observation of the Authority requires reconsideration in view of the fact that such observation is not complete in the context of likelihood examination. The focus of GSFC is always to produce the goods in its plant and it has no interest to import and sell the subject goods for nominal or no profits. The imports from Qatar had its basis in the demand supply gap and company did it to retain in its customer basis especially at a juncture where the new plant is almost ready to go live. Once the production starts in the new capacity, the imports from Qatar would be nil by GSFC. The price of imports made during the POI from Qatar did not impact the performance of the DI as can be seen from the injury data and the likely impact of such imports by GSFC itself is also nil because no such imports will be undertaken by GSFC after commencement of production in the new line. Thus, what is going to be the basis of pricing policy of the producers/exporters from the subject countries is not the import by GSFC but certainly capacity additions by GSFC which alone establishes likelihood of dumping and injury in the present case. Exporters will have to reduce their prices to stop GSFC from selling the Melamine produced from its new plant on top of the current capacity and such reduction in prices shall lead to further dumping and injury.
- It appears that the Authority has proposed to hold that the performance parameters of Domestic Industry are stable and no injury due to imports from subject countries seems to exist and the fact that imports from Qatar have been carried out by domestic industry at similar prices, indicate that such import prices are non-injurious and negative injury margin both during POI and post POI further substantiate this aspect.
- We request the Authority not to confirm this proposed view considering the submissions in these comments. The facts of imports from Qatar are once again reiterated and facts of imports from Qatar need to be seen in such back drops. Exporters are bench marking their price based on the duty in force and any removal of duty will lead to decline in price from subject countries. Imports from Qatar by GSFC did not influence the price since such imports did not create any pricing pressure on GSFC. But prices offered by exporters from subject countries are driven by the duties in force and such prices did not adversely impact the performance of DI for

the reason that AD duties are in force. Also, view on injury margin needs to be readdressed in view of the factual inadequacies in the NIP determined. Also, there are duties on China PR and EU has also imposed ADD on imports of Melamine into EU from China PR. Any expiry of present duty shall only lead to increased exports from EU as they would try to take over the market of China PR as well in addition to the new capacities coming into production in India. Thus, imports from Qatar is not any determining factor but the exports from EU are directly linked to existence or expiry of present duties and in the case of expiry, the market will be once again captured by dumped imports from EU which will destabilise the position of DI in very short time.

- It is our considered submission that the domestic industry over the period recovered from the injury caused by the dumped imports from the subject countries and should the measures in force against such sources be allowed to expire, it is, however, likely that the injury would precipitously recur as the DI would be exposed to significant price pressure from such dumped imports. Expiry of duty will lead to even lower prices and potentially increased dumped volumes and there is not even an iota of fact which shows the situation of exports shall remain the same even after expiry of duties and the position of DI would continue to be stable. As a consequence, the situation of the domestic industry would only deteriorate and it cannot be said that the DI would still be in a stable condition.
- Also, the European Commission in the matter of SSR of ADD on imports of Melamine from China PR observed that it is likely that the entry of low-priced Chinese imports to the Union market would immediately drive down the prices if the measures were allowed to lapse.
- Price of Melamine remains a sensitive issue in the Indian market also. There is not even a single factor which suggests exporters from subject countries will not reduce their prices to gain more market share in India in the event of expiry of duties and the DI will still be able to achieve prudent prices even with such low priced imports. Price sensitivity of Melamine is something even acknowledged by an AD Authority like EC and it cannot be concluded that producers/exporters from export oriented subject countries like EU will not reduce their prices to gain more market qua the DI and also other exporting countries given their export orientation and excess capacities. In such scenarios, the DI will be forced to reduce its prices and none of the facts in the Disclosure statement show that the import prices will not go down and DI will not be forced to reduce its prices in the event of unfavourable import prices. It is very obvious that if the DI has to reduce its prices, the injury is just imminent.
- It has also been observed by the Authority that even after expansion of capacity in India, there will be a need for imports. The real fact in this regard is that if the AD duties are allowed to expire, the adverse effects of even such necessitated imports would be so grave that there shall be price adversities in the market. The reason for that is the estimated excess capacity in countries like EU alone is much more than Indian demand and the exporters shall compete to capture even such left out demand position in India which will attract users to such dumped sources and the DI shall not be in a position to maintain its fair prices. Continuation of duty, which is nothing but a fair margin to remove the distorting effects of dumping, shall be beneficial for the DI and also users equally.
- It is submitted that Imposition of ADD has helped the domestic industry to recover from the injurious effects of dumping in the past. Injury parameters have shown recovery, however, there has been significant imports at dumped rates which shows the DI is highly vulnerable to dumping and injury once again;
- The current dumping signifies that it is highly likely that dumping will continue and intensify in the event of expiry of the present anti-dumping duties. Additionally, GSFC has demonstrated that there are significant surplus capacities with the producers of the product concerned in the subject countries and these producers and exporters have considerable export orientation and India remain a potential and attractive market that dumping and injury from such imports is likely in the event of expiry of present ADD on subject countries. The NIP as calculated needs re-examination as the same is grossly underreported and is very low and that it is evident that the expiry of the present anti-dumping duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and we request the Authority to recommend continuation of ADD on dumped imports of the subject goods from subject countries.

Submissions made by the importers and Other Interested Parties/ other Parties

63. M/s Exim Corp represented by M/s Seetharaman Associates

- We welcome the observations that the Authority proposes to hold that the performance parameters of Domestic Industry are stable and no injury due to imports from subject countries seems to exist. The fact that imports from Qatar have been carried out by domestic industry at similar prices, indicate that such import prices are non-injurious. Negative injury margin both during POI and post POI further substantiate this aspect. We request the

DGAD to take these observations to their logical conclusion and terminate the investigation without imposition of any measures.

- Further the above observations call for certain incidental findings from the DGAD on two critical aspects namely: GSFC does not qualify as Domestic Industry; and Initiation of SSR shall not be automatic without regard to the circumstances of each case and urge the authority to give a specific findings in regard to these two issues.
- We also request Designated Authority to give a finding as to how the domestic industry had projected the non-injurious price and that the said price did not meet the legal standards contained in Annexure III to the AD rules.

64. M/s International Trade Remedies & Practices representing M/s Agarwal Chemicals

- It has been mentioned in the disclosure that the provisions of Rule 2(b) requires to examine imports by domestic industry with reference to dumped article thereby limiting such examination to the subject countries only. “It is submitted that the interpretation of Rule 2(b) drawn by the domestic industry is restrictive. Had it been the intention of the law drafters that the imports by the domestic producers are to be examined only for the subject countries, they could have simply used the words ‘subject country (ies)’ in place of the words ‘dumped article’”.
- The examination and use of imports from Qatar forming basis of conclusion in the current investigation clearly establishes the fact that the examination of imports by the domestic industry cannot be restricted to subject countries but are required to be examined for the other countries also. Therefore, in view of the significant imports by the domestic industry of as high as 40% in the POI, the current investigation, in the first place, could not have been initiated had the complete information of imports been provided prior to the initiation as the imports by the domestic industry of such high volumes clearly establishes the fact that the over reliance of the domestic industry is being placed on the imports. Thus, the domestic industry lacks the standing in the current investigation.
- The facts and methodology for the determination of CNV for the subject countries namely EU, Iran and Japan have been mixed up and are not clearly understood. We request the Hon’ble Authority to please appropriately clarify them in the final findings. Without prejudice, it is submitted that we are not able to appreciate the logic and rational of using the cost of the domestic industry for CNV. It may be seen that as per the practice followed for the determination of CNV, the COP of the domestic industry is invariably adjusted for cost of raw materials on the basis of international prices and by adopting the best consumption norms of raw materials. It may also be seen that COP of the domestic industry may not to be used in the current investigation as the cost of the subject goods is available from the EU findings for the year 2015-16 that is more reliable and authentic as compared to the COP of the domestic industry and may be adjusted for raw material prices of Urea for 2016-17, consumption norms of Urea from domestic industry information and profit @ 5%. Therefore, we request the Hon’ble authority for not to utilize the cost information of the domestic industry for the CNV. We also request that CNV for POI 2016-17 based on the domestic prices of European Union for 2015-16 from the EU findings after adjusting them for the difference between the spot prices of Melamine in ICSLOR in 2016-17 over 2015-16 may please also not to be utilized in view of the following:
 - (a) It is not clear as to whether the adjustment to the EU prices for 2015-16 has been made on the basis of difference between ICSLOR price for 2015-16 and 2016-17 considering the spot prices in EU or the difference between the global prices from WTA by EU for 2015-16 and 2016-17. It is submitted that determination of CNV on any of the above two bases is not correct as it is not clear whether the prices reported in the EU findings or ICSLOR are of the traders/producers, whether there is any credit period involved, whether the prices are at ex-factory level or at some other level of trade and whether the same are in the ordinary course of trade or not. Further, as per our information, the prices reported in ICSLOR are for the whole Europe but not for the EU alone. It may be seen that Europe also include several other countries which are not part of the EU. Therefore, in the absence of such vital information for the EU alone, the EU prices as reported in EU findings and adjusted for ICSLOR prices for the POI cannot be considered for the CNV for EU as well as for Iran and Japan. The Hon’ble CESTAT in its order in the case of Dye Stuff Manufacturers Association of India Vs. Govt. of India 2003 (157) E.L.T. 154 (Tri. - Del.) also held that the normal value for a subject country cannot be determined on the basis of incomplete information.

(b) The Spot prices are always as matter of fact higher than the contractual prices and there is no indication that the prices in EU are spot basis. It may be seen that the prices in the domestic market are generally contractual prices.

(c) The best method to compute the CNV for EU is to utilize the cost of Melamine as disclosed in EU findings and duly adjusted for Urea prices for 2016-17. In the original investigation also, the determination of CNV was made on the basis of international prices of Urea, other cost and profit @ 5%. The determination of CNV for Iran and Japan may also be made on the basis of international prices of raw material Urea or from the DGCI&S imports data and other costs from aforesaid EU findings and profit @ 5%. We are not able to appreciate for changing the methodology in the current investigation. The details of the CNV for EU on the above basis and the evidences already submitted as part of our rejoinder submissions.

- CNV compared as per European Commissions cost data and 5% profit comes to 1045\$/MT. CNV for EU as computed by us may also be extended to Iran and Japan.
- We are also not able to appreciate the rational and logic of the contents of the para 20 of the disclosure statement for utilizing the third country prices of the subject countries for CNV for POI and post POI. However, no details of the CNV on the basis of 3rd countries prices for POI and post POI have been disclosed in the current investigation. It may also be seen that before relying upon the 3rd countries prices the same are required to pass the OCT test which again cannot be carried out in the absence of cost of the subject goods. We would, therefore, request for determination of CNV on the basis of EU costs and international raw material prices and profit @ 5%.
- There are also no details on the determination of normal value for Iran and Japan in the disclosure statement. We request the Hon'ble Authority for the disclosure of the same in the final findings. We also request that the normal value for Iran and Japan may also be constructed on the basis of international Urea prices, other costs from EU and profit @ 5%.
- In paras 21-23 of the disclosure statement, the details of the determination of ex-factory export price of European Union, Iran and Japan have been disclosed. It is submitted that the adjustments for ocean freight for EU, overseas insurance proposed to be made from the CIF prices appear to be on the higher side and for credit cost, no adjustment may please be made.
- There appears to be some error in computation of EX-EP which may be rechecked length of post POI may be mentioned.
- In para 28 of the disclosure statement, it has been recorded that the NIP for POI and post POI has been computed. However, the specific period for which NIP for post POI has been determined not disclosed. We request for disclosing the post POI period in the final findings.
- In para 32 of the disclosure statement, it has been recorded that the imports from subject countries have reduced after imposition of ADD and that their share has also come down. It is submitted that the imports from subject countries in the POI have marginally declined as compared to the imports in the base year 2013-14. Therefore, the imports from the subject countries are more or less at the same level in the POI as compared to base year.
- The details of the price underselling for the POI have been provided which are significantly negative for the subject countries. However, the details of the landed value, NIP and price underselling for the Post POI period have not been provided.
- We request the Authority to please also record in the final findings that the domestic industry has placed over reliance on imports to the extent of 40% of their production, therefore any analysis with regard to capacity,

production and capacity utilization is misleading and misnomer under the facts and circumstances of the current investigation.

- With regard to profitability, cash flows and ROI, we request the Authority to please also record in the final findings that there is a significant improvement in these factors over the injury investigation period.
- The Authority may record in the final findings the details on the conclusion of the dumping margin for the POI as well as for the Post POI.
- The Authority has rightly recorded in the disclosure statement that the protection for future production plan which is still to come up cannot be addressed in the ongoing SSR wherein the assessment on likelihood of injury to the existing manufacture base needs to be examined. The level playing field for the additional capacity of Domestic Industry whenever it comes up can be considered by the Authority based on the circumstances prevailing at that time and as per the provisions of AD Rules.
- The disclosure statement, states that the details of the imports volume and prices by GSFC have been provided. Since such a vital and significant information was willfully concealed by the domestic industry and not provided as part of the application prior to the initiation of the current investigation in all fairness, the current investigation could not have been initiated.
- The Authority has rightly recorded in the disclosure statement that even though Qatar is not a Subject Country, the imports from Qatar by GSFC is also a trendsetter of prices in the country which the exporters from Subject Countries would no doubt benchmark. Therefore trend of import prices from the Subject countries cannot only be attributed to the pricing policy of the producers/exporters from the Subject Countries but is also expected to be impacted by the import prices from Qatar which were largely by GSFC.
- In the disclosure statement, it has been recorded that the performance parameters of Domestic Industry are stable and no injury due to imports from subject countries seems to exist. We request the Authority to please also record in the final findings that there is a significant improvement in the performance of the domestic industry over the injury investigation period.
- In the disclosure statement, it has also been recorded that imports from Qatar have been carried out by domestic industry at similar prices, indicate that such import prices are non-injurious and negative injury margin both during POI and post POI further substantiate this aspect. We request the Authority to please record in the final findings as part of conclusion that the prices of imports from Qatar by the domestic industry are significantly lower than the prices from subject countries. It is also submitted that the negative injury margin in the POI and post POI indicates that there is no injury to the domestic industry nor there is any likelihood of injury to the domestic industry in the current investigation.
- It may be seen that as per Section 9A(5) of the Customs Tariff Act and Rule 23(1B) of the Indian Anti-dumping Rules, the anti-dumping duties in sunset review investigation can be extended only when the domestic industry has established that there is a likelihood of recurrence or continuation of both dumping and injury. The duties cannot be extended and the duties are required to be withdrawn in case any of the two conditions i.e. likelihood of dumping or likelihood of injury is not present in a sunset review investigation. It is submitted that there is an absence of likelihood of continuation or recurrence of both dumping and injury in the current investigation. Therefore, the duties may please be revoked in the current investigation.
- In the disclosure statement, the details on the likelihood of dumping margin and injury margin on the basis of Post POI period has been made which may be specified in the Final Finding. It is submitted that as stated above the CNV for the subject countries for the post POI may also please not to be determined on the basis of the COP of the domestic industry and CNV may please be determined on the basis of the raw material prices of Urea, the other cost based from the EU findings and profit margin at the rate of 5%. It may be seen that the normal value in the original investigation was also constructed on the basis of the international prices of Urea. We, therefore, request for determining CNV on the similar basis in the current investigation for post POI as well. It will

indicate that there is negative dumping margin and there is no likelihood of dumping in case of withdrawal of duties. Even on the basis of the details disclosed, it appears that the dumping margin is not significant and negative. It also indicates that there is no likelihood of dumping in case of withdrawal of duties.

- The details of the CIF prices and the landed values for the subject countries EU, Iran and Japan for post POI have not been disclosed. We request for their disclosure in the final findings as has been disclosed for the POI. We request the Authority to record in the final findings that since the injury margin for each of the subject countries is significantly negative there is no likelihood of injury to the domestic industry in the current investigation in case of withdrawal of duties.
- The prices by the subject countries of the subject goods in other markets are higher than the Indian market, there is no likelihood of getting the same directed to Indian market and there is no likelihood of injury to domestic industry after withdrawal of duties.
- We request the Authority for the termination of the current investigation and recommend for withdrawal of duties.

65. M/s Century Plyboard (I) Ltd.

- The observation by Designated Authority with regard to imports made by the Domestic industry; in para 13 of Disclosure Statement and on injury in para 48 have been mentioned.
- Respondent interested party had made submissions with analysis that the injury margin in POI as well as third country is negative. The Designated Authority in para 60 of Disclosure statement has noted regarding the injury margins being negative in POI and post POI.
- The observation of Authority in para 61 of Disclosure have been mentioned
- Further submissions are as under:
 - a. There is no justification for continuation of anti-dumping duty for the reason that there is insufficient evidence that there is likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of withdrawal of anti-dumping duty.
 - b. The landed price of imports from subject countries is significantly higher than the fair price that can be expected by GSFC. Thus, the injury margin in the current period in respect of each of the subject countries is negative.
 - c. There are no imports of Melamine from Indonesia over the entire injury period. Further, the petition does not contain any evidence of likelihood of recurrence of injury from imports from Indonesia
 - d. Comparison of landed price of imports from subject countries with the selling price of the domestic industry and the NIP of the domestic industry clearly shows that the selling price of the domestic industry was consistently and significantly above landed price of imports, cost of production and the NIP of domestic industry.
 - e. While the demand assessed by GSFC is in the region of 64,086 MT, the capacity with GSFC is only 15,000 MT and no efforts have been made by GSFC in expanding the capacities. Despite assurances, GSFC is making no efforts in increasing its capacity to fill in the demand supply gap. The Authority has considered the argument of the domestic industry of capacity expansion and have held in the Disclosure Statement that proposed expansions cannot be a concern in the ongoing anti dumping investigation. It is submitted that even when GSFC is making public statements in the market for the past, about a decade, for expansion of capacities, the fact has remained that the company has not expanded its capacity till date.
 - f. Import price from Qatar is in fact lower than import price from subject countries. If import price of subject countries are higher than import price from Qatar, and if a significant proportion of these imports are by GSFC,

imports from subject countries can also not cause injury to domestic industry, as has also been held by the Authority.

- g. Imports have declined in absolute as well as relative terms. There is negative price undercutting without adding anti-dumping duty in landed price from subject countries during POI and as well as Post POI. It shows no price effect of the imports on the domestic industry. Production, sales and utilization are at optimum levels. Profits, cash flow and ROI has increased significantly over the injury period. Thus there is no continued injury to the domestic industry.
- h. The authority has recommended withdrawal of anti-dumping duty on the grounds that injury margin in POI in respect of imports from subject countries is negative in cases such as White Cement, Zinc Oxide from China, Acetone from Japan and Thailand, Phenol from Japan and Thailand and Caustic Soda from Chinese Taipei.
- i. GSFC admitted that there is no import of melamine from Indonesia. In fact, GSFC was informed by some unknown person, whose authority is also not known, that the plant in Indonesia might be idle. Yet, GSFC has claimed likelihood of injury without showing what are exports from Indonesia to rest of the world and despite the fact that Melamine has dedicated customs classification. Authority has rightfully concluded that the producers/ exporters in Indonesia have closed their operations thus there is no likelihood of dumping and injury from Indonesia.
- j. Authority has observed exports from Iran and Japan to an extent of 10000 MT and 49000 MT. However, what is pertinent to note here is also the price at which these goods have been exported. We had earlier placed on record submissions and data establishing that there is negative injury margin in terms of third country exports by EU, Iran and Japan. Global trade is not barred at fair price is not condemned. Thus, in the present situation injury margin in POI, post POI and third country exports is all negative warranting cessation of anti dumping duties.
- k. Further, it is also noted from the Disclosure Statement that the domestic industry have claimed that capacity in EU, Iran and Japan is 450000MT, 20000 MT and 90000 MT respectively. The melamine review findings referred in the Disclosure Statement for the capacity in EU also states as follows:

Despite this significant market share, imports from third countries did not have an injurious effect on the Union industry as it can be seen from the development of the injury indicators as explained below. The reason is that even though their average price level was somewhat below the MIP (in the range of 1 000 EUR/tonne throughout the period considered) (2) it was never as low as the Chinese prices observed during the original investigation or the current Chinese export prices to the rest of the world (around 855 EUR/tonne adjusted to CIF Union frontier). Even more importantly, all these sources have rather limited production capacity (mostly in the range of 50 000 tonnes to 60 000 tonnes annually) (3) which means that they do not have the same destabilising impact on the supply/demand balance of the melamine market as the PRC was able to exert in the original investigation

- Further, as noted in the past review finding of the Authority such as Aniline, had held that the fact of mere availability of surplus capacity does not in itself sufficient to conclude a finding that the dumping from a subject country would recur or continue and cause injury to the domestic industry in case of withdrawal of duties.
- It is submitted that the domestic industry is not suffering any material injury, performance of the domestic has improved significantly, there is no evidence of likelihood of dumping and injury and further petitioner itself is importing significant volumes from Qatar at a price comparable or even lower than subject countries and not feeling injured from these prices. Such being the case, petitioner is unlikely to suffer injury from the present subject countries. Therefore there is no justification for continuation of anti-dumping duties and the present measures should be allowed to cease.

Examination by the Authority

The Authority has examined submissions made by various interested parties in response to the disclosure as under:

66. The Authority notes various submissions regarding not holding M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited as Domestic Industry as per rule 2 (b) of AD Rules on account of imports made by it from Qatar. The Authority holds that the instant case is of Sunset Review and despite substantial imports of PUC from Qatar, GSFC has not discontinued production of PUC post imposition of ADD measure rather it is in the process of enhancing capacity of the same in near future. Further it is the only producer of Melamine in the country. The anti-dumping duty was levied in the original investigation to ensure a level playing field for M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited who was identified as a Domestic Industry at that point of time as per Rule 2 (b) of AD Rules. Post levy of ADD, M/s Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited undertook imports from Qatar a non-subject country in significant volume. The Authority holds that while Rule 2 (b) requires evaluation of applicant's domestic industry's standing considering import of dumped article and relationship with exporters/importers, the issue of any imports or relationship with other sources not claimed/identified to be dumped would require appropriate examination on a different trajectory of causality to ensure that genuine causes of injury to Domestic Industry are identified fairly. Therefore the issues of GSFC's standing as Domestic Industry are misplaced and Authority holds that on account of non-importation of PUC from subject countries during POI, GSFC meets the requirements of Rule 2 (b), it is reiterated that significant imports by GSFC from Qatar have been appropriately examined under injury to domestic industry and causality of imports from subject countries on injury to domestic industry.

67. The Authority notes that various interested parties have questioned the methodology of computation of CNV, for 3 Subject Countries EU, Iran and Japan during POI and post POI. M/s International Trade Remedies & Practices representing Agarwal Chemicals have stated that CNV on Domestic Industry's Cost of Production, secondary sources like ICSLOR and World Trade Atlas (3rd country prices), domestic prices reported in European Union findings are all not appropriate and that only Cost of Production reported in European Union with 5% profit or international raw material prices of urea be adopted. Further it has been mentioned that ordinary course of trade test needs to be applied when 3rd country prices are adopted for CNV. Adjustments may be involved in such a methodology.

68. In this regard, the Authority notes that M/s Agarwal Chemicals have not provided any evidence of adjustments. Further M/s Agarwal Chemicals as an Interested Party at a belated stage requested to participate in oral hearing and while many submissions have been made by them, no evidence has been provided by them to substantiate any adjustment being advocated by them on different aspects. Further when none of the producers/exporters have participated, the Authority as per Rule 6 (8) and WTO provisions has appropriately referenced best available information and has adopted appropriate methodology for computation of normal value. In case of EU, the availability of EU's finding provides a credible document for referencing. The secondary sources like ICSLOR and World Trade Atlas have been adopted by Authority in past as source of reasonably credible data for purpose of validation depending in specific cases where such data is reasonably available. The Authority has constructed CNV based on Domestic Industry data adopting its consistent methodology as done in such cases and also at the same time noted existence of other data in EU's finding, ICSLOR, World Trade Atlas data which corroborates the CNV computed by Authority for POI and post POI i.e. 1/4/2017 to 30/9/2017. The post POI considered in disclosure and the final findings is 6 months period as consistently adopted by the Authority in SSR cases. The submission that cost reported in EU's finding be adopted and only 5% profit be added is not appropriate since as per provisions of Annexure 1 of AD Rules and WTO Article 2.2.2, the normal profits are referenced for normal value and not 5%. In the instant case the EC's findings have published the prevailing domestic prices which includes actual profits. Also ordinary course of trade test can be applied on a producer's/exporter's specific cost and price data and not on an average basis, collectively for all non-cooperating producers/exporters. The Authority confirms that the methodology adopted for POI and post POI is appropriate.

69. As regards certain errors reported in Exep and request to disclose CIF prices of post POI period i.e. 1/4/2017 to 30/9/2017 as well, slight correction in Exep have been appropriately done in foregoing paras, which do not lead to any significant change in the dumping margin as reported in the disclosure statement. The post POI CIF import prices have also been stated in para 59 under post POI examination. As regards computation of 'CNV' in post POI from secondary sources as well, the Authority holds that the evaluation of critical parameters of Dumping and Injury in POI and thereafter non-injurious import prices from subject countries renders further computation of CNV on other secondary sources trivial.

70. As regards recomputing NIP especially by re-examination of working capital and pricing of by product melamine in the production process, as submitted by Domestic Industry, the Authority noting the provision of para (Viii) of annexure III

holds that M/s GSFC is a multi-product/location company and has two business segments namely fertilizers products and Industrial products. Since no working capital details are available with respect to Melamine the notional calculation of working capital has been done as per Audited annual accounts of the company for the year 2016-17. The net current asset as per Audited annual accounts of the company for the year 2016-17 has been worked out in the percentage ratio of sales revenue of Melamine to the total sales revenue of GSFC notionally as per practice followed in DGAD. The calculation of working capital provided by DI seems to be based on certain assumption which are neither supported and are not clear.

71. As regards by product in cause on ammonia, the company consumed Natural Gas as raw material and by routing through various processes like Synthesis Gas - Ammonia – Sulphuric Acid – Urea produced Melamine in their two plants in Baroda Unit. The NG requirement for IP products are based on Natural Gas purchased at market price which is non-subsidized and therefore valuation of Ammonia recovered from Melamine was valued at the charging rate of Ammonia.
72. The Natural Gas price are based on end use. Natural Gas rates for fertilizer use are on Administered Price Mechanism (APM) and for industrial product as per market rate. The average Natural Gas rates were Rs. *** for fertilizer use and Rs. *** per unit for industrial use during 2016-2017 as per data of GSFC and the corresponding Ammonia rate for fertilizer products were Rs. *** /- MT and for Industrial product Rs. *** /-MT as per Cost Audit Report of the Company. The pricing of Ammonia is uniform and there in no grades in the Books of account of the company. The accounts do not show any costing based on inert gas contents.
73. In any case by product price of Rs. ***/MT is suppressed price of subsidized Ammonia. Domestic Industry has itself admitted that the average CFR price of Ammonia was US \$ *** per ton during 2015-16 as compared to US \$ *** per ton during 2016-17. The price is comparable with the price of by product considered for non-subsidized product in the working of NIP. The Authority therefore confirms the NIP already disclosed on a confidential basis to the Domestic Industry.
74. Further same importers have sought disclosure of NIP to them as well. The Authority holds that as per provisions of confidentiality in AD rules and its consistent practice it has provided the non-confidential methodology on NIP computation to all Interested Parties and no further disclosure is warranted. Claims by certain interested parties regarding non-availability of certain submissions by an importer in public file, the Authority holds that the public file was updated time to time and in any case the generic submissions of all Interested Parties were mentioned in the disclosure for benefit of all interested parties which were essentially of overlapping nature.

Conclusions and Recommendations:

75. Having examined the contention of various interested parties and on the basis of the above facts, circumstances, limitations and analysis, the Authority concludes as under:
 - (i) The economic financial parameters of domestic industry post levy of Anti-Dumping Duty are stable and healthy. There is no injury due to imports from subject countries i.e. EU, Iran and Japan during POI. Imports from Indonesia are Nil during injury period and POI and even post POI. Further there is no injury due to imports from subject countries in post POI.
 - (ii) The imports made by GSFC from Qatar have been significant during injury period, POI and post POI which are either at a price lower than import price from subject countries or comparable. Therefore price depression if any cannot be attributed to exports from the subject countries.
 - (iii) Protection of Anti-Dumping was for existing capacity of GSFC to address material injury on account of dumped imports from subject countries and cannot be extended for protecting additional capacity of product under consideration being set up by GSFC which is yet to come up.

- (iv) The Authority in view of the above does not consider it appropriate to recommend continuance of existing Anti-Dumping Duty on the subject goods from EU, Iran, Indonesia and Japan and hereby terminates this investigation in accordance with Rule 14 (b) of AD Rules.

SUNIL KUMAR, Add.Secy. & Designated Authority